असंशोधित

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

29 जुलाई, 2021

सप्तदश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई, 2021 ई0
पंचदश सत्र 07 श्रावण, 1943(शक)

( कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न )
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । (व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव है जातीय जनगणना को लेकर के, इसमें हमलोग पहले भी चाहते थे कि विधान सभा में एक बार मौका मिल जाता .....

अध्यक्ष : समय पर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चूँकि सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर ..

( व्यवधान )

श्री नितिन नवीन, मंत्री : आज टी0एम0सी0 के सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है, बिहार को गुंडा कहा है और उनके भतीजा यहां नेता विपक्ष बैठे हुए हैं तो उनको बताना चाहिए कि टी0एम0सी0 के लोगों ने बिहार के लोगों को गुंडा कहा है, जिसके सार्गिद बनकर के चुनाव लड़ने गये थे तो उसपर उनका क्या बयान है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये )

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुदामा जी, आपका नाम कितना सुन्दर है और आप काम क्या रहे हैं ? यह उचित नहीं है । अपने स्थान पर पहले जाइए, आपको बोलने देंगे । महबूब साहेब, आप पहले अपने स्थान पर जाइए । आप स्थान पर जाइए, वहीं से आपको बोलने देंगे ।

महबूब जी, अपने स्थान पर जाकर आपको क्या कहना है, बोलिए । आपकी कोई भी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी । अनुमति लेकर स्थान से बोलियेगा वही बात प्रोसिडिंग्स में जायेगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो लिये हुए हैं, वह सब हटाया जाय ।

(इस अवसर पर आसन के आदेश से माननीय सदस्यों के हाथों की तख्ती एवं कागजात को मार्शल द्वारा ले लिया गया )

अध्यक्ष : अब आपलोग चले जाइए अपने स्थान पर । स्थान पर जाकर बोलिए । उचित समय पर बोलियेगा तभी बात आपकी आयेगी । अभी समय उचित नहीं है । ये बोलेंगे, आप अपने स्थान पर जाइए ।

माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रश्नोत्तर-काल के बाद जिसका समय जो तय है, उसी समय कहेंगे ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में बैठ गये )

(व्यवधान)

<u>प्रश्नोत्तर काल</u>

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-08(श्री सुधाकर सिंह,क्षेत्र सं0-203,रामगढ़)</u>

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महादेय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत जिन मौजों को चकबंदी प्रचालन हेतु अधिसूचित किया गया है, उन्हीं मौजों में भू-अंतरण हेतु चकबंदी प्राधिकार से एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होती है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

वर्तमान में बिहार राज्य के पुराने शाहाबाद के 38 अंचलों एवं गोपालगंज जिले के एक अंचल (कटेया) कुल मिलाकर 39 अंचलों में चकबंदी योजना संचालित है । शेष 141 अंचलों को कार्यबल एवं संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण चकबंदी निदेशालय के अधिसूचना संख्या-54/चक0 दिनांक 19.01.2018 द्वारा चकबंदी अधिनियम की धारा 4(क) के तहत अनाधिसूचित करते हुए चकबंदी प्रचालन को अधिसूचना निर्गत की तिथि से रद्द कर दिया गया है । जिन अंचलों को चकबंदी के प्रचालन हेतु अधिसूचित करते हुए चकबंदी योजना का प्रचालन किया जा रहा है, उससे संबंधित मौजों में ही एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होती है, शेष अंचलों में भू-अंतरण हेतु एन0ओ0सी0 लेने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि चक को विखंडित होने से रोका जा सके ।

3. पुराने शहााबाद के 38 अंचलों एवं गोपालगंज जिले के एक अंचल(कटेया) कुल मिलाकर 39 अंचलों में चकबंदी योजना सक्रिय रूप से संचालित है । इन सक्रिय अंचलों के वैसे राजस्व ग्रामों जिनमें चकबंदी योजना के

प्रचालन में और समय लगने की संभावना है, उन राजस्व ग्रामों के रैयतों की कठिनाई को देखते हुए भू-अंतरण हेतु एन0ओ0सी0 लेने की बाध्यता को खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में चकबंदी पदाधिकारी, रामगढ़ (कैमूर) से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अधिसूचना सं0-557/चक0 दिनांक 15.07.2021 द्वारा रामगढ़ अंचल के कुल 81 राजस्व ग्रामों को चकबंदी अधिनियम की धारा 5(ए) के तहत निबंधन के लिए भू-अंतरण की अनुमति से मुक्त किया गया है । वर्तमान में उक्त मौजों में एन0ओ0सी0 की बाध्यता नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब तो संलग्न है । माननीय सदस्य को तो पूरक पूछना चाहिए, सदन का समय बचाने की सबकी जिम्मेवारी है ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जाइए, वह जगह बैठने का नहीं है ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, मेरा पूरक सवाल यह है कि रामगढ़ और नोआंव अंचल में 220 मौजे हैं.....

अध्यक्ष : आपका विरोध प्रकट हो गया, माननीय सदस्य, आपलोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण कर लें । आपलोग जाइए अपने स्थान पर ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, रामगढ़ और नोआंव अंचल में 220 मौजे हैं, केवल 4 मौजे में चकबंदी चल रहा है, 81 मौजे को विमुक्त कर दिया गया, बचे हुए बाकी मौजे को कब विमुक्त किया जायेगा इस नियम के तहत ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, निश्चित रूप से जो आपने कहा, आपका चिन्ता वाजिब है, 81 मौजे को विमुक्त कर दिया गया है और 4 मौजे में काम चल रहा है । जहां काम पूरा कर दिया जायेगा, उसको बहुत जल्द ही विमुक्त कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सुनिए महबूब जी, आज स्वास्थ्य विभाग पर भी डिबेट है, सबको बोलने का मौका मिलेगा, आप पूरी बात को रख सकते हैं । कल उतना सकारात्मक वातावरण में बातचीत हुआ, कुछ तो असर दिखाई पड़ना चाहिए, आपलोग अपने स्थान को ग्रहण करें । आप अपने जगह पर जाइए, जिस विषय को कहना चाहते हैं, सदन नियम के हिसाब से चलता है । संविधान और नियम पर आपकी आस्था और आपने शपथ लिया है, इसलिए आपलोग अपने स्थान को ग्रहण करें । जब स्वास्थ्य विभाग का डिबेट है तो फिर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । अभी आप लोगों का ही प्रश्न है न ।

आप माननीय विधायक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए । जाइए अपने स्थान पर । आपको जानकारी होनी चाहिए, आज 3 घंटे का समय है । अब आप जाइए अपने स्थान पर महबूब जी । खासकर पुराने लोगों की जिम्मेवारी है कि नये लोगों को बता दें कि कौन वक्त किस विषय को रखें । अब जाइए अपने स्थान पर। आप ये प्रशिक्षण नहीं दें, 3 घंटे का डिबेट है, जाइए । अच्छी बात को समझनी चाहिए ।

कोई विषय अपने स्थान से हटकर कहेंगे, कभी वह बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी । महबूब जी, आपलोग वापस अपने स्थान पर जाइए । महबूब जी, पहले आप अपने लोगों को अपने स्थान पर ले जाइए । आपसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर जायं, अपने आसन को ग्रहण करें । सुदामा जी, महबूब जी, अरूण बाबू सबलोग आपलोग अपने स्थान पर जाइए ।

(व्यवधान)

आपलोग वहां से बोलियेगा तो आपकी बात सुनेंगे । पहले आपलोग अपने स्थान पर जाइए । जब तक आपलोग अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

टर्न–2/ज्योति/29.07.2021

श्री सत्यदेव राम : महोदय, गंभीर मामला है । काफीं लोगों की मौत हुई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप प्रश्नोत्तर काल होने देना चाहते हैं कि नहीं ? कोई विषय प्रोसिडिंग्स में नहीं आ रहा है । आप अपने स्थान पर जांय ।

(व्यवधान)

पहले स्थान पर जाईये । स्थान पर जाईयेगा तो डौकुमेंट्स मिलेगा । अपना स्थान ग्रहण करिये ।

(व्यवधान)

3 घंटे की स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा है । स्थान पर जाईये । सच बोलने वाले स्थान तो ग्रहण करिये । आप क्या चाहते हैं कि हम सदन चलायें न , सदन की इच्छा है न कि सदन चले ? सब लोग चाह रहे हैं सदन चलाने के लिए तो आप इतनी संख्या में पूरे सदन को डिस्टर्ब मत करिये । आप जाईये वहॉं । चलिए श्री संजय सरावगी जी ।

<u>अल्प सूचित प्रश्न संख्या–9 (श्री संजय सरावगी क्षे.सं. 83 दरभंगा )</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य में अंचल स्तर पर संधाारित जमाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन कार्य के तहत अबतक कुल 3,78,00,641(तीन करोड़ अठहत्तर लाख छः सौ एकतालीस) जमाबंदी पंजियों को डिजिटाईजेशन कर रैयतों/नागरिकों के लिए आवश्यक कार्यार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया गया है । अवशेष जमिाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन का कार्य वर्तमान में भी चल रहा है ।

जमाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन के कम में हुई टंकण भूल/लिपिकीय त्रुटि सुधार हेतु विभाग द्वारा मई, 2020 में परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-443 (17) रा0, दिनॉक 13-05-2020 द्वारा सभी जिला समाहर्त्ताओं को वांछित निदेश निर्गत एवं संसूचित किया गया है । इस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी पंजियों में निहित अशुद्धियों के सुधार हेतु रैयतों/नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर त्रुटियों का सुधार/परिमार्जन किया जा रहा है । अबतक परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त 10,46,922(दस लाख छियालीस हजार नौ सौ बाईस) आवेदनों में से 8,33,103 (आठ लाख तैतीस हजार एक सौ तीन) आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जो कुल 79.58 % निष्पादन है ।

3-उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री संजय सरावगी : उत्तर संलग्न है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : हॉं, मैं पूरक पूछता हूं अध्यक्ष महोदय । जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उत्तर एकदम इतर है । जब पदाधिकारियों का बनाया हुआ प्रश्न बिना समीक्षा के सदन में भेजा जायेगा तो यही हाल होगा । ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला होगा तो यही हाल होगा । अच्छे पदाधिकारी का डिमोशन और दागी पदाधिकारी का प्रोमोशन तो यही होगा । अब मैं मूल पर आता हूँ । मेरा प्रश्न देखिये खण्ड-2 में अध्यक्ष महोदय, कि ‘‘ जमाबंदी रजिस्टर एवं लगान की पुरानी रसीद में अंकित ब्यौरा के आधार पर कम्प्यूटर में अपडेट नहीं करने से सवा करोड़ जमाबंदी अपवडेट नहीं हो सका है ’’एवं 69.42 लाख जमाबंदी में खाता नंबर नहीं है, 83.48 लाख जमाबंदी में रकवा ही शून्य है इसपर माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं यह तो बतायें इसप्रकार का उत्तर में तो कहीं हैं ही नहीं इसलिए जरा मंत्री जी बतला दें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ..

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय मंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, उनकी बातों में दम है । आप आसन से खाली आश्वस्त कर दीजिये कि 3 घंटे का जो डिबेट होने वाला है विस्तारपूर्वक जो पार्टिया भाग लेने वाली हैं वे अपनी अपनी बात रखेंगी लेकिन महोदय इनका जो तख्ती के अलावा जो डौकुमेंट जो लिया गया है वह कम से कम वापस करा दिया जाय तो ये साथी लोग बैठ जायेंगे और क्वेश्चन आवर चलेगा ।

अध्यक्ष : ये आप नेता प्रतिपक्ष के नाते एश्योर करेंगे न कि वह तख्ती फिर नहीं दिखायेंगे ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : विरोध में तो महोदय,

अध्यक्ष : तख्ती दिखाने का नहीं बात अपनी शालीनता से आप कह रहे हैं वे लोग भी कह देंगे ।

(व्यवधान )

अध्यक्ष : हम फिर प्रशिक्षण लगायेंगे विधायकों का और हमको लगता है कि आपलोगों का भी लगाना पड़ेगा । संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप ही की बात कह रहे हैं ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : 3 घंटे के डिबेट में अपनी बात रखेंगे लेकिन उसके लिए पर्याप्त इनको समय दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य वेल में बैठे हुए हैं और शायद जैसा कि लग रहा है कि कोरोना काल में या कोरोना से जो मृत्यु हुई हैं उनके आंकड़ो के संबंध में इनका कुछ प्रश्न है । महोदय, आसन से आपने ठीक ही कहा और आसन को भी और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सरकार की संवेदनशीलता का एहसास इस माने में होना चाहिए कि आज जो वित्तीय कार्य में अनुपूरक व्यय विवरणी पर जो विशेष वाद विवाद आयोजित है 3 घंटे का उसमें सरकार ने आज के हालात जो प्रदेश के है जो कोविड महामारी के कारण सभी जगह अस्त व्यस्तता है । हमारे शिक्षण संस्थान बंद है । लोगों की मृत्यु हो रही थी । फिर टीकाकरण है और फिर जांच की बात है चूंकि अभी बिहार का इस प्रदेश ही नहीं पूरे मुल्क और पूरी दुनिया का यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है यह तो समझिये और आसन भी जरुर इस बात को एप्रिसियेट करेगा और सराहना करेगा कि सरकार ने यही संवेदशीलता दिखाते हुए आज जो

बहस होनी है तीन घंटे की उसमें स्वास्थ्य विभाग को रखा है वरना सरकार कोई दूसरा विभाग भी निर्धारित कर सकती थी । सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा तीन घंटे का इसीलिए किया है कि जो नेता, प्रतिपक्ष भी कह रहे थे और इसमें सभी सदस्यों को अपने दलों की संख्या के आधार पर समय आवंटित आसन करेगा वह समय उनका है और उस समय में चाहे वह कोविड महामारी के जिस पक्ष का हो मृत्यु के आंकड़े का मामला हो, वैक्सिनिशन का मामला हो या जॉच का मामला हो सभी बात का और अंत में महोदय, इसीलिए चूँकि तीन घंटे पर्याप्त होते हैं गंभीर से गंभीरत्तम विषयों पर विमर्श के लिए इसलिए महोदय, हम भी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं अपने अपने स्थान पर जाईये और अपने समय में सारी बात कहिये ।

अध्यक्ष : अब आप लोग जाईये अपनी जगह पर ।

( इस अवसर पर वेल में बैठे माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गए )

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : डौकुमेंट लंच आवर में मिलेगा ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड क-उत्तर स्वीकारात्मक है । और माननीय सदस्य ....

श्री संजय सरावगी : उत्तर संलग्न है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : थोड़ा सुनने का प्रयास करिये । उत्तर इनका स्वीकारात्मक है । प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों की जमाबंदी डिजिटाईजेशन जो करना है उसमें काफी मात्रा में अभी कमी है । किन्हीं का खाता, किसी का खेसरा किसी का नाम छूट गया है तो मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य जी को कि बिहार सरकार द्वारा 2020 में पोर्टल परिमार्जन का लौंच किया गया जिसके आधार पर 10 लाख 46 हजार 922 आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें से 8 लाख 33 हजार 103 आवेदन को निष्पादन किया गया यानी 79.58 परसेंट इस कार्य को किया गया है लेकिन और भी काम अधिक होना चाहिए । कोरोना काल के कारण स्टाफ की कमी, हमारे पास डाटा ऑपरेटर की कमी थी जिनकी नियुक्ति हो गयी है ।तो निश्चित रुप से बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण्ण चाहिए । मैं जो पूछ रहा हूं कि परिमार्जन की संख्या तो 10 लाख है । मेरा प्रश्न है आप देखिये महोदय, प्रश्न का खंड-2 मै।

अध्यक्ष : जरा समय का ध्यान रखें ।

श्री संजय सरावगी : समय को भटका रहे हैं माननीय मंत्री । मेरा यह कहना है कि सवा करोड़ जमाबंदी अप डेट नहीं हो सका । पेपर कटिंग में भी है कि 79 लाख जमाबंदी में खाता नंबर नहीं है और 83 लाख जमाबंदी में रकवा ही शून्य है और मंत्री जी बोल रहे हैं कि दस लाख परिमार्जन आया और यहाँ त्रुटि डेढ़ करोड़ में है तो परिमार्जन ..

अध्यक्ष : मंत्री जी इसको देखवा लीजियेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि डेढ़ करोड़ जो त्रुटिपूर्ण जमाबंदी अपडेट हुई इसमें साल भर से दो साल से इनपर अभी तक नहीं हुआ है कितने दिनों के अंदर सरकार ..

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री संजय सरावगी : हम यह चाहते हैं कि कितने दिनो के अंदर सरकार इन सभी जमाबंदी को अपडेट करेगी एवं साल दो साल से जो अप डेट नहीं हो रहा है नाम नहीं है, खेसरा नहीं है, रकवा नहीं है उन पदाधिकारियों पर जहाँ इतनी बड़ी संख्यामें लंबित है उन पदाधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है और कबतक करेंगे और कार्रवाई के विषय में बतावें ।

अध्यक्ष : जो इनका पूरक प्रश्न है आप सारी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को अवगत करायेंगे ।

श्री संजय सरावगी : सदन में प्रश्न है और मंत्री जी को तैयारी करके आना चाहिए । इतना महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष : आपको बतायेंगे बुंला करके एक बार मिल कर चलिए । वे जानकारी प्राप्त कर लेंगे तब न बतायेंगे ?

<u>अल्प सूचित प्रश्न संख्या 10(श्री नीतीश मिश्रा, क्षे.सं.-38, झंझारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्य मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3-स्वीकारात्मक है । राज्य के सभी जिला मुख्यालय शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई सुशान के कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। साथ ही, एक लाख से ज्यादा आबादी वाले 27 शहरी क्षेत्रों का मास्टर प्लान भारत सरकार की Amrut योजना के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, जिसमे 22 जिला मुख्यालय शहर शामिल है । इस प्रकार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों शहरों, Amrut योजना के अंतर्गत चयनित शहरों तथ कुछ अन्य

मुख्य शहरों सहित 46 शहरों का Geographical Information System(GIS) आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें पटना महायोजना–2031 अधिसूचित है ।

मास्टर प्लान तैयार करने के क्रम में आयोजना क्षेत्र की घोषणा की जाती है एवं आयोजना प्राधिकार का गठन किया जाता है । वर्तमान में 13 आयोजना क्षेत्र अधिसूचित है एवं 13 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है ।

अध्यक्ष : जवाब संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा था कि सरकार ने बहुत व्यापक पैमाने पर नगर निकायों की संख्या बढ़ायी है यह देखते हुए कि बिहार में शहरीकरण की आबादी वह राष्ट्रीय औसत के काफी पीछे है, उन सभी नगर निकायों के लिए मास्टर प्लान की बात मैंने की थी ताकि जो इज औफ लिविंग है अर्बन एरियाज में उसको सुनिश्चित करें कि प्लान्ड वे मे चाहे ड्रेनेज हो या सिवरेज हो या जो घर बनते हैं भारत सरकार ने औन लाईन बिल्डिंग परमीशन सिस्टम लागू किया है क्या हम इन सभी निकायों में लागू करेंगे हैण्ड होल्डिंग प्रोवाईड करें ताकि ये लगभग आज बिहार में 157 नगर पंचायत हैं क्या ऐसे ऐसे छोटे शहर एक वृहद मास्टर प्लान बनाने की सरकार की कोई मंशा है कि इन नगर निकायों को मदद करें कि वो एक मास्टर प्लान बनायें ताकि अगले 20 वर्ष 50 वर्ष के लिए एक विकसित शहर हमारे प्रदेश में हो सके ।

टर्न–3/पुलकित–अभिनीत/29.07.2021

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे माननीय सदस्य ने आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को रखा है और मैं सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग 46 शहरों का ज्योग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान हमलोग तैयार कर रहे हैं । वर्तमान में 13 जो आयोजना क्षेत्र अधिसूचित हैं और 13 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन भी किया गया है । महोदय, उसका नाम भी है, कहेंगे तो सभी सदस्यों को भिजवा भी दूंगा ।

अध्यक्ष : भिजवा दीजिएगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : हां । महोदय, 13 और शहरों को इसमें शामिल किया गया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है और धीरे–धीरे महोदय, यह जो अभी जिसका ज्योग्राफिकल सर्वे हो रहा है उसको करने के बाद जो शेष शहर हैं उसको

भी शनैः-शनैः, धीरे-धीरे लेंगे । उन सारे शहरों का मास्टर प्लान बनाकर अग्रेतर कार्रवाई जो उसके विकास के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए होगा उसको सुनिश्चित करेंगे ।

हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विस्तार से इन चीजों को रखने का प्रयास किया ।

अध्यक्ष : चलिए ।

अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0- 305 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0- 225, गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

डा0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक । रौना-गुरूआ विधान सभा क्षेत्र के गुरारू प्रखंड के रौना पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत कुल 7 वार्ड यथा वार्ड संख्या-1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 आते हैं । उक्त सभी वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना का क्रियान्वयन कराया गया है। वर्तमान में एकरारनामा के तहत सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर उक्त वार्डों में शत-प्रतिशत 1325 गृह जल संयोजन कर पूर्ण रूप से आच्छादित कर जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

कनौसी-गुरारू प्रखंड के अंतर्गत कनौसी पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत कुल 11 वार्ड यथा वार्ड संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 आते हैं । उक्त सभी वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना का क्रियान्वयन कराया गया है । वर्तमान में एकरारनामा के तहत सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत 1850 गृह जल संयोजन कर उक्त वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित कर जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

कोंची-गुरारू प्रखंड के अंतर्गत कोंची पंचायत में कुल 16 वार्ड हैं जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत कुल 11 वार्ड यथा वार्ड संख्या-1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 आते हैं । उक्त सभी वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना का क्रियान्वयन कराया गया है । वर्तमान में एकरारनामा के तहत सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत 1925 गृह जल संयोजन कर उक्त वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित कर जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

गुड़रू–गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुड़रू पंचायत में कुल 17 वार्ड हैं जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत कुल 11 वार्ड यथा वार्ड संख्या–1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 आते हैं । उक्त सभी वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना का क्रियान्वयन कराया गया है । वर्तमान में एकरारनामा के तहत सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर शत–प्रतिशत 2050 गृह जल संयोजन कर उक्त वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित कर जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

अजमतगंज–गुरूआ विधान सभा क्षेत्र के परैया प्रखंड के अजमतगंज पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत कुल 9 वार्ड यथा वार्ड संख्या–1, 5, 6, 8, 12 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत वर्तमान में एकरारनामा के तहत सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर शत–प्रतिशत 694 गृह जल संयोजन कर उक्त वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित कर टावर से जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है । परैया ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत 50 हजार गैलन क्षमता के जलमिनार द्वारा वार्ड संख्या–2, 3, 4, 10 में शत–प्रतिशत 186 गृह जल संयोजन द्वारा जलापूर्ति की जा रही है ।

उक्त सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया के अंतर्गत पंचायतों में पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर देखा, मुझे लगा था कि कुछ वार्डों में कुछ टोला छूटे हुए हैं, उसकी जांच कराकर पूर्ण कराने की मांग किये थे । महोदय, अभी भी कुछ टोला छूटा हुआ है, उसकी जांच कराकर पूर्ण करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है मैं पंचायतवार लाया हूं... .

अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही दिये हैं, पूरक का जवाब दीजिये ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, जो भी टोला छूटा हुआ है । माननीय सदस्य यदि मुझे सूची देंगे तो मैं उसको एक महीना में ठीक करा दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0– 306 (श्री निरंजन कुमार मेहता, क्षेत्र सं0– 71, बिहारीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : 1– उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, मधेपुरा के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि मधुकरचक पंचायत के वार्ड नं0–1 में श्री

कामेश्वर पाठक के घर से पूरब ग्राम पंचायत की पी0सी0सी0 सड़क बनी हुई है परन्तु पश्चिम में आर0डब्लू0डी0 सड़क से जुड़ी हुई नहीं है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत जमीन रैयती किस्म का है । उक्त जमीन का एक हिस्सेदार श्री वासुकीनाथ पाठक, पिता-स्व0 निशिकान्त पाठक ने पश्चिम की ओर से निकलने वाले रास्ते को निजी हिस्से की बताकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है, जबकि पूरब से निकलने वाले रास्ते का उपयोग अन्य हिस्सेदार द्वारा किया जा रहा है ।

3- प्रश्नगत भूमि की प्रकृति रैयती होने के कारण लोक भूमि की परिधि में नहीं आता है । संबंधित पक्षकारों के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशनुगंज के न्यायालय में विविध वाद सं0-33/2021 के तहत मामला दर्ज कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-147 के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया हुआ है .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं । आपके आदेशानुसार मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, यह उत्तर प्राप्त है और उत्तर जो है खंड - 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है । खंड -2 में जिनके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है, अंचलाधिकारी के द्वारा लिखा गया है कि पूरब से निकलने वाले रास्ते का उपयोग अन्य हिस्सेदार द्वारा किया जा रहा है और खंड- 1 में आर0डब्लू0डी0 सड़क से जुड़ी हुई नहीं है । महोदय, हम तो वहां के स्थानीय विधायक हैं, बराबर टोला में किसी काम से जाते रहते हैं । ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से मेरे द्वारा बनाया हुआ है और वह रास्ता ग्रामीण कार्य से जुड़ा हुआ है । हम केवल माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री महोदय विभाग से इस रिपोर्ट की जांच करा लिया जाय, उच्च पदाधिकारी से या जिला पदाधिकारी से । इस टोला को रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता बहुत बाधित है, लोग निकल नहीं सकते हैं, अस्पताल जाने का होता है, नहीं जा सकते हैं । खुद हम इस चीज को देखें हैं, इसलिए आपके संरक्षण में हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि रास्ता हो चाहे जैसे भी हो...

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी के यहां परिवाद चल रहा है, डिसिजन भी मुझे लगता है कि पक्ष में देना चाहिए, क्योंकि रास्ता बना हुआ है । अगर नहीं होता है तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि यह रास्ता अगर जमीन क्रय

करके भी देना होगा तो माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें और इस टोला को रास्ता मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका दो रोड है । एक रोड सरकारी है और एक रोड लोक भूमि की जमीन नहीं है, प्राईवेट रैयती जमीन है और उस रैयती जमीन पर रोड है, लेकिन इसका विवाद जो माननीय विधायक जी ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय में चल रहा है तो निश्चित रूप से वो आने के बाद जो न्याय होगा उसके अनुसार कार्य कराया जायेगा । अगर वह रैयती भूमि है और लोगों की आवश्यकता है, सरकार की लीज नीति के तहत नियम बना है तो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा उस जमीन को अधिग्रहण करके उस पर रोड बनवाया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सर, एक मिनट सर...

अध्यक्ष : अब हो गया । बहुत सकारात्मक जवाब है । अब मिलकर बात कर लीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0- 307 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र सं0- 106, जीरादेई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है आप पूरक पूछिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, बता दिया जाय, जवाब नहीं ले पाये हैं ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 10/आ0 दिनांक 24.07.2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि सिवान जिलान्तर्गत नवतन (नौतन) प्रखण्ड के पंचायत खलवॉ में कुल 1847 एवं गम्भीरपुर में 1834 राशन कार्डधारी हैं । कोरोना महामारी के दौरान सभी पंचायतों/ग्रामों में जीविका एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डोर-टू-डोर सघन सर्वेक्षण कराते हुए सभी पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है । सितम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक नवतन प्रखण्ड के पंचायत- खलवॉ में 429 एवं पंचायत- गम्भीरपुर में 503 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं । स्थायी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति/परिवार अपना आवेदन पत्र प्रपत्र (क) में प्रखण्ड कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर दाखिल कर सकते हैं । राशन कार्ड निर्गमन एक सतत प्रक्रिया है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, कहा जा रहा है कि राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, लेकिन जब प्रखंड कार्यालयों में आवेदन देने लोग काउंटर पर जाते हैं तो वहां से बी0डी0ओ लौटा देते हैं । ऐसी बहुत सारी घटना कई ब्लॉकों में

हुई है, मारा-पीटी की स्थिति बन जाती है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जांच करवा लिया जाय, बहुत सारे जगहों पर, यह तो केवल दो पंचायत मैं उदाहरण के तौर पर दिया हूं, कई पंचायतों में गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित हैं और जो संख्या बतायी जा रही है वह संख्या पर्याप्त नहीं है, उससे भी ज्यादा संख्या में लोग वंचित हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगी कि इसकी जांच की जायेगी कि पंचायतों में गरीबों का नाम छूटा है कि नहीं ? अगर छूटा है तो उसको बनवाया जायेगा कि नहीं बनवाया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट दिया है कि यह सतत प्रक्रिया है । नए राशन कार्ड निर्गत के लिए जो योग्य लाभार्थी हैं, जो अर्हता रखते हैं वो आर0टी0पी0एस0 काउंटर में जाकर अपना प्रपत्र (क) भरकर देंगे और फिर उसकी जांच कर राशन कार्ड निर्गत किया जाता है । फिर भी मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगी कि आप भी आर0टी0पी0एस0 काउंटर में जो छूटे हुए गरीब हैं उनका अप्लाई करवा दीजिए और मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए तो मैं उसको दिखवा लूंगी और जांच करवाकर जो योग्य व्यक्ति होंगे, जो गरीब होंगे, लाभार्थी होंगे उनको राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय..

अध्यक्ष : चालिए, अब बैठ जाइये । अब इतना सकारात्मक जवाब...

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, एक सकेण्ड महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदन लिया ही नहीं जायेगा, इसका आदेश यहां से दिया जाय, वो लेते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष: आप लिखकर जानकारी दीजिए । मंत्री जी ने बताया ही है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बोलिए चौधरी साहब । आप दोनों बैठ जाइये । बैठ जाइये अभी, आपसे पहले जिन्होंने, कुछ तो सुधारना पड़ेगा, हर चीज में हम बोले ही तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी पड़ेगी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि सिवान जिला में 19 प्रखंड हैं और इन 19 प्रखंड में जो लोग अप्लाई किये हैं राशन कार्ड के लिए, करीब 80 हजार कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ है और जो गरीब हैं, जो लाभुक हैं, जो योग्य हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इतने लंबित और बहुत दिनों से लंबित जो राशनकार्ड अभी प्रशासन के अधीन हैं उसकी

जानकारी आपको है ? अगर जानकारी है तो यथाशीघ्र जिनके राशन कार्ड हैं उनको राशन कार्ड दिलवाने की दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आपने जानकारी ही दी है, उसको दिखवा लेंगे । माननीय मंत्री जी, आप दिखवा लीजिए ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक सतत प्रक्रिया है । आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में कोरोना काल में बड़ी संख्या में गरीब और लाचार लोगों का राशन कार्ड बना है । 32 लाख व्यक्तियों का नाम राशनकार्ड में जोड़ा गया है और उनको लाभ दिया जा रहा है । अभी भी जो, यह निरंतर प्रक्रिया है और लोग प्रपत्र (क) भरकर आर0टी0पी0एस0 काउंटर में देते हैं, उसकी विहित प्रक्रिया है, जांच कराकर और फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है । 32 लाख व्यक्तियों को दिया गया है ।

श्री अवध विहारी चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय...

टर्न-4/हेमन्त-धिरेन्द्र/29.07.2021

क्रमशः

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 32 लाख व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया है, उनको लाभ दिया जा रहा है । यह निरंतर प्रक्रिया है, लोग प्रपत्र को भरकर आर.टी.पी. एस. काऊंटर में देते हैं । उसकी विहित प्रक्रिया है, उसकी जांच कराकर फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं, उनको दिया जाता है । 32 लाख व्यक्तियों को दिया गया है इस कोरोना काल में ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैंने तो कहा..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बोल रही हैं ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : और जहां तक सीवान जिले की बात माननीय सदस्य ने कही है यह तो सिर्फ पौटन प्रखंड का मामला प्रश्न में अंकित है और मैं देखवा लूंगी सीवान जिले का । जो लंबित मामले हैं उनका जल्द-से-जल्द निष्पादन कराकर, आपकी भावना के अनुसार उसको देखवा लूंगी ।

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, यह पूरे बिहार से संबंधित है, सिर्फ सीवान में ही पौटन प्रखंड है । इसलिए मैंने आपके माध्यम से सूचना दी कि बहुत दिनों से राशन कार्ड बन गया है और लंबित है, वितरण नहीं हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो, जो बन गया है, उसको वितरित करवा दें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है कि यह एक सतत प्रक्रिया है..

अध्यक्ष : सीधे पूरक पूछिये, भूमिका बनाइयेगा तो और सदस्य का समय चला जायेगा ।

श्री सत्यदेव राम : बिल्कुल सही है । मेरा एक छोटा सा सवाल है और पूरे बिहार के लिए है कि गरीब हमेशा छूट जा रहा है और जो योग्य नहीं है वही लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं, महोदय । यही एक सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए यह प्रश्न किया गया है. ..

अध्यक्ष : यही पूरक है आपका ?

श्री सत्यदेव राम : गरीबों को जोड़ने के लिए सरकार अधिकारियों पर दबाव डाले, निदेश दे ताकि गरीबों को जोड़ सके ।

अध्यक्ष : राशन कार्ड अमीर का बनता है कि गरीब का ही बनता है । बैठिये, बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : अमीर लोगों का बना है, महोदय मैं चेलेंज के साथ कहता हूं ।

अध्यक्ष : उदाहरण के साथ दीजिए, मौखिक हवा में बात मत करिये । उदाहरण दीजिए, जांच करवा लेंगे माननीय मंत्री । बताइये, कहां का है, कौन से व्यक्ति का है ?

श्री सत्यदेव राम : पूरे सीवान में, बरौनी में चारों तरफ मैं देख रहा हूं..

अध्यक्ष : आप वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी बात मत करिये सदन के अंदर । बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, वरिष्ठ कहकर मेरे सवाल को छोटा न किया जाय । यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे बिहार में गरीबों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा है ।

अध्यक्ष : नाम बताइये, लिखकर दे दीजियेगा, देखवा लेंगे । माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0- 308 (श्री ललन कुमार, क्षेत्र सं0- 154, पीरपैंती)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । पूर्व के प्रस्तावित योजना में स्टैण्ड पोस्ट के प्रावधान को संशोधित कर ''हर घर नल का जल'' किये जाने के कारण योजना में अतिरिक्त 505 कि0मी0 पाईप तथा 47302 अदद् गृह जल संयोजन का प्रावधान होने के कारण अधिक समय लगा है । वर्तमान में योजना अंतर्गत निर्मित कुल 18 अदद् जलमीनार में से 17 अदद् जलमीनार द्वारा जलापूर्ति शुरू की गई है । 01 अदद् जलमीनार भवानीपुर का मामला न्यायालय में रहने के कारण माह जून में पूर्ण किया जा सका है, तथा जलमीनार से अभी जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है । जुलाई माह के अंत तक भवानीपुर जलमीनार द्वारा भी जलापूर्ति

चालू होना संभावित है । वर्तमान में योजना Trial and Run अंतर्गत चालू किया गया है ।

3- सभी जलमीनार द्वारा माह अगस्त से जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : महोदय, पूरक के ही संदर्भ में कहना चाहते हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, हर घर नल का जल, इस योजना के तहत हमारे क्षेत्र में, 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है महोदय और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 18 जल मीनार में से 17 जल मीनार चालू कर दिया गया है जो कि सरासर गलत है महोदय । हम बताना चाहते हैं कि इससे लगभग ढ़ाई लाख लोगों को पानी मिलना था, 50 घरों को पानी जाना था । लेकिन इसकी हकीकत यह है कि आज की डेट में यह रिपोर्ट इतनी गलत है कि एक भी घर में इसकी जलापूर्ति नहीं की जा रही है और यह पूरी अनियमितता की भेंट चढ़ गयी महोदय । हमारा पीरपैंती आर्सेनिक प्रभावित एरिया है वहां लोग इस बीमारी से, दूषित जल पीने से मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है और इन्होंने यह रिपोर्ट दे दी और मुश्किल से चार-पांच मीनार की टेस्टिंग हुई थी हम लोगों ने देखा है जो कि टेस्ट के समय ही फेल कर गया था । हमारा पूरक यह है कि क्या माननीय मंत्री ये जो रिपोर्ट गलत बनाकर जिन अधिकारियों पर हमने इल्जाम लगाया उन्हीं अधिकारी की रिपोर्ट आज सदन पटल पर रख दी गयी । क्या इस रिपोर्ट की अपने स्तर से उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे । अगर ये जांच करवाना चाहते हैं तो कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह स्वीकारात्मक है और 18 जो मेरा जल मीनार था उसमें से 17 को हमने बनाया है । माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है, तो माननीय सदस्य लिखकर दें । यदि वह गलत प्रश्न है तो मैं दोषी पदाधिकारी को 15 दिन के अंदर उसे सस्पेंड करूंगा ।

श्री ललन कुमार : महोदय, नहीं अब इससे बड़ी बात क्या लिखकर दें ।

अध्यक्ष : अब आपकी मांग तो मान ही लिये हैं ।

श्री ललन कुमार : महोदय, आप बार-बार आसन से कहते हैं कि मिल लीजिए मंत्री जी से । इस विषय पर मैं पांच बार मिला हूं और अब इसको लिखकर क्या देना है और महोदय, एक मार्मिक विषय सदन के सामने रखना है । महोदय, हमारे पीरपैंती विधान सभा में सोनू टोला कचरिया गांव है । कोविड काल में हम वहां गये थे,

वहां पर हर घर में अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दूषित जल, आर्सेनिक जल के कारण और उस समय से हम सब चीजों को बता रहे हैं । इसमें मंत्री महोदय स्पष्ट बतायें कि इसकी जाँच करवायेंगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं और नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न दूषित जल वाला नहीं है । उन्होंने सीधे जल मीनार की बात कही है और इतने घरों में पानी नहीं मिला है । तो माननीय सदस्य को मैंने आश्वस्त किया है कि यदि यह असत्य है तो निश्चित रूप से मैं जाँच करवाऊंगा और दोषी पदाधिकारियों पर 15 दिन में कार्रवाई करूँगा, तो फिर मिलने का कहां सवाल है । मैं आपसे मिलने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं स्वत: कार्रवाई करूँगा ।

अध्यक्ष : एक मिनट । माननीय श्री नन्द किशोर यादव जी ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, विषय बहुत गंभीर है और माननीय सदस्य जब सदन के अंदर कहते हैं कि अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो माननीय मंत्री महोदय को इसका विश्वास करना चाहिए और उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि अनियमितता हुई है और दिख भी रहा है महोदय, 14 अगस्त, 2015 को अगर एकरारनामा हुआ और 30 महीने में उस काम को पूरा करना था । इसका अर्थ है कि दो साल की देरी हो गई और दो साल पहले कोई संकट भी नहीं था, जिसमें काम बंद हो सकता था । तो मेरा कहना है कि जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट बनाकर दी है जिसको माननीय मंत्री ने पढ़ा है, उस पर कार्रवाई तो करें ही करें लेकिन यह जो गड़बड़ी हुई है, क्या उसकी जाँच निगरानी से करायेंगे माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी से कराने से क्या होगा, इंजीनियर से कराने से क्या होगा, निगरानी से जाँच करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : महोदय, मैंने प्रश्नकर्ता को स्पष्ट कहा है कि यदि कहीं उसमें कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से जाँच करवाऊंगा और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करूंगा । तो निश्चित रूप से निगरानी क्या, मैं अपने विभाग के लिए सक्षम हूँ, अपने विभाग से कार्य करवा कर लोगों को पानी दूँगा ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, यह कार्य इंजीनियर ने ही किया है । जब विभाग का जवाब आता है, विभाग के उच्चाधिकारी इसको देखते हैं, विभाग के प्रधान सचिव देखते हैं, उनके देखने के बाद ही माननीय मंत्री महोदय के पास आता है और जब उन्होंने ही गलत जवाब दिया है तो वे जाँच क्या करेंगे, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मामला गंभीर है, आप अपने स्तर पर इसकी जाँच करा कर दोनों माननीय सदस्यों को अवगत करायेंगे ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-309 (श्री सत्यदेव राम, क्षेत्र सं0-107, दरौली)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न नगर परिषद, दानापुर निजामत के क्षेत्रांतर्गत नहीं पड़ता है और यह प्रश्न ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री जय प्रकाश यादव ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरा प्रश्न ...

अध्यक्ष : अब इसमें क्या प्रश्न है । पूरक इसमें क्या होगा ?

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, हम जानने के हकदार है न कि जब प्रश्न स्थानांतरित हुआ है, तो मेरा प्रश्न कब सदन में आयेगा ।

अध्यक्ष : अब तो सदन जब आयेगा, तब ही न फिर आयेगा । श्री जय प्रकाश यादव ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, किस आधार पर स्थानांतरित हुआ है ।

अध्यक्ष : आपको माननीय मंत्री जी बताये हैं । आप नहीं थे यहां । माननीय मंत्री जी, फिर से बता दीजिये कि क्यों स्थानांतरित हुआ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न में स्वयं इस बात को अंकित किया है कि पटना जिलांतर्गत दानापुर प्रखंड के नवरत्नपुर टोला और वास्तव में मैंने जाँच कर ली है, व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालक पदाधिकारी से बात भी की है, यह हम विभाग को भेज दिये हैं, फिर विभाग के द्वारा इनको जवाब जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री जय प्रकाश यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-310 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सुबाष सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदनानुसार जिला में धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति सरकार द्वारा निर्धारित समय से की जाती है । राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत धान फसल की अधिप्राप्ति 23 नवम्बर, 2020 से एवं रब्बी विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत गेहूँ फसल की अधिप्राप्ति 20 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ की गई ।

अररिया जिला में इस वर्ष कुल 162 (एक सौ बासठ) समितियों के माध्यम से 7991 (सात हजार नौ सौ इक्यानवे) किसानों से 64293.70 (चौसठ हजार दो सौ तिरानवे दशमलव सत्तर) मे०टन धान की अधिप्राप्ति निर्धारित अवधि अन्तर्गत करते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया ।

अररिया जिला में 109 (एक सौ नौ) समितियों के माध्यम से 1964 (एक हजार नौ सौ चौसठ) किसानों से 10080 (दस हजार अस्सी) मे० टन गेहूँ की अधिप्राप्ति निर्धारित अवधि अन्तर्गत करते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री सहकारिता विभाग का....

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : जी महोदय, उत्तर संलग्न है, हमें उत्तर ऑनलाइन प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, उसमें उत्तर अस्वीकारात्मक है । मेरा प्रश्न है कि किसानों का धान और गेहूँ समय पर खरीद नहीं हुआ, विलंब से पैक्स खरीद करते हैं । उत्तर है कि नवम्बर से ही शुरू हुआ है लेकिन उच्च पदाधिकारियों का ही उत्तर है, महोदय । वास्तविक में धरातल पर धान की जो खरीद होती है वह काफी विलम्ब से होती है और कैश क्रेडिट समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण पैक्स चेयरमैन जो हैं वह धान की खरीदारी समय पर नहीं करते हैं और यही उत्तर है । नवम्बर से देने का है लेकिन लास्ट दिसम्बर से हमारे यहां खरीद हुई है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, पूरक है कि क्या आने वाले समय में भी सही समय पर खरीद होगी ? कैश क्रेडिट सही समय से होगा, घोषणा के अनुकूल कैश क्रेडिट होगा तो निश्चित रूप से.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : सही समय पर खरीद होगी । बाद में तो किसान अपना धान बाजार में बेचते हैं और बाजार से ही धान खरीद कर दिखाया जाता है । धरातल पर यही होता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

टर्न-5/संगीता-सुरज/29.07.21

श्री सुबाष सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत धान फसल अधिप्राप्ति का कार्य 5 दिसंबर, 2020 से और रब्बी विपणन

मौसम 2021-22 अन्तर्गत गेहूँ फसल अधिप्राप्ति का कार्य 29 अप्रील 2021 से प्रारंभ हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-311 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सहकारिता विभाग को स्थांतरित है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, प्रश्न स्थांतरित है तो सहकारिता विभाग को क्यों नहीं गया ?

अध्यक्ष : प्रश्न स्थांतरित हुआ है जवाब जायेगा ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, कब तक ?

अध्यक्ष : जवाब जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-312 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदन प्रखण्ड के सभी कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक SIO के निर्गत खाद्यान्न को उपभोक्ताओं के बीच पॉस मशीन से Biometric authentication के माध्यम से वितरित किया जा चुका है । दरभंगा सदन प्रखंड में जून, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है, जो राज्य औसत के समरूप है ।

| माह | वितरण प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | NFSA | PMGKAY |
| जून, 2020 | 76.84 | 75.16 |
| जुलाई, 2020 | 85.87 | 83.84 |
| अगस्त, 2020 | 84.41 | 82.20 |
| सितम्बर, 2020 | 90.20 | 87.92 |
| अक्टूबर, 2020 | 88.72 | 86.91 |
| नवम्बर, 2020 | 93.61 | 91.43 |
| दिसम्बर, 2020 | 89.79 | ..... |

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर जो प्राप्त हुआ है यह जनसरोकार से, गरीब से जुड़ा हुआ मामला है । महोदय, 12 माह के सामान में से गरीबों को 6 माह का मात्र सामान मिलता है और इसमें ट्रांसपोर्टर, एस0एफ0सी0 और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की बड़ी मिली भगत है और जो जांच प्रतिवेदन

माननीय मंत्री जी ने मंगवाया है उसी पदाधिकारी के जिसके खिलाफ प्रश्न पूछा गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप अपने विभाग से नहीं दूसरे किसी विभाग निगरानी विभाग या आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराये । यह एक प्रखंड का मात्र मामला है नहीं तो सदन की संयुक्त कमेटी से जांच करा दीजिये, कोई जांच करा दीजिये चूंकि जिसके खिलाफ वहीं जांच किया है तो जांच का क्या फलाफल होगा ? महोदय, 6 माह का मात्र गरीबों को सामान मिलता है 12 माह का सामान उठता है । अंतिम 29, 30 तारीख को सामान उठता है और 31 तारीख, 01 तारीख से बांटना शुरू करता है और 10 तारीख तक बांटता है और फिर अगले महीने में भी वही 29, 30 तारीख को सामान उठा होता है तो उठाव और वितरण की पंजी भी इसमें संलग्न नहीं है कि कितने माह का उठाव हुआ है और वितरण कब-कब हुआ है । महोदय, यही मेरी आपत्ति है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहता हूं । सरकार इसको आपूर्ति विभाग से नहीं जांच कराके आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, निगरानी विभाग या सदन की कमेटी से जांच करावे यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप इसको देख लें । आप अपने स्तर से इसको दिखवा लें ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, इसमें देखना क्या है मंत्री जी तो देख ही लिये हैं..

अध्यक्ष : मंत्री जी पहले अपने स्तर से देख लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, अब सदन में प्रश्न आया है महोदय और पूरे राज्य की समस्या है हम तो स्पेस्फिक प्रखंड का उठाये हैं । आपूर्ति विभाग से छोड़कर आप किसी दूसरे विभाग से निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग...

अध्यक्ष : मंत्री जी, वहां के जिलाधिकारी से आप जांच करवा दे । बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : सदन की कमेटी से जांच करवा दे । पूरे राज्य का सवाल है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने...

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कितने दिन में ये जांच हो जायेगा और किन से जांच मंत्री जी करवाना चाहते हैं ये मंत्री जी बता तो दें ।

अध्यक्ष : बता तो दिये कि जिलाधिकारी से करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, ये तो जिलाधिकारी का प्रतिवेदन ही है । यह प्रतिवेदन आप देखिये महोदय जो प्रश्न के जवाब...

अध्यक्ष : अभी आपने कहा कि अधिकारी ने भेजा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप जवाब देखिये । महोदय, मेरे पास जवाब है आप देखें जिलाधिकारी का प्रतिवेदन । देखिये, महोदय इसमें लिख हुआ है कि जिला

पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है जो प्रतिवेदित किया है आप उसी से कह रहे हैं कि जांच करा देंगे । महोदय ये तो उत्तर में है आपके पास उत्तर है आप देखिये । हम कह रहे हैं निगरानी विभाग से । ये पूरे बिहार का मामला है । महोदय, 6 महीने के सामान का कालाबजारी हो जाता है । हम बहुत बताना नहीं चाहते हैं इस सदन में ये आम जनता से, जनसरोकार से सवाल है । महोदय, निगरानी विभाग से नहीं तो सदन की कमेटी से जांच करा दीजिये । पूरे बिहार में यह समस्या है और ये गरीब की समस्या का सवाल है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, तो आयुक्त से जांच करवा दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, आयुक्त से क्यों हमने निगरानी विभाग से कहा आप कह रहे हैं आयुक्त से । आप सदन की कमेटी से...

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, हमने निगरानी विभाग से कहा ये तो गलत परंपरा है...

अध्यक्ष : जितनी जांच है सब निगरानी विभाग से शुरू होगा तो निगरानी विभाग सबकी जांच कर पायेगी । हर विषय पर निगरानी की जांच हो ये उपयुक्त नहीं है । पहले क्रमबद्ध होगा जिलाधिकारी ने भेजा है तो आयुक्त करेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं उनको कहने का मौका देना चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण होता है । अब बायोमैट्रिक सत्यापन के तहत पॉस मशीन के द्वारा यह होता है इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है । महोदय, माहवार जो प्रतिशत में वहां वितरण हुआ है मैंने उत्तर में भिजवा दिया है यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो हम अपने विभाग के किसी अधिकारी से जांच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप सदन चलाइये लेकिन यदि जनसरोकार से सवाल, गरीब का सवाल, कालाबाजारी होते रहे और सरकार मुकदर्शक रहे और महोदय आसन से भी संरक्षण नहीं मिले तो हमारे पास क्या उपाय है ?

अध्यक्ष : आपको तो इतना समय दिया गया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप जिलाधिकारी से बोले हम कह रहे हैं...

अध्यक्ष : अब तो विभागीय पदाधिकारी से कह रहे हैं...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन की कमेटी से जांच कराने में क्या कठिनाई है । एक भी सदन की कमेटी से, गरीब का सवाल है...

तारांकित प्रश्न संख्या-313 (श्री महबूब आलम, क्षेत्र संख्या-65, बलरामपुर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय,

1- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बारसोई (कटिहार) के पत्रांक-221 दिनांक-23.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत बारसोई में वित्तीय वर्ष- 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार 4069 लाभुकों को प्रथम किस्त की भुगतान की गई है ।

2- स्वीकारात्मक । नगर पंचायत बारसोई के द्वारा 2389 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

शेष बचे लाभुकों का भुगतान बैंक के बदल जाने से हुए IFSC Code में बदलाव के कारण लंबित था, जिसे नये बैंक एवं IFSC Code को Update कर दिया गया है एवं भुगतान की प्रक्रिया में है ।

3- शेष बचे 1680 लाभुकों को आगामी अगस्त माह तक नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई कर दी जायेगी ।

(इस अवसर पर राजद के अधिकांश माननीय सदस्य वेल में आ गये )

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को लाया और त्वरित कार्रवाई हो रही है, अगस्त माह में सभी को भुगतान हो जायेगा ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद महोदय, लेकिन इसमें एक संशोधन है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसमें 4 हजार 388 में से 2 हजार 116 को दिया गया । इसमें 2 हजार 272 को देना है । 2 हजार 272 संशोधित कर लिया जाय । मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इसको हम दिखवा लेंगे । जो छूटा हुआ है, कर देंगे ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार तिवारी । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप आसन ग्रहण करें । आप दबाव की व्यवस्था बना करके चाहेंगे कि आपकी मर्जी के हिसाब से सदन चले ऐसा नहीं होगा । आसन पर बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–314 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, क्षेत्र संख्या–200, बक्सर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर के पत्रांक–1627 दिनांक–23.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत सोहनीपट्टी, बक्सर में कचरा के निस्तारण हेतु कुल 02 कम्पोस्ट केन्द्र बनाया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र ही प्रारम्भ करा दिया जायेगा । लैंडफील साईट के लिये नगर परिषद की स्वामित्व की जमीन उपयुक्त नहीं है । पूर्व में नदाँव पंचायत में 05 एकड़ जमीन लैंडफील साईट विकसित करने हतु चयनित किया गया था, जिसका पर्यावरणीय ऑडिट में अनापत्ति प्राप्त नहीं हो सका । पुनः चौसा पंचायत में लगभग 03 एकड़ जमीन चयनित किया गया है, जिसे कचरा निस्तारण हेतु प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संजय कुमार तिवारी : महोदय, उत्तर मिला हुआ था । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्थल का चयन कब तक कर लिया जायेगा चूंकि जो कचरा डंपिंग हो रहा है, वह डेढ़ कैनाल पर हो रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–6/मुकुल–राहुल/29.07.2021

क्रमशः

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : आम लोगों को आने–जाने में भारी कठिनाई होती है । महोदय, चूंकि बरसात के दिनों में दुर्गंध आती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, स्थल का चयन कब तक होगा यह माननीय मंत्री जी हमको बता दें ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम तीन महीने के अंदर उसको कर लेंगे, अधिकतम समय बोले हैं, इधर ही हो जाना चाहिए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : जी, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब सुनिये, सुनिये–सुनिये । थोड़ा सुनने का भी अभ्यास कीजिए, आप हमारी बात सुनियेगा तब न । आप मेरी बात सुनियेगा । ललित जी, आप

मुख्य सचेतक हैं । ललित जी, आप सुनिये । अब आप थोड़ा सा शांत हो जाइये शांत । अब आप पहले शांत होइये, आप शांत होइये न पहले ।

(व्यवधान जारी)

आसन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को संरक्षित करता है । सत्तापक्ष के लोग कभी कहते हैं कि विपक्ष को संरक्षित करते हैं, विपक्ष कहते हैं कि सत्तापक्ष को संरक्षित करते हैं और इसीलिए इस आसन से कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है, अब शांत हो जाइये, अब शांत होइये ।

(व्यवधान जारी)

आप हमारे पास आयेंगे और कहां जायेंगे ? शांत हो जाइये । नेता प्रतिपक्ष, आपके मुख्य सचेतक को तो शांत कीजिए । अब तो शांत हो जाइये । अब एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए । आप मुख्य सचेतक हैं, आप समझते हैं कि सदन नियमावली चलता है, माननीय मंत्री जी ने जब कह दिया कि हम विभाग के वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

सदन की कमेटी में भी कितना विलंब होता है वह तो हम देख रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं कि जो भी सवाल है, महोदय, यह गरीब-गुरबाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इसकी जांच कराना चाहते हैं लेकिन लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि गरीबों की भलाई हो, उनको जो हक मिलता है वह पूरा हो । अगर हमलोग कमेटी से इसकी जांच करवा दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है लोगों को तो न्याय चाहिए और न्याय दिलाने में अगर सरकार इच्छुक है तो भाई संसदीय कमेटी से इसकी जांच करा दे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए । हम आप सब लोग चाहते हैं कि गरीब को उसका अधिकार मिले, हक मिले, इससे जांच करवाओ, उससे करवाओ । महोदय, जो प्रश्नकर्त्ता है उसकी संतुष्टि के लिए तो इतना सवाल होना चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मैं हर तरफ देखूंगा । माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है, आप लोग बैठ जायं, उस जवाब से संतुष्ट नहीं होइयेगा तो पुनः हमलोग विमर्श कर लेंगे, चलिए।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 315 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या-126, महुआ)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : (क) स्वीकारात्मक है ।

(ख) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर का पत्रांक-1473, दिनांक-20.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रामाशीष चौक पर बस स्टैंड की जमीन एन0एच0ए0आई0 की है ।

CWJC No.-8137/2020 मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में एन0एच0ए0आई0 द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए उक्त जमीन को खाली कराया गया है तथा जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक-03, दिनांक- 18.03.2021 के आलोक में बस स्टैंड निर्माण के लिए नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत एन0एच0 के सटे 5 एकड़ भूमि क्रय करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि 515.52000 लाख (पांच करोड़ पंद्रह लाख बावन हजार रू0) मात्र आवंटित की गई है ।

(ग) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, राजधानी के बगल में वैशाली जिला मुख्यालय है, हाजीपुर में आज तक बस स्टैण्ड नहीं है । यहां से बंगाल, यू0पी0 और झारखंड के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा का संचालन प्रतिदिन होता है । सदर थाना के बगल में रेलवे की 15 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई है । क्या सरकार रेलवे से लीज पर 5 एकड़ जमीन लेकर बस स्टैण्ड का निर्माण कराना चाहती है या नहीं ?

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है और विभाग ने राशि भी भेज दी है, जिससे जमीन खरीदने में कोई कठिनाई न हो और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको हम दिखवा लेंगे, अगर रेल मंत्रालय, भारत सरकार सहमत होती है तो हमें क्या दिक्कत है, हम लीज पर भी ले सकते हैं तो उसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे जिससे कि रेल मंत्रालय की जो जमीन, जिसे माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं उसके हम प्रयास करेंगे, नहीं तो अन्यथा जो राशि भेजे हैं उस राशि के आलोक में जो जमीन मिल रही है उस जमीन को हम खरीदेंगे । वैसे माननीय सदस्य को और कोई वैकल्पिक जमीन मिले, क्योंकि यह उनके जिले का मामला है तो उसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, घुड़दौड़ की जमीन है रामाशीष चौक के पास बस स्टैण्ड के बगल में वहां बिहार सरकार की जमीन पर कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उस जमीन का उपयोग बस स्टैण्ड के रूप में किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री सिद्धार्थ सौरभ ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-316, (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, नौबतपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में कुल 204 योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी । विभागीय पत्रांक-1308, दिनांक-13.03.2021 द्वारा ही 63 योजनाओं की दूसरी स्वीकृति दी गई है । प्रथम स्वीकृत योजना में से 124 योजना का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 28 योजना का कार्य प्रगति पर है ।

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण योजनान्तर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सभी कच्ची नाली गलियों का पक्कीकरण किया जाना है । योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा कराया जा रहा है, जिसके लिए पंचम वित्त आयोग मद अन्तर्गत आवंटित राशि में से 20 प्रतिशत राशि इस योजना पर व्यय करने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त राज्य योजना मद से भी राशि आवंटित की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष में पंचम वित्त आयोग मद की राशि आवंटित की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान जारी)

श्री सिद्धार्थ सौरव : नाली-गली पक्कीकरण योजना के तहत नगर पंचायत, नौबतपुर में 23 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें विगत 5 वर्षों में मात्र तीन करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है, तो बाकी 20 करोड़ रुपया की राशि कब तक स्वीकृत की जाएगी । 23 करोड़ की स्वीकृत योजना में पिछले 5 वर्षों में मात्र 3 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए गए हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, विभिन्न नगर निकायों में जो राशि भेजी जाती है उस राशि के विरुद्ध में स्थानीय नगर निकाय को विहित प्रक्रिया के तहत योजनाएं लेनी हैं और अभी चालु वित्तीय वर्ष में पंचम वित्त आयोग मद की राशि के आवंटन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और वह राशि जल्द जा रही है और राशि को जल्द भेज रहे हैं जो पूर्व से पारित प्रस्ताव है उसपर कार्य किया जाएगा ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक है । पंचम वित्त आयोग मद के अन्तर्गत आवंटित राशि का मात्र 20 परसेंट ही मुख्यमंत्री शहरी गली-नाली पक्कीकरण योजना में लग सकती है । इस हिसाब से तो जब 100 करोड़ रुपया पंचम वित्त आयोग मद में भेजा जाएगा तब जाकर 5 वर्षों में पूर्व में पारित योजना पूरी हो पाएगी, इसमें तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे । कम से कम ये जो 5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण योजना स्वीकृत है कम से कम उसकी राशि प्रदान करवाएं

। ऐसे तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे । क्या मंत्री महोदय, बताएंगे कि राशि कब तक उपलब्ध हो पाएगी ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो राशि जाती है उसके विरुद्ध में योजना ली जाती है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए कोई अतिरिक्त राशि भेजने की संभावना बनेगी तो हम भेज देंगे ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-317 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड में धर्मपुर रत्ती (जयरामपुर) एवं पश्चिम (मड़वा) अंतर्गत सीधी जलापूर्ति योजना का प्रावधान है । दोनों योजनाओं में जलमीनार (पानी की टंकी) का प्रावधान नहीं है । वर्तमान में दोनों योजना से सीधी जलापूर्ति चालू है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह टंकी पहले बंद थी, लेकिन आप जब से जवाब मांगे हैं वह टंकी बनकर चालू हो गई और माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने प्रभाव से काम किया, वो दोनों मेरी टंकी चालू हो गई । महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जाइए । अपने स्थान पर जाइए । हो गया अभ्यास, अभ्यास हो गया । बैठ जाइए । आसन न सरकार से, न विपक्ष से प्रभावित होता है । आसन अपने हिसाब से और नियम से काम करता है । अपना स्थान ग्रहण करिए । इतिहास गवाह है इतिहास को भी झांकिए, बैठिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य वेल से अपनी-अपनी सीट पर चले गए)

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र(बैठे-बैठे) : इतनी बेईमानी कीजियेगा तो काम चलेगा ?

अध्यक्ष: एक मिनट बैठिए, पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए । बेईमानी शब्द गलत है वापस लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, ये क्षमा मांगें, ये असंसदीय बात वापस लें । महोदय, क्षमा मांगें ।

टर्न-7/यानपति-अंजली/29.07.2021

...क्रमश:..

अध्यक्ष: आप शब्द को वापस लीजिए, यह परंपरा अब सदन के अंदर नहीं चलेगी । चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हों या सदस्य हों । आप वापस लीजिए । मैं तीन बार कह रहा हूं कि आप यह शब्द वापस लीजिए । बेईमानी शब्द गलत है आसन के प्रति । आप वापस लेंगे इस शब्द को ?

(व्यवधान)

बैठ करके नहीं बोलिए, उठकर के बोलिए ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, कोई बात जब हम खड़े होकर बोलते हैं तो आसन कैसे...

अध्यक्ष: नहीं, यह तो और गलत है । बैठे-बैठे बोलना यह तो और गलत बात है ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, जब कोई बात बैठ के बोल रहे हैं तो वह आसन के संज्ञान में तो नहीं जाता था अब कैसे आ गया महोदय ।

अध्यक्ष: नहीं, नहीं बैठे-बैठे बोलना उचित नहीं है । ललित जी, आप मुख्य सचेतक हैं इस तरह की भाषा नहीं चलेगी और अब सदन में सुन लीजिए कि इस तरह की जो है किन्हीं को अवसर नहीं मिलेगा कि कुछ भी आसन के प्रति बोल दें और अगर जो बोलेंगे तो आसन इसको स्वीकार नहीं करेगा । आप वापस लेंगे ?

श्री भाई वीरेन्द्र (बैठे-बैठे) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको तकलीफ हुई तो हम इस शब्द को वापस लेते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : खड़ा होकर के बोलिए, बैठकर के नहीं । बैठ जाइये सब लोग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आसन के प्रति कोई असम्मानजनक शब्द नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आसन ही हमलोग, सबलोग एक-एक करके बोलते हैं कि आसन ही हमलोगों का संरक्षक है और आसन पर ही आक्षेप और आरोप लग जाएगा फिर हमलोगों का संरक्षण कैसे होगा, इसलिए आसन के प्रति तो कोई ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए और माननीय सदस्य ने बैठे-बैठे कुछ कह दिया है उन्होंने वापस भी ले लिया है इसलिए आसन से अनुरोध करेंगे कि इस बात को, मतलब माफी तो आप ही दे सकते हैं उन्होंने वापस ले लिया है तो इस बात को आगे बढ़ाया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विषय आ गया है खास कर के वरीय लोग क्षमा के योग्य नहीं होते हैं यह ध्यान रखिए, नए लोग आपसे सबक सीखते हैं और नए लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है । आगे से इसको ध्यान में रखिएगा ।

## कार्यस्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 29 जुलाई, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

पहला श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री ललित कुमार यादव, श्री शशिभूषण सिंह, श्री रामानुज सिंह, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री समीर कुमार महासेठ ।

दूसरा, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री महानंद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं श्री संदीप सौरभ ।

तीसरा, श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान और विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 176 (3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने

के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जाएंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, हमको सदन के सामने रखने का मौका मिले महोदय, हमलोगों की मांग पर महोदय, जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है बिहार विधान सभा में लगभग दो बार जो है पारित किया है सर्वदल सम्मति से महोदय और इसबार जो है पिछड़ों और अतिपिछड़ों को केंद्र सरकार बोलती है कि गिनती नहीं करायेगी । कुत्ते-बिल्ली की गिनती होती है, धर्म की गिनती होती है, एस0सी0, एस0टी0 की गिनती होती है लेकिन पिछड़े, अतिपिछड़े और अन्य जातियों की इसमें गिनती छोड़ दी गई है और हमलोग चाहते हैं महोदय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कई लोगों का कार्यस्थगन है सब बोलेंगे तो इनका अगला शून्यकाल समाप्त हो जाएगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, दो मिनट महोदय । सर्वसम्मति से महोदय ये हाउस ने पास किया है अगर हाउस ने पास किया है कोई चीज सर्वसम्मति से, तो यह हमारे मान-सम्मान की भी बात है महोदय ।

अध्यक्षः अब आपका दो मिनट का समय हो गया । मा0 सदस्य महबूब जी, आप बोलिए ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, हमारे तरफ से...

अध्यक्षः एक मिनट में अपनी बात रखिए, बोलिए ।

श्री महबूब आलमः महोदय, कोविड महामारी, हमलोगों ने महोदय और सरकार का बयान है कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है । महोदय, सरकार मौत का झूठा आंकड़ा पेश कर रही है । महोदय, इसलिए हमलोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। महोदय, इसको स्वीकृत करने की कृपा करें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्माः महोदय, पूर्वी एवं उत्तर बिहार में बाढ़ एवं कटाव की परिस्थिति पर विमर्श होना चाहिए । उल्लेखनीय है राज्य के उत्तर एवं पूर्वी बिहार बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है । समय पर बाढ़ सुरक्षा तथा कार्य का सही आकलन नहीं कराये जाने के कारण समुचित काम नहीं हो सका जिसके कारण गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर एवं सारण सहित लगभग 12 जिलों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं फसल की जो क्षति हुई है उसके अतिरिक्त भी । अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए हम चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाय।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री कुंदन कुमार ।

शून्यकाल

श्री कुंदन कुमारः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में आई0ओ0सी0एल0 बरौनी द्वारा 50 बेड का पेडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी, बेगूसराय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्रांक–1509, दिनांक–28 जून, 2021 के संदर्भ में अबतक एन0ओ0सी0 अप्राप्त है ।

अतः पेडियाट्रिक वार्ड की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग से एन0ओ0सी0 की स्वीकृति देने की मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, बरसात में भागलपुर के कहलगांव प्रखंड मुख्यालय से लगमा एवं कैरिया पंचायत के लक्ष्मीपुर–बभिनियां, जंगलगोपाली, जेठियाना, सिमरिया, कैरिया और सौर गांवों का संपर्क पूरी तरह से भंग हो जाता है ।

अतः सरकार से उक्त गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवीः माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलांतर्गत प्रखंड नरकटियागंज के नगर परिषद अंतर्गत चांदनी चौक से अनुमंडल मुख्यालय की तरफ जानेवाली पथ का पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य हो रहा है । जिसमें कनीय अभियंता के द्वारा प्राकलन के विपरीत कार्य कराया जा रहा है ।

मैं उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग करती हूं ।

श्री मोहम्मद कामरानः अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के कौआकोल थाना कांड सं0–272/2021 के द्वारा शराब माफिया के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पत्रकार श्री रौशन कुमार सोनु के घर के पास खड़ी गाड़ी के छत पर शराब रखकर फंसाया गया है । इसी उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः श्रीमती विभा देवी ।

श्री प्रकाश वीरः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे ऑथोराइज किया है ।

अध्यक्षः ठीक है, पढ़िये ।

श्री प्रकाश वीरः अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में माह के दिनांक 22 से 28 तारीख तक जन वितरण प्रणाली के तहत उपयोग किये जाने वाले सर्वर अक्सर फेल रहता है । गरीब एवं दलित लाभुकों के हित में सर्वर की समस्या को शीघ्र दूर करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी–शिवहर–पूर्वी चंपारण को रीगा–शिवहर–ढाका होते हुए मोतिहारी को रेल सेवा से जोड़ने का मामला विगत कई दशकों से केवल सर्वे तक सीमित है ।

मैं राज्य सरकार से जन हित में रीगा-शिवहर-ढाका होते हुए मोतिहारी को रेल लाइन/रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन: अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ सालों से प्राईवेट विद्यालय बंद होने से स्कूल फीस नहीं आई जिससे बिहार के लाखों कर्मियों को वेतन नहीं मिल सका एवं 5 सालों से प्राईवेट शिक्षण संस्थानों को आर0टी0ई0 की राशि का भुगतान नहीं हुआ है । जो किसी भी संबधन प्राप्त संस्थानों का हक है ।

अत: शिक्षक एवं कर्मचारियों को 10,000 एवं 50 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह एवं आर0टी0ई0 की राशि का भुगतान देने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/29-07-21

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां रेलवे रैक पॉइंट के पास ओभर ब्रीज के दोनों तरफ फोर लेन का सर्विस पथ, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण नहीं करने से प्रतिदिन सैंकड़ों ट्रक, मजदूर तथा आम आदमी को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। अत: मैं सरकार से एन0एच-31 पथांश में पथ निर्माण विभाग से फोर लेन सर्विस पथ निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी में अंसारी बुनकरों की संख्या लगभग 20 हजार है । उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरायी हुई है । उनके प्रशिक्षण उत्पाद के विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है । अत: मधुबनी में बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

सुश्री श्रेयसी सिंह: अध्यक्ष महोदय,एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की विगड़ती आर्थिक स्थिति एवं शारीरिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों का नियोजन प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग करती हूँ।

श्रीमती नीतु कुमारी:अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत संवेदक कुमार कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया, नवादा को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा एवं कार्य प्रमंडल, रजौली के द्वारा विगत 4 वर्षों में जो पथों का कार्य कराया गया है उसमें अनियमितता बरती गयी है जिससे पथों की स्थिति जर्जर है। सभी कार्यों की जांच निगरानी विभाग से करवाने की मांग करती हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा,अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलानतर्गत केसरिया विधान-सभा क्षेत्र के पैतीसों पंचायत बाढ़ या जलजमाव से ग्रस्त रहने से फसल की क्षति के साथ-साथ आमलोगों को भारी असुविधा है। उपर्युक्त सभी पंचायतों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर आपदा के अन्तर्गत देय सुविधाओं एवं फसलों की क्षति का मुआवजा अविलम्ब दिया जाय।

श्री आनंद शंकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड नवीनगर के लेम्बोखाप ग्राम के स्व0 सीता कुँवर मध्य विद्यालय, लेम्बोखाप में रसोईया के पद पर कार्यरत थी। इनकी मृत्यु वर्ष 2020 में हो गयी। इनके पुत्र छोटू कुमार को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है । आग्रह है कि उचित मुआवजा जल्द भुगतान करावें ।

श्री मिथिलेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र के पत्रांक 1234 दिनांक 18-6-21 एवं नगर विकास विभाग के पत्रांक 1490 दिनांक 18-6-21 से संबंधित लोकहित के कार्य सरकार शीघ्र पूरा करावे ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलवाराय, बार्ड नं0-8 स्थित मननपुर मंदिर से पटेल टोला होते हुए खगनी खेड़ा तक सड़क जीर्णशीर्ण है जिसका निर्माण जनहित में अति आवश्यक है तथा मननपुर मंदिर के निकट लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल तोरणद्वार का निर्माण करावे।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के रायपुर बजरंग बली चौक से आशाटोल सत्संग भवन होते हुए पहाड़पुर ढाला तक अतिवृष्टि से सड़क खाई में परिणत हो गया है। अतः सड़क चलने लायक बनवाने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भयंकर बरसात बाढ़ के प्रकोप से प्रखंड बाजपट्टी, नानपुर बोखरा के सभी किसानों का सम्पूर्ण फसल नष्ट हो चुका है। अतः जनहित में तीनों प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय,अररिया जिला सहित सीमांचल क्षेत्र में बढ़ते बंगलादेशी घुसपैठियों के चलते नहरों, सड़कों, तालावों सहित गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है जिससे निकट भविष्य में भारी विवाद उत्पन्न हो सकता है । अवैध कब्जा किये गये जमीन को मुक्त कराने की मांग सदन से करता हूँ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर अवस्थित ग्राम खुर्माबाद जो कि कैमूर जिला के सीमा से सटा है, वहां का स्थानीय थाना चेनारी की दूरी 20 कि0मी0 होने के चलते कानून व्यवस्था की समस्या बनी रहती है। अतः ग्राम खुर्माबाद में सहायक थाना बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमारः अध्यक्ष महोदय, मुंगेर शहर के मुख्य मार्ग जो ठेला चालक एवं फुटकर विक्रेता से अतिक्रमित रहता है तथा स्थायी दुकानदार को इससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। अतः सरकार से ठेला चालक एवं फुटकर विक्रेता से अतिक्रमणमुक्त करने की मांग करता हूँ।

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, जिला समस्तीपुर ग्राम आधारपुर के सनोवर खातुन एवं अनवर की भीड़ द्वारा हत्या एवं श्रवण राय की राह चलते हत्या कर दी गयी है जो प्रशासनिक विफलता है। अतः मैं सरकार से मृतक के आश्रितों को 20 लाख रू0 मुआवजा और सरकारी नौकरी एवं बच्चों के मुफ्त पढ़ाई की मांग करता हूँ।

मो0 इजहार असफीः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अन्तर्गत विशनपुर बाजार में 16–9–18 को एन0जी0ओ0 के संस्थापक के कारण एक अप्रिय घटना घटित हुई थी जिसमें लगभग 76 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अतः घटना की जिला प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय जांच हो ताकि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं।

श्री महानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, अरवल नगर परिषद वार्ड–3 एवं वार्ड–13 में नल जल चालू होने से पहले टंकी गिर कर टूट गया। जांच एवं तत्काल चालू करवाने की मांग करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बिहार में इस साल अप्रैल–मई माह में कोविड से मरे करीब दो लाख लोगों के परिजनों को 4–4 लाख रू0 मुआवजा देने और गांव से लेकर जिलास्तर तक के सभी अस्पतालों को मानक के अनुसार सुचारू रूप से चलाने की मांग करता हूँ।

श्री रामवली सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड अन्तर्गत धर्मपुर गांव के बीच से होकर ढक्कन विहीन पक्का नाला गुजरता है। जान माल की क्षति से बचाव के लिए नाला पर ढक्कन निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री अरूण सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 से ही विक्रमंगज प्रखंड के विकलांग पेंशनधारियों का पेंशन बंद है। जांचोपरांत भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

श्री ललित नारायण मंडलः अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार धानुक जाति को बिहार में अनुसूचित जन जाति घोषित करे।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी के जयनगर से खजौली तक भारा कोरहिया होकर जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिगृहित कर शीघ्र निर्माण करावे।

श्री अजय कुमारः अध्यक्ष महोदय, विभूतिपुर विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत वैती नदी के दोनों किनारे सुरौली से केराय पुल तक तटबंध निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री सत्येन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में प्रत्येक वर्ष स्नातक में नामांकन हेतु डेढ़ लाख आवेदन दिये जाते हैं जबकि विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में आवंटित सीटों की संख्या मात्र 35000 है। मैं सरकार से उक्त सभी महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग करता हूँ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन सहित कुछ अन्य विभागों के प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखे जाने हैं। मैं इसे प्राथमिकता से ले रहा हूँ पहले रिपोर्ट रखे जायेंगे, इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे, समय बचेगा तो शेष शून्यकाल लिये जायेंगे अन्यथा शून्यकाल कमिटी को भेज दी जायेगी।

टर्न-9/मधुप/29.07.2021

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-3516, दिनांक-26.04.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017(अधिसूचना संख्या-4412, दिनांक-23.05. 2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदनों ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक

प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मण्डल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्य के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-241(ख) के अधीन इस पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय बिहार विधान सभा में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-85, दिनांक-17.03.2021 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-85, दिनांक-17.03.2021 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, दिनांक-25.11.2020, एस0ओ0-192, 193, 194, 195, 196, दिनांक-11.12.2020, एस0ओ0-197, दिनांक-17.12.2020, एस0ओ0-199, 200, 201, 202, 203, 204, दिनांक-18.12.2020,

एस0ओ0-205, 206, दिनांक-23.12.2020, एस0ओ0-241, 73, दिनांक-30.12.2020, एस0ओ0-74, 75, दिनांक-14.01.2021, एस0ओ0-84, दिनांक-12.03.2021, एस0ओ0-86, दिनांक-26.03.2021, एस0ओ0-99, 100, 101, दिनांक-02.06.2021, एस0ओ0-104, 105, दिनांक-14.06.2021, एस0ओ0-106, दिनांक-16.06.2021, एस0ओ0-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, दिनांक-01.07.2021 एवं एस0ओ0-117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, दिनांक-09.07.2021 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, दिनांक- 25.11.2020, एस0ओ0-192, 193, 194, 195, 196, दिनांक-11.12.2020, एस0ओ0-197, दिनांक-17.12.2020, एस0ओ0-199, 200, 201, 202, 203, 204, दिनांक-18.12.2020, एस0ओ0-205, 206, दिनांक-23.12.2020, एस0ओ0-241, 73, दिनांक-30.12.2020, एस0ओ0-74, 75, दिनांक-14.01.2021, एस0ओ0-84, दिनांक- 12.03.2021, एस0ओ0-86, दिनांक-26.03.2021, एस0ओ0-99, 100, 101, दिनांक- 02.06.2021, एस0ओ0-104, 105, दिनांक-14.06.2021, एस0ओ0-106, दिनांक- 16.06.2021, एस0ओ0-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, दिनांक-01.07.2021 एवं एस0ओ0-117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, दिनांक-09.07.2021 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

टर्न-10/आजाद/29.07.2021

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष

2012-13 एवं 2013-14, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमपनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957'' की धारा-28 (3) एवं ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019'' के नियम-90 के तहत ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण)(संशोधन) नियमावली, 2021'' की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 299वाँ प्रतिवेदन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित 303वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल है, इसको पढ़ने दिया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, ध्यानाकर्षण के बाद । 32 शून्यकाल पढ़ा गया और टाईम 20 मिनट है और 20 मिनट के अन्दर 32 शून्यकाल हुआ है ।

(व्यवधान)

आप जितना टाईम बर्बाद कर रहे हैं आगे मौका मिलेगा, ध्यानाकर्षण के बाद हम पढ़ायेंगे, समय मिलेगा । हम तो खुद आपलोगों को मौका दे रहे हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री जनक सिंह, संजीव चौरसिया एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । सूचना पढ़ी गयी है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : इसमें समय चाहिए, कल हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । सूचना पढ़ी गयी है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : इसमें भी समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है .....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए ध्यानाकर्षण में स्वीकृति मिली है । माननीय मंत्री जी, विधान परिषद् में हैं ।

श्री अजीत शर्मा : ई0डब्लू0एस0 से संबंधित मामला है मंत्री महोदय ।

अध्यक्ष : चलिए, श्री आलोक कुमार मेहता जी ।

सर्वश्री आलोक कुमार मेहता, ललित कुमार यादव एवं श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण में सूचना दी है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के द्वारा पत्रांक-7446 दिनांक 23.07.2021 को निर्गत किये गये संकल्प के माध्यम से बिहार सरकार के अन्दर काम करने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद बिना कोई .....

अध्यक्ष : आप पहले ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़िए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार संकल्प संख्या-7446, दिनांक 23.07.2021 निर्गत कर राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है । राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना कूलिंग पीरियड के संविदा के आधार पर नियोजन करने का व्यवस्था संकल्प के जरिए कर रही है । उक्त संकल्प के लागू होने से एक तरफ तो सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेंशन के साथ-साथ वेतन भी प्राप्त करेंगे वहीं दूसरी तरफ वर्षों से राज्य के सभी सेवाओं के कर्मियों एवं अधिकारियों को प्रोन्नति न कर उनके मनोबल में ह्रास कर रही है । यदि सरकार चाहे तो वरीय पदों पर कनीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति देते हुए कनीय पदों पर नयी नियुक्ति कर सकती है । बिना कूलिंग पीरियड के अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियोजन करने से एक तरफ तो उनके सेवा अवधि में निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होगा वहीं दूसरी तरफ सरकार के चहेतों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार की तरफदारी का अवसर प्रदान करेगा । यह संकल्प राज्य सरकार की अदूरदर्शिता

एवं बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला है । ऐसे संकल्प को लोकहित में रद्द किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित अति लोकमहत्व के विषय की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी समय चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री कृष्णनन्दन पासवान, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री कृष्णनंदन पासवान, अनिल कुमार एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कृष्णनन्दन पासवान : अध्यक्ष महोदय, ''भारत सरकार और बिहार सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना स्वायल हेल्थ कार्ड योजना है । स्वायल हेल्थ के अन्तर्गत मिट्टी की जॉच कर कौन सा रसायन उपयोग किया जायेगा इसकी जानकारी किसानों को दी जाती है । मानव जीवन के लिए कौन से उपयोग रासायनिक हैं, यह भी बताया जाता है । मिट्टी जॉच मूलतः रसायन विज्ञान के डिग्रीधारकों द्वारा ही हो सकती है । राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जॉच प्रयोगशालाएं हैं जिसमें ''मृदा विश्लेषक मानव बल'' के नाम से पद सृजित है । ये पद स्थायी रूप से अभी तक भरे नहीं गए हैं । कुछ ही जगहों पर दैनिक वेतनभोगी मृदा विश्लेषक मानव बल नियुक्त किया गया है जबकि राज्य में रसायन विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं की संख्या काफी है ।

अतः किसान एवं राज्य हित में मृदा विश्लेषक मानव बल के स्थायी पदों के विरूद्ध रसायन विज्ञान के डिग्रीधारकों को स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जॉच प्रयोगशाला कार्यरत है । परन्तु इन प्रयोगशालाओं में मृदा विश्लेषक मानव बल के नाम से कोई भी पद सृजित नहीं है । केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत मानव बल के रूप में मिट्टी नमूनों की जॉच में सहयोग हेतु प्रति मिट्टी नमूना के विश्लेषण में सहयोग हेतु 60रू0 मात्र की पारिश्रमिकी पर पूर्णतः अस्थायी रूप से मिट्टी जॉच प्रयोगशालाओं में रखा जाता है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-11/ज्योति/29-07-2021

क्रमशः

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : जो मृदा विश्लेषक नहीं है । प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्त होने पर इन्हें रखा जाता है जो आवश्यकता आधारित एवं पूर्णतया अस्थायी है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह स्थायी रुप से किसानों से जुड़ा हुआ मामला है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार प्रयत्नशील है कि किसानों के उपज में वृद्धि हो । लेकिन वृद्धि होती है तब जब किसानों की मिट्टी बंजर हो जाती है और मिट्टी में खाद भी दिया जाता है और वह फसल उगती नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मिट्टी की जॉच की प्रयोगशाला है लेकिन सरकार डिग्रीधारकों को स्थायी रुप से नियुक्त करना चाहती है ताकि किस मिट्टी में कौन सा रसायन खाद दिया जायेगा ताकि किसानों को फसल उपजाने में लाभ मिल सके?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , मंत्री : महोदय, स्वायल हेल्थ कार्ड जो दिया जाता है और मिट्टी की जॉच जो प्रयोगशाला में की जाती है तो उसकी जॉच और उसका विश्लेषण विशेषज्ञ ही करते हैं और विशेषज्ञ हैं प्रयोगशाला में । (व्यवधान) भाई वीरेन्द्र ध्यान से सुनिये आप किसान नहीं हैं क्या ? सुनिये न वीरेन्द्र जी और ललित जी दोनो-ऐसा नहीं है जो जॉच करते हैं वह विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हैं इस आधार पर हर जिले में स्थापित जो जॉच प्रयोगशाला हैं वह काम कर रहे हैं । मैं इसके बारे में बिल्कुल जो ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान जी द्वारा लाया गया है मैं स्पष्ट उनके दिमाग में यह बात देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें कहीं कंफ्युज्न की बात नहीं रहनी चाहिए कि कैसे काम होता है प्रयोगशाला में । इसमें पॉच बातें हैं मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ । पहला बिहार राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय जॉच प्रयोगशाला स्थापित है । काम कर रहा है तथा क्रियाशील है जिसके प्रभारी पदाधिकारी सहायक निदेशक, रसायन हैं जो वर्ग -2 के पदाधिकारी होते हैं ।

अध्यक्ष : चलिए अब संसूचित हो गया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय मिट्टी जॉच प्रयोगशाला में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी वर्ग-3 के पदाधिकारी का पद स्वीकृत है जो कार्यरत हैं जो मिट्टी नमूनों की जॉच करते हैं। यह रिपोर्ट आज का है और यह जारी है । यह पहले से भी है आप किसी

प्रयोगशाला में जाकर स्वयं भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं । तीसरा सुन लीजिये ..

अध्यक्ष : अब हो गया माननीय मंत्री जी । संतुष्ट हो गए, माननीय मंत्री जी । अब शेष शून्य काल लिए जायेंगे ।

सामान्यत: शून्य काल की सूचना के लिए किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत नहीं किया जाता है । मैं इस मामले को अपवादस्वरुप लिया हूँ और यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा और आगे से इसको ध्यान में रखेंगे । मनोज मंजिल जी ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, दुल्हिनगंज, भोजपुर में पूर्व मंत्री श्री भगवान कुशवाहा के परिवार द्वारा महादलित परिवार के नवयुवतियों, महिलाओं, बुजुर्गों पर हमला किया गया, भाकपा-माले जांच दल में शामिल मुझ पर भी हमले की कोशिश की गई । सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रॉयल चलाकर न्याय की मांग करता हूं।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के परैया प्रखण्ड में मात्र एक ही विद्युत सब-स्टेशन है, जिसके कारण अत्यधिक दूरी पर स्थित पंचायतों में विद्युत आपूर्ति में काफी कठिनाई होती रहती है ।

अत: परैया प्रखण्ड के पुनाकला पंचायत में एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण शीघ्र करायी जाय ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पिपरा विधान सभा के चकिया बाजार में रेलवे गुमटी पर प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिए जी0ए0डी0 एप्रूव हो चुका है और उसका डी0पी0आर0 बनाकर स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा गया है ।

अत: डी0पी0आर0 की शीघ्र स्वीकृति कराकर पुल का निर्माण प्रारंभ कराया जाय ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अन्तर्गत कोरोना काल में ऐसे सैकड़ों मरीजों की मौत हुई है जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है इसके बावजूद उनका नाम अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है । ऐसे मृत व्यक्तियों की जांच कर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 74 साल बाद भी पटना के पालीगंज प्रखंड स्थित सरसी-पिपरदाहां पंचायत के घुर्णा बिगहा गांव में आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है । इसके चलते ग्रामीणों को भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । घुर्णा बिगहा में अविलंब सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 'गेट स्कोर' के आधार पर संविदा पर नियोजित सहायक अभियंताओं (असैनिक) के स्थायीकरण की मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के सेक्शन 18(13) के अंतर्गत वर्ष 2016 से निर्धारित शुल्क दान देकर सीनेट की आजीवन सदस्यता लंबित है ।

अतः जितने लोगों की सदस्यता लंबित है उसे अविलंब अधिसूचित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाय ।

श्री सुधाकर सिंह : रामगढ़ विधान सभा के बन के बहुआरा गांव में पानी निकासी के नाला को मिट्टी भरकर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कर देने से जलजमाव की विकट समस्या पैदा हो गई है । ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए पक्की सड़क काटकर तीन चार जगहों पर नाला बनाने का कार्य करावें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, आशा कार्यकर्त्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किये हैं। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ है । लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है । आशा कार्यकर्त्ताओं को कर्मचारी का दर्जा एवं 18 हजार रूपये मानदेय देने की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत नरपतगंज प्रखण्ड के गौड़राहा बिशनपुर पंचायत स्थित वार्ड 9 में जय प्रकाश यादव के घर में सिमरबन्नी स्थित दीना भद्री थान तक कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिनके प्रयास से या जिनके निमंत्रण पर बादल आया, उन्हीं के घर बरसात नहीं हो रही है । जरा बचोल जी पर तो ध्यान दीजिये।

अध्यक्ष : धैर्य रखने वालों को जरूर मिलेगा ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव में चार दशक से चल रहे गंगा बटेश्वर पम्प नहर योजना का लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पा रहा है जिससे किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है ।

अतः सरकार से उक्त पम्प योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामविशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर के तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी स्थानांतरण के पश्चात 15वीं वित्त का पैसा बिना खाता में रहे करोड़ों रूपये का चेक दिनांक 26.03.2021 को विन्देश्वरी प्रसाद,

राजस्व कर्मचारी के नाम से निर्गत कर गबन किये हैं जबकि उक्त राशि ऑनलाईन भुगतान करना है ।

टर्न–12/अभिनीत–पुलकित/29.07.2021

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक की नियुक्ति जनहित में शीघ्र कराई जाय ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र की जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, सिर्फ 11 ही शब्दों में है ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु में नदियाँ भर जाने से सीमांचल सहित मेरे विधान सभा में नाव ही एकमात्र साधन है ।

अध्यक्ष : अब शांत रहिये ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : घाटों में सरकारी नाव के अभाव में गांववासियों का सम्पर्क जिला तथा प्रखण्ड मुख्यालय से टूट जाता है ।

मैं संबंधित विभाग से मांग करता हूं कि अविलम्ब घाटों में नाव की समुचित व्यवस्था हो ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, ''ममता'' कार्यकर्त्ता की प्रोत्साहन राशि 300/– रूपये से बढ़ाकर 1000/– प्रति डिलेवरी करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला विस्फी एवं रहिका प्रखण्ड में धौस, जीवछ नदियों में आयी भीषण बाढ़ से आम जनता का जीवन स्तर व्यस्त हो गया है । किसानों की खेती चौपट हो गयी है । सरकार अविलम्ब राहत कार्य चलावे ।

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले में चेरिया बरियारपुर, खोदावनपुर एवं छौड़ाही प्रखंडों में सालोंभर हो रहे जलजमाव से कृषि कार्य प्रभावित हैं, जिसे कृषक हित में जलजमाव से शीघ्र मुक्त करायी जाय ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, नरकटिया विधान सभा के बंजरीया प्रखण्ड के 13 पंचायतों को बाढ़ ग्रस्त घोषित करते हुए प्रत्येक परिवार को 6000/– रुपये जल्द से जल्द दिये जायं ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा सी0बी0एल0के0 कॉलेज बरियारपुर के लिये भेजे गये संबंधन को शिक्षा सचिवालय पटना द्वारा अस्वीकृत करने संबंधित कारण के जांच की मांग सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अंतिम आपके ही बगल में बैठे हैं ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी अंचल कार्यालय द्वारा शहर का नाम मच्छरगांवा भेजा गया, लेकिन नव सृजित नगर पंचायत का नाम- ''योगापट्टी'' हो गया है । सदन के माध्यम से सुधार की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, केवटी विधान सभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा प्रखण्ड अंतर्गत कलिगांव पंचायत के निस्ता चौड़ी से वाटरवेज कुरसाहा (खिरोई नदी) तक पक्की नाला का निर्माण किया जाय जिससे लगभग दो हजार एकड़ जमीन कृषि योग्य हो जायेगा । अन्नदाता के हितों में सोचते हुए इसे शीघ्र बनवाने की कृपा की जाय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार में लगभग 80000 (अस्सी हजार) अधिवक्ता हैं जो कोरोना काल में न्यायालय में न्याय प्रक्रिया (केस हेयरिंग) बंद रहने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं । मैं देश के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भांति वित्तीय सहायता, जीवन यापन भत्ता के रूप में देने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखंड में वर्ष 2017 में रबी फसल की क्षतिपूर्ति हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा 564 कृषकों की सूची उपलब्ध करायी गयी, उसमें से केवल एक किसान को ही अनुदान मिला, बाकी किसानों को भी अनुदान देने की मांग करता हूं ।

श्री अली अशरफ सिद्दीकी : (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री रण विजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड के निकसपुर पंचायत अंतर्गत चन्दौली हाट से भाया लालू चौक, रामपुर होते हुए उदा हाट एन0एच0 103 तक सड़क काफी जर्जर है ।

सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाय ।

श्री विनय कुमार चौधरी : (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती मंजू अग्रवाल : महोदय, शेरघाटी विधान सभा अंतर्गत नदी घाटों से अवैध बालू की ढुलाई बालू माफियाओं के द्वारा काफी तेजी से हो रही है । प्रशासन को सारी जानकारी रहने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है । ये कार्य प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है । जिसमें उच्च पदाधिकारी भी शामिल हैं ।

अतः दोषियों पर कारवाई करने का कष्ट करें ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज प्रखण्ड में चमुआ बखरी मुख्य मार्ग पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल का निर्माण रोहन कन्स्ट्रक्शन द्वारा कराया गया था, तीन माह के अंदर नवनिर्मित पुल ध्वस्त हो गया है । मैं सदन के माध्यम से इसकी जांच की मांग करता हूं।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधान सभा में मेजरगंज के बसबिट्टा पंचायत के रसुलपुर गांव में बागमती नदी के कटाव के कारण 50 बीघा जमीन एवं हजारों घर नदी की धार में आ गया है । बांध निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत गोविंदगंज विधान सभा के अरेराज, पहाड़पुर एवं संग्रामपुर प्रखण्ड के आधे भाग में बाढ़ का पानी, आधे भाग में जलजमाव के कारण धान की रोपनी नहीं हो पायी, जिसके कारण किसानों का बहत बुरा हाल है । मैं सदन से मांग करता हूं कि फसल क्षतिपूर्ति एवं आगामी रबी फसल के लिए बीज, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के संबद्ध महाविद्यालयों में प्रबन्धकारिणी समिति का गठन वर्षों से लम्बित है । उक्त समिति के अभाव में महाविद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है । साथ ही डी0ए0वी0 महाविद्यालय, सिवान के कर्मियों का भुगतान नवम्बर, 2011 से लम्बित है । समस्याओं का निदान शीघ्र कराया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठ जाइये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इसके लिए हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिना प्रबंधकारिणी समिति के एफिलेटेड जो कॉलेज हैं, आप सोच सकते हैं कि छपरा विश्वविद्यालय में जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं उसमें किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कमिटी का गठन नहीं हो सका है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठ जाइये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, यह सोचने का विषय है, कैसे कॉलेज चलेगा ।

अध्यक्ष : आपके सीनियर सीटिजन को ध्यान में रखकर के समय दिया है ।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/हेमंत-धिरेन्द्र/29.07.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या 39 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अत: किसी एक विभाग की अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग को लेता हूं । जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन(मुखबंध) द्वारा किया जायेगा ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी सुनिये शांति से ।

इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है ।

(व्यवधान)

आप पुराने सदस्य हैं, बिना अनुमति के बार-बार उठकर बोलना आपको शोभा नहीं दे रहा है । अभी बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

जब हम बोल रहे हैं । आप आदत मत बनाइये, बैठ जाइये ।

विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | - | 56 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | - | 55 मिनट |
| जनता दल युनाइटेड | - | 32 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | - | 14 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0एल0) | - | 09 मिनट |

| | | |
|---|---|---|
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | - | 04 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | - | 03 मिनट |
| विकासशील इंसान पार्टी | - | 03 मिनट |
| सी0पी0आई0एम0 | - | 02 मिनट |
| सी0पी0आई0 | - | 02 मिनट |
| | कुल | 180 मिनट । |

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' स्वास्थ्य विभाग'' के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3673,99,40,000/- (तीन हजार छः सौ तिहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री ललित कुमार यादव, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री सुधाकर सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं । जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय । ''

महोदय, सरकार की डिमांड पर कटौती प्रस्ताव मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि महोदय, कोरोना काल में राज्य में जो अव्यवस्थाएं थीं और कोरोना काल में महामारी से पूरा देश प्रभावित था, अपना राज्य भी प्रभावित था । जनता की अपेक्षाएं सरकार से महामारी काल में बेहद थी और सरकार से अपेक्षाएं जनता को । आम आदमी इतना हुजूर महामारी से त्रस्त था । पूरे देश में अपने प्रदेश के ऐसे लोग विदा हो गए हमसे, हमारे बीच से और लगता था कि कल होकर कौन चला जायेगा, कहना मुश्किल था । ऐसे में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, राज्य में भी ऑक्सीजन की कमी हुई, सरकार के मंत्री का बयान आया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, मानने

योग्य नहीं है । पूरे देश में कोई नहीं मानेगा, सरकार भले ही कह ले, पीठ जरूर बजा ले लेकिन ऑक्सीजन का अभाव था और घोर अभाव था । देश के माने-जाने संगीतज्ञ बिहार के, सांस-सांस कहते हुए उनके प्राण पखेरू उड़ गये, एक सिलेंडर नहीं मिला, पूरा देश, मुल्क गवाह है, फेलियर हुआ है सिस्टम का, व्यवस्था का । देश के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस समय कोरोना काल की आवक का देश को, देश के संसद में इस सवाल को उठाया था, लोगों ने मजाक उड़ाया । मजाक उड़ाया गया राहुल गांधी जी का, कोई माना नहीं लेकिन जिस वक्त राहुल जी कांग्रेस के नेता, हमारे नेता आवाज उठाये, अगर देश संभला होता, देश की व्यवस्था भारत सरकार, देश की राज्य सरकारें अगर संभली होतीं तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता था लेकिन कोई नहीं संभला और देश से कीमती लोग चले गये । जितनी मृत्यु हुई, चाहे अपने राज्य में या राज्य के बाहर देश में, उस मृत्यु की विवेचना, गणना सही ढंग से नहीं हुई और कहा गया कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार जिम्मेदारी नहीं ली, जब टीके लगने थे, टीके की व्यवस्था थी, यह पूरी दुनिया में हुजूर, जो देश व्यवस्था किया टीकाकरण हुआ, उस देश में मृत्यु नहीं हुई । कोरोना रुका लेकिन अपने यहां समय पर व्यवस्था नहीं हुई । पूरे देश की सरकार, राज्य सरकार की इस मामले में फेलियर रही है । महोदय, राज्य सरकार में बहुत कीमती मौत हुई, लोग गये, बहुत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य, प्रदेश में अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की । इस मामले में, मैं श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने साहस दिखाया और कहा कि हम अपने राज्य में मृतकों के परिजन को चार लाख रुपया देंगे । मैं स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस अवसर पर । स्वास्थ्य का विषय है लेकिन एक बात महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आसन के माध्यम से सरकार से कि आप उस सिस्टम में अंचलाधिकारी के माध्यम से आवेदन लिये जाते थे अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था में, अब आप सी0एस0 के माध्यम से अनेक उसमें लेकुना लगाये जा रहे हैं । कोई मृतक की पत्नी को दौड़ते-दौड़ते परेशान हो कर अनुग्रह अनुदान की आस, मन में तृष्णा चार लाख रुपये की प्यास बुझती नजर आ रही है । पैसा देना है सिस्टम को सरल कीजिये, जब सी0एस0 के यहां से, सी0एस0 के कार्यालय से प्रमाण-पत्र जारी हो गया, मृत्यु प्रमाण-पत्र पर्टिकुलर अस्पताल से जारी हो गया कि व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई । उस प्रमाण-पत्र के बाद, आवासीय प्रमाण-पत्र के बाद कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चार लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान हो जाना चाहिए । व्यक्ति को परेशान नहीं होने की जरूरत है, यह सरकार व्यवस्था करे । महोदय, उसके बाद से, तृतीय फेज कोरोना, जो बच्चों के

लिए घातक हो सकता है । देश में संभावनाएं आयी, पूरे मुल्क के सभी राज्यों ने अपनी तैयारी की, हमारी भी तैयारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि अब ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं रहेगी ।

(क्रमशः)

टर्न-14/संगीता-सुरज/29.07.2021

(क्रमशः)

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कार्रवाई भी हुई लेकिन आज तक एकाध प्लांट को छोड़कर, उसी में हमारे अनुमंडल में, हमारे क्षेत्र में, महाराजगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगा । प्लांट तो लग गया लेकिन चालू नहीं हुआ । मैं आसन से विधानसभा में एक सवाल भी किया था कि ऑक्सीजन प्लांट कब चालू होगा ? जवाब भी आया अगस्त के अंत में, क्या हो रहा है ? एन0एच0ए0आई0 को आपने प्लांट लगाने को दिया । हर सिस्टम को अलग-अलग आपने दिखावे के लिए तो लोगों को लगा दिया कि भाई हम बहुत तेजी से करना चाहते हैं । जल्दीबाजी में ऑक्सीजन प्लांट सभी अनुमंडलों में, अखबारों में, सुर्खियों में आपके अखबार एडवरटिज्मेंट के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश को सूचना दिया कि हम ऑक्सीजन के लिए, तृतीय फेज के लिए तैयार हैं । उस तैयारी के हालात अच्छे नहीं हैं । एकाध प्लांट को छोड़कर के पटना में, पूरे राज्य में, सब अनुमंडलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हुआ है और ऑक्सीजन प्लांट तैयार होने चाहिए, अन्य उपकरण तैयार होने चाहिए, कोरोना से निपटने की तैयारी होनी चाहिए । महोदय, इस अवसर पर मैं सरकार से यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं । महोदय, ये तो सारा डिमांड एक दिन का है और सारे डिमांड एक ही गिलोटीन में शामिल है । अन्य दिनों में बोलने का अवसर, कहने का अवसर नहीं मिलेगा इसीलिए स्वास्थ्य विभाग से हटकर के मुझे कुछ कहना आवश्यक है । महोदय, एक सवाल को मैं रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से, एपेक्स कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट कहा बिहार में पुलिस शासन, पुलिस राज कायम है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं देश का सुप्रीम कोर्ट कहा है, ये प्रमाणित है महोदय । नवगछिया में एक इंजीनियर जो अपनी पत्नी के साथ दशहरे में दिनांक- 24.10.2020 को पूजा-पाठ करके लौट रहा था । रंजीत मंडल नाम का ऑफिसर इंचार्ज रास्ते में सिविल में मोटरसाइकिल चेकिंग के लिए खड़ा था, हुजूर । अंदर रिवाल्वर लटका के सिविल में दारोगा पुलिस चेकिंग करता था जो गलत है, पुलिस मैन्युअल के खिलाफ है । सिविल में दारोगा ड्यूटी नहीं कर सकता और रंजीत मंडल ने हाथ दिया । आशुतोष

कुमार पाठक मोटर साइकिल रोके, उनको पीटना शुरू कर दिया । आशुतोष कुमार पाठक से एक गलती जरूर हुई कि उन्होंने सिविल में खड़े दारोगा को नहीं समझा और उनसे बहस शुरू किया । उसका परिणाम क्या हुआ हुजूर, परिणाम हुआ कि उनको वहां जीप में बांधकर के दिन-दोपहर घसीट करके नवगछिया थाने में ले जाकर के 4 बजे शाम तक पीटा गया और उसी थाने में उनके ससुर नौकरी करते थे, वो चिखते-चिल्लाते रहे, औरत चीखती-चिल्लाती रही, 3 वर्ष की गोद में अबोध बच्ची पापा, पापा चिल्लाती रही पुलिस नहीं मानी तब तक पिटाई करती रही जब तक आशुतोष कुमार पाठक की मौत नहीं हो गई ये क्या है ? महोदय, इस राज्य में ऐसी घटना घटती है भागलपुर इलाके में । सरकार कहां है ? कहां सरकार सोई हुई है और मैं महोदय बड़ी दर्द और पीड़ा से कहना चाहता हूं कि...

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, घसीटा नहीं गया था...

(व्यवधान)

श्री विजय शंकर दूबे : आप बैठिये तो सही । आप बैठिये तो ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय...

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मुझे उसको पूरा कर लेने दिया जाय । महोदय, मैंने 15.03.2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो सरकार के मुखिया हैं, अगुआ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उनके समक्ष आवेदन दिया । मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 16वें साल में प्रविष्ट कर गए, श्रीबाबू से ज्यादा आगे बढ़ गए लेकिन करनी हुजूर ठीक नहीं है । तीन दिन में कागज पहुंचना चाहिए वह पत्र महोदय, गृह आयुक्त के यहां 15.03.2021 को मुख्यमंत्री के कार्यालय में पता नहीं जदयू का कागज पहले पहुंच जाता है उसके बाद बी0जे0पी0 वालों का भले ही पहुंच जाता हो, हमारे कागजात को गृह आयुक्त के कार्यालय में पहुंचने में यात्रा करनी पड़ी 22 दिन के बाद गृह आयुक्त के यहां बिहार सरकार में पहुंचा है और कार्रवाई नहीं हुई । महोदय, कोई अनुग्रह अनुदान की बात नहीं हुई और तब हार कर उस मामले को मानवाधिकार आयोग के यहां...

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मानवाधिकार के यहां पेटिशन दिया, मानवाधिकार ने तुरन्त मामले को एग्जामिन करके मैं धन्यवाद करता हूं मानवाधिकार राज्य में काम ठीक से हो रहा है...

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद ।

श्री विजय शंकर दूबे : और सात लाख रुपये वार्ड के कलेक्टर ने दिया लेकिन सरकार से मैं मांग करता हूं महोदय कि ऐसे मामले में देश के जाने-माने साहित्यकार मैनेजर पाण्डे, गोपालगंज उनके बेटे के साथ ऐसी घटना घटित हुई । लालू जी का राज था और राबड़ी देवी जी...

अध्यक्ष : अब बैठ जायं, बैठ जायं । श्री भूदेव चौधरी जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, एक मिनट । महोदय, ऐसे मामले में 15 लाख रुपये, विधवा को नौकरी और मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उस आशुतोष पाठक की विधवा को नौकरी...

अध्यक्ष : आखिर जो एक्स्ट्रा समय होगा वह एड्जस्ट कहां होगा, बैठ जाइये अब ।

श्री विजय शंकर दूबे : और सरकार उसे अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था करे, उसके जीवन-यापन की व्यवस्था हो, विधवा को नौकरी हो यह मैं मांग करना चाहता हूं । महोदय मैं...

अध्यक्ष : अब भूदेव जी को हम बुला चुके हैं ये नहीं बोलेंगे तो इनका समय गिनती तो चालू है ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार करे व्यवस्था । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव...

अध्यक्ष : भूदेव चौधरी जी ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के संबंध में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, आभारी हूं । महोदय, यह बात सही है कि अभी विगत दिनों, विगत माह फरवरी में, जो आम बजट आया उसमें 2 लाख 18 हजार का बजट आया और उसमें से 27 हजार 50 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित हुई किन्तु मुझे यह हैरत होती है कि अभी इतने कम समय में ही स्वास्थ्य विभाग के लिए 3 हजार 673 करोड़ राशि की मांग की गई है । मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने कम समय में स्वास्थ्य विभाग को इस मांग को रखने का क्या औचित्य पड़ा ? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विकट परिस्थितियों से यह बिहार अभी-अभी हाल में गुजरा है । जब आदमी जिन्दगी से निराश और हताश हो जाता है चारों तरफ जब उसकी नजर पड़ती है तो उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान और उसके पहले अगर मेरी जिन्दगी कोई बचा सकता है तो वह है डॉक्टर, वह है स्वास्थ्य विभाग लेकिन विगत दिनों जो स्थितियां बिहार के लोगों ने देखा है तड़प-तड़प कर मरते हुए देखा है, चिल्लाते-चिल्लाते मरते हुए देखा है, यह स्वास्थ्य विभाग की चर्चा जब होती है तो रूह कांप उठती है, आत्मा व्यग्र हो

उठती है । मैं भी खुद भुक्तभोगी हूं ।

(क्रमशः)

टर्न-15/मुकुल-राहुल/29.07.2021

क्रमशः

श्री भूदेव चौधरी : और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग चिल्ला-चिल्ला करके अपनी जान गंवा बैठे हैं और इतना ही नहीं पता नहीं कहां से मंत्री महोदय को यह बयान देने का अवसर मिला कि कोरोना में, कोविड में कोई भी आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। मैंने देखा है, अध्यक्ष महोदय, अब ऐसे-ऐसे लोगों को वहां डिप्यूट किया गया था कि जब मैं खुद पेशेंट को लेकर गया तो ऐसे लोगों के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर था जिसको लगाने का हुनर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कि वह सिलेंडर कैसे लगाये और उसको यह भी अनुभव नहीं था कि सिलेंडर में ऑक्सीजन है कि नहीं है । ऑक्सीजन के बगैर-बगैर, हजारों-हजार लोगों की जान चली गई, किसी-किसी को तो कहा गया कि आप होम-आइसोलेट हो जायं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां भी लोग देख रहे थे कि कोई आकर के मेरी मदद करे लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता था, जोकि सीनियर डॉक्टर होते थे वे पेशेंट को देखते नहीं थे, किट किसी भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को पहना देता था और उसको पता नहीं कैसा एडवाइस मिलता था कि वह देखता था और वह देखेगा क्या, वह तो जो रेफर होकर जाता था । मैं आपको बताऊं, हमारे माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल जी बांका के हैं, चार-चार वेंटिलेटर वहां है एक अमरपुर में और एक बौसी में, 6 हैं 6, एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा और आज की तारीख में वह वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है । मुझे तो आश्चर्य होता है कि वेंटिलेटर अगर वहां रहता तो 57 लोगों की जो जान गई है वह जान किसी की नहीं जाती । प्रखंड के पी0एच0सी0 में तो ऑक्सीजन का इतना अभाव था कि कोई भी आदमी साधारण सर्दी-जुकाम होता था और वह जाते थे तो सीधे के सीधे उनको कह देता था कि आप जाओ जिला हॉस्पिटल में और अध्यक्ष महोदय, जिला हॉस्पिटल जो भी जाता था वह वापस नहीं लौटता था । अभी ये-ये बातें उठीं कि चार लाख रुपया दिया गया, जिंदगी के सामने यह चार लाख का कोई मुराद नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट कोई वैल्यू नहीं है और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे गांव में तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो दो दर्जन लोगों की जान गई, लेकिन कुछेक को छोड़कर मुझको लगता है कि अभी शत-प्रतिशत लोगों को यह पैसा भी नहीं मिला है यह तो आंख में धूल

झोंकना हुआ । आपने जिंदगी के साथ क्रूरतम मजाक किया । कोई नहीं चाहता, गरीब की तो जान गई ही पैसे वालों की भी जान गई है और आपने देखा होगा कि दवा के लिए पंक्तिबद्ध, इलाज के लिए पंक्तिबद्ध और जब जान चली जाती थी तो श्मशान घाट में जलने के लिए भी पंक्तिबद्ध होना पड़ता था, पंक्तिबद्ध होना पड़ता था और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नदियों में जो लाश तैर रही थी उस तैरती हुई लाश को पहचानने में भी सरकार आनाकानी की और नतीजा यह हुआ कि जिसको जलना चाहिए था वह जला नहीं, जिसको कब्र होना चाहिए था उसको कब्र नहीं हुआ। यह स्थिति इतनी भयावह और इतनी गंभीर हुई कि रूह कांप उठती है । मैं स्वास्थ्य विभाग के इन कारनामों से बहुत दुखी हूं, यह तो धन्य है आर0जे0डी0 ने, राष्ट्रीय जनता दल विधायकों ने संपूर्ण बिहार में और विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में यह लालू रसोई अभियान चलाया जिससे कि गरीबों की जान बची, गरीबों की जान बची ।

(व्यवधान)

अगर यह राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो शायद बीमारी से तो जिन लोगों की जान गई ही, भूख से भी जान चली जाती ।

अध्यक्ष : आप लोगों को भी मौका मिलेगा, उसमें अपनी-अपनी बात बोलियेगा ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके निर्देश पर बिहार के हर क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने खाने की व्यवस्था की, दवा की व्यवस्था की, सेनेटाइजर की व्यवस्था की और उचित इलाज की व्यवस्था, इसलिए तो धन्यवाद के पात्र हैं । मैं कहना चाहता हूं आदरणीय, अरे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दवाई 40-50 रुपये में बाजारों में मिलती थी, जब यह कोरोना का लहर आया तो उसकी कीमत 400 से 500 हो गई, जो दवाई 40-50 रुपये में मिलनी चाहिए थी वह लाखों में मिलने लगी, रेमेडेसिवीर वह लाखों में मिलने लगी, लोग तड़प-तड़प के जान दे दिये । हमारे यहां एक डॉक्टर थे प्रेम राज बहादुर जी, वे डॉक्टर थे धौरैया में कार्यरत थे । जब वे बीमार पड़े तो चिल्ला रहे थे, डॉक्टर से आरजू मिन्नत कर रहे थे कि मेरी जान बचाओ, मुझको सुई दो, दो-दो लाख में सुई का डिमांड हुआ उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाई। महोदय, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, भारी मन से कहना पड़ता है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 49 स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं आपको जानकर के दुख होगा, आश्चर्य होगा कि उसमें से 32 ऐसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं जिसका भवन ही नहीं है वे या तो किराये पर चल रहे हैं या

तो कागज पर चल रहे हैं, कहीं नेम प्लेट नहीं है । निराशा और हताश है वहां के लोगों को, उसमें से जो 5 रजौन में बने हैं और 14 धौरैया में बने हैं वह भवन बने हुए लगभग दशकों हो गए, जर्जर स्थिति में है, दीवार फट गई है, छत चरमरा गई है, बरसात में पानी टपकता है । हम आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर जिंदगी के प्रति आप सजग हैं, आपमें सजगता है तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में आप सर्वे करवाएं और जहां भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र में भवन नही हैं वहां भवन की व्यवस्था करवाएं और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 23 जगह जमीन भी उपलब्ध है और मैं कोशिश करके भी अन्य जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र है उसके लिए जमीन आवंटित करने को कह दिया है लोग देने के लिए तैयार हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिंदगी अब भगवान के हाथ में है या डॉक्टर के हाथ में । आपने देखा होगा किस तरह से अब तो तीसरी लहर की भी संभावना है, तीसरी लहर के आने की संभावना है उसकी भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । हम आपसे विनती करते हुए यह कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं, ये चार लाख रुपये की घोषणा से मैं खुश नहीं हूं ये तो आंख में धूल झोंकने के बराबर है । लोग कहते हैं कि चार लाख रुपया ले लेते मेरे पिताजी की जिंदगी बचा देते, मेरे भाई की जिंदगी बचा देते तो वह खुश होता । क्या सरकार ने आंकड़ा दिया ? सरकार ने आंकड़ा दिया की सिर्फ और सिर्फ बिहार में 5424 लोग कोरोना से मरे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ और हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया । जब हाईकोर्ट ने सरकार को डांटा फटकारा की फिर से सर्वे कराओ तो बढ़कर के वह आंकड़ा 9424 हो गया । क्यों आंकड़े छिपा रहे हैं, क्यों आप बरगला रहे हैं ? आप सर्वे कराएं, प्राइवेट हॉस्पिटल मे भी कई लोग मरे हैं, हमारे क्षेत्र की घटना है । एक अजय कुमार 28-29 वर्ष का नौजवान, उसको पोजिटिव हुआ, सरकार के पास मायागंज हॉस्पिटल में वह गया, वहां डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत सीरियस है यहां एडमिट नहीं होगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ईलाज कराया, लेकिन उसकी भी जान 17 अप्रील को चली गई । अब वहां के सी0एस0 पता नहीं क्या-क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है वह कहते हैं कि सरकारी सी0एस0 से लिखवा कर आओ । जब वह सी0एस0 के पास जाता है तो वे कहते हैं कि हम नहीं लिखेंगे, वह बांका के लोग लिखेंगे बांका के हो । हम जानना चाहते हैं सरकार से कि अगर आपका दिल उदार है, दयालु है और आप चाहते हैं कि कोरोना में जितने लोगों की जान गई है उसका सर्वे जरूर कराएं चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल में मरा हो, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल में मरा हो, उसकी जान गई है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि

हम उसको समुचित मुआवजा दें और आपने मुझको जो समय दिया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, समय बचा है शेष समय को आप...

अध्यक्ष : शेष समय जो छोटे दलों को जाता है बड़े दलों का समय उसमें एडजस्ट होगा । श्रीमती संगीता कुमारी ।

टर्न-16/यानपति-अंजली/29.07.2021

श्रीमती संगीता कुमारी: महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हैं । मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को, श्री ललित यादव जी को, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को और आदरणीय जगदाबाबू जी को, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा और इस गरिमामय पद को सुशोभित करने का मुझे अवसर प्रदान किया । मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया की जनता को साथ ही मैं सदन को भी आभार प्रकट करना चाहूंगी । राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था है फिर भी माननीय सदस्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से 600 करोड़ लगभग राशि दी गई है । महोदय, स्वास्थ्य विभाग को पूर्व के आवंटित राशि के बावजूद पुनः प्रथम अनुपूरक के द्वारा 3 हजार, 676 करोड़, 99 लाख 40 हजार जैसी भारी-भरकम राशि का कोई औचित्य नहीं है । चूंकि स्वास्थ्य बजट की बात हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने का मुझे अवसर मिला है और एक जन प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में जाता है तो मांगे होती थी कि रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं लेकिन समय के साथ लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं इसपर हम आएं हैं तो आज की हमारी मांग रही है कि पढ़ाई, दवाई और कमाई । पढ़ाई की जो स्थिति है बिहार में यह किसी से छिपी हुई नहीं है शिक्षा की कई बार सदन में भी चर्चा हो चुकी है । कमाई की जो बात हुई है जो अप्रवासी बिहारियों ने इसकी पोल खोल दी है लेकिन जहां रही बात दवाई की तो कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था जो खुलकर सामने आई है तो उसमें बिहार की सुशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है । महोदय, मैं चर्चा करना चाहूंगी कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई है, जिनलोगों की जान चली गई हैं मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ऑक्सीजन को देने में कमी नहीं की है निश्चित रूप से सरकार के जो कथन आए हैं उससे मैं समझती हूं कि जिन लोगों की जानें चली

गई हैं वह सांस लेना ही भूल गए थे इसलिए उनकी मृत्यु हुई है । बक्सर में पानी पर तैरती लाशें, जिन लोगों की मृत्यु हुई, बक्सर में जिस तरह से लाशें तैर रही थीं पानी पर और कुत्ते नोच रहे थे तो मानवता शर्मसार हो गई थी उस दिन और उस दिन यह लग रहा था कि कुत्तों के लिए होली और दिवाली आ गई है तो हम मानवता को तार-तार कर देखते रहे एक दूसरे को निहार रहे थे । आखिर कौन लोग थे जो पानी पर तैर रहे थे । जब मनुष्य जन्म लेता है तो इसके साथ होती है, जब मनुष्य मरता है तो उसके पास नाम होती है पर सांसें नहीं होती हैं । पानी पर तैरती लाशें बता गईं, वजन तो सांसों का था, हल्की-फुल्की सी जिंदगी, वजन तो ख्वाहिशों का था ।

महोदय, मानवता को शर्मसार करने वाले सारे कुकृत्य हैं । कोरोना काल में जब महिलाएं अपने पति का इलाज करने गईं तो इज्जत को तार-तार किया गया । परिजन अपने बच्चों को कंधे पर लेकर दौड़ते रहे और महिलाएं जब अस्पताल में गईं तो महिलाओं के साथ अपने पति की जिंदगी बचाने के साथ-साथ अपनी आबरू को बचाने की भी संकट आ गई थी । कोरोना काल में महिलाओं ने चीख-चीख कर ये रोना रो रही थीं एक तरफ पति को खोने का दुख और दूसरी तरफ थी इज्जत को बचाने का दुख, ये कोरोना काल में हमने महिलाओं का चीर-हरण देखा । तो सवाल उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का ढोंग रचने की बात हम करते हैं और सुशासन का ढोंग रचते हैं तो कोरोना काल में अस्पतालों में जब महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है और बेबस और लाचार महिलाएं रोती-बिलखती हैं तो सवाल उठता है मानवता भी कहीं न कहीं महोदय, शर्मसार होती है । सरकार की 4 लाख कोरोना काल में सरकार की जो वेंटिलेटर की बात हुई, सरकार की तरफ से आया कि 400 वेंटिलेटर हमारे पास थे लेकिन वेंटिलेटर तो थे लेकिन उसके चलाने वाले टेक्निशियन के लोग कहां थे, आपके मशीनें तो थीं चलाने वाले लोग कहां थे, आज भी कहां हैं और आज भी जब हम बात करते हैं महोदय, बिहार की स्वास्थ्य के मामलों में 21 बड़े प्रदेशों में बिहार 20वीं रैंक पर है जब कि सरकार विकास का दावा करती है । बिहार में एक डॉक्टर पर 28 हजार 391 आबादी की सेवा करता है बिहार कोई सुधार नहीं कर सका । महोदय, आज भी बिहार में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर गांव में 42 बच्चे मर जाते हैं 1000 की आबादी पर और शहरों में 1000 की आबादी पर 34 बच्चे मर जाते हैं जो देश के मानक से ज्यादा है, तो सुधार कहां हुआ ? अगर हेल्थ स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हम बात करेंगे, चाहे मैं अपने क्षेत्र की भी मैं बात करना चाहूंगी तो निश्चित रूप से उपकेंद्र की बहुत ही जर्जर व्यवस्था है, न डॉक्टर हैं, न भवन हैं,

न दवाइयां हैं और न कुछ भी और जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम करती है और भगवान भरोसे अपना इलाज करती है और ईश्वर जो करेंगे, तो हेल्थ मानक उपकेंद्र मानक के अनुसार 21000 उपकेंद्र होने चाहिए 10000 की आबादी पर, केंद्र के हिसाब से जो कि नहीं है । वर्तमान में मात्र 9949 उपकेंद्र हैं जो प्रति 55000 आबादी पर एक उपकेंद्र है, जो चिंता का विषय है और मानक से बहुत नीचे है । प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर बात किया जाय बिहार की महोदय, तो 3548 का है जो केवल 1899 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो आवश्यकता से 50 प्रतिशत कम हैं । 15 वर्षों में मात्र 2 प्रतिशत केंद्र की वृद्धि हुई, जो कि नाकामी है, जो कि चिंता की बात है कि 1373 केंद्र बंद क्यों हो गए ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाय, तो 2020 तक मात्र 533 ही हैं जबकि मानक के अनुसार 887 होने चाहिए जो कि मात्र 67 परसेंट ही हैं, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है । महोदय, मैं रेफरल अस्पताल की बात करूं, तो 2020 में 71 में से 57 ही चालू हैं और 14 रेफरल अस्पताल बंद हो गए हैं, क्या यही विकास है ? 2020 में 61 अनुमंडलीय अस्पताल में 55 ही चालू हैं, उनमें से सभी स्वीकृत पद पर चिकित्सकों की भारी कमी है, 6 अनुमंडल अस्पताल बंद हैं । अगर महिलाओं की स्वास्थ्य की बात की जाय तो महिलाओं की, खासकर ग्रामीण महिलाओं की आज भी कई ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं, जो चिकित्सकीय अभाव में मारी जाती हैं । अगर हम सर्वे की बात करें तो वर्तमान समय में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार 96.7 परसेंट महिलाओं को प्रसव से पहले चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलती है । महोदय, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार 21 बड़े राज्यों की तुलना में 20वें स्थान पर स्वास्थ्य इंडेक्स में चला गया है । राज्य में 10000 की आबादी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए केवल 8 डॉक्टर्स और 2 नर्स ही काम कर रहे हैं । महोदय, मैं कैमूर जिले से आती हूं, जहां पर सरकार की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होने चाहिए मैं मांग करना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो । कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो रही है और वैक्सीनेशन की बात हम अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं लेकिन 75 प्रतिशत ही होने चाहिए, जिसमें 26 प्रतिशत ही हुआ है और इसमें भी मैं समझती हूं कि ग्रामीण जनता के साथ कहीं न कहीं दोहरी भूमिका उनके साथ निभाई जा रही है । शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण ज्यादा है, ग्रामीणों में कम है, क्योंकि हमारे लिए ग्रामीण जो गांव की जनता है उसकी भी जिंदगी की कीमत उतनी ही है जितना शहरी की है । तो मैं मांग करना चाहूंगी कि गांव की जनता के साथ भी दोहरापन रवैया न अपनाया जाय । सरकार नेशनल हेल्थ पॉलिसी के

अनुसार, मैं एक मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जो सरकारी सहायता दे रही है, साथ ही निजी अस्पतालों में भी जो डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी सरकार जवाबदेह बने और सरकार उनको भी वह सहायता राशि दी जाय ।

अध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्रीमती संगीता कुमारी: महोदय, कोरोना काल में जिस तरह से दवाओं की कालाबाजारी की गई और जिस तरह से दवा के बिना लोग मारे गए, तो मैं सरकार से भी मांग करना चाहती हूं कि इस कालाबाजारी को किस तरह से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए और तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि तीसरी लहर की बात हुई क्या हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या हम उतनी तैयारियां कर चुके हैं क्या हमारे पास वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन प्लांट की मानक की भी बात हुई है लेकिन जितनी बातें आपकी आ रही हैं उसको चलाने वाले टेक्निशियन नहीं हैं, डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सों की भारी कमी है, तो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करे ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री विनोद नारायण झा ।

श्री विनोद नारायण झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया है । आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रथम अनुपूरक व्यय में सम्मिलित अनुदान मांग के क्रम में 3673 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांग रखी है । अपोजिशन की ओर से कटौती प्रस्ताव आया है । अध्यक्ष महोदय, आज जब वे लोग बोल रहे थे तो मैंने देखा आदरणीय दूबे जी और भूदेव बाबू भी चिंतित थे कि इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, यदि आप संवेदनशील होते, तो आज आप कहते कि पैसे की ज्यादा जरूरत है ।

...क्रमश:...

टर्न-17/सत्येन्द्र/29-07-21

श्री विनोद नारायण झा(क्रमश:): आज लोगों की जान बचाने की जरूरत है, दुनिया में महामारी आयी है और उस महामारी से मुकाबले की जरूरत है, पैसे कितने भी खर्च हों लेकिन एक भी आदमी का जीवन जाने न पावे इसलिए जितने पैसे की जरूरत है उतनी दीजिये, यदि आप संवेदनशील होते तब । ठीक है, कटौती प्रस्ताव एक प्रक्रिया है लेकिन शब्दों से तो कह ही सकते थे । मैं तो चाहता हूँ कि अपोजिशन आज एक विशेष उदाहरण पेश करता देश में, जब स्वास्थ्य विभाग का बजट आया तो कटौती प्रस्ताव के बदले विपक्ष की ओर से बढ़ोत्तरी प्रस्ताव आता

कि बजट को बढ़ा दीजिये क्योंकि जो महामारी आयी है अध्यक्ष महोदय, दुनिया ने इसकी कल्पना नहीं की थी । आज स्वास्थ्य के बजाय प्रमुख नेता कोरोना पर कंसनट्रेट कर गये हैं, स्वाभाविक भी है, जो परिस्थितियां आज दुनिया में आयी, किसी को उम्मीद थी क्या कि ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा । जब हम बोला करते थे तो कहते थे कि महामारियां, खासकर पैनडेमिक जो वर्ल्ड वाईड होती है, वह तो इतिहास की वस्तुएं हो गयी है, वह तब आती थी जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, जब स्वास्थ्य पर इतना काम नहीं हुआ था । अब तो वह इतिहास की वस्तु हो सकती है जो आज ये एक चर्चा का विषय है और शोध का विषय है । ब्रिटेन, नार्वे और अमरीका के बैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह प्राकृतिक नहीं है, ये मेन मेड है, यह लेबोरेटरी में किया गया है, बुहान के बायोलोजिकल सेंटर पर ऊंगलियां उठ रही है, इतनी बड़ी आपदा आयी इस दुनिया में, मैं एक पुरानी आपदा की कहानी इसी क्रम में पढ़ा है, वर्ष 1918 ई0 में स्पेनिस इंफ्लूंजा आया था जिसके सिम्टम्स कोरोना से मिलते जुलते थे या बराबर ही थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब हमारे सैनिक लौट रहे थे स्पेन से और मुम्बई बंदरगाह पर एक सप्ताह से ज्यादा उनको तकनीकी कारणों से रूकना पड़ा और जब बाहर निकले तो उसमें से सैंकड़ों लोग स्पेनिस इंफ्लूंजा के शिकार हो गये और जब वे लोग देश भर में अपने अपने गांव गये तो पूरे भारत में यह स्पेनिस इंफ्लूंजा फैल गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय भारत की आबादी 8 करोड़ थी और उस 8 करोड़ में जो आंकड़े आये हैं कि उस स्पेनिस इंफ्लूंजा में 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने जान गवां दी, आठ करोड़ आबादी में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान चली गयी । आज जब ये आया तो हम सावधान थे, भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सक्षम सरकार थी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सक्षम सरकार थी। महोदय, एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो हमारे दिल पर चोट पहुंचाता है, एक भी आदमी यदि बीमारी से मरे तो सबके आंखें नम होती है लेकिन जो इतना बड़ा क्राईसिस आया मानवता के खिलाफ, 100 वर्षों के बाद इतना बड़ा क्राईसिस आया, उस क्राईसिस का मुकाबला जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ भारत की सरकार और बिहार सरकार ने किया, आज तो मैं चाहता था कि बिहार विधान-सभा उनकी तारीफ करे, उनकी प्रशंसा करे और प्रस्ताव पास करे। याद कीजिये बिहार में डेथ रेट के बारे में, मैंने कहा कि एक आदमी का मरना भी हमें दुख पहुंचाता है लेकिन जो दुनिया में डेथ रेट था और बिहार जिसको गरीब और कम संसाधन वाला राज्य माना जाता है, उस राज्य में कितनी मजबूती से हमलोगों लोगों ने मुकाबला किया ।

आज मैं कृतज्ञ हूं उन कोरोना वॉरियर्स का, उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन पारा मेडिकल स्टाफों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की,जान की वाजी लगा दी और सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर उन कोरोना वॉरियर्स ने लोगों के जान बचाने का काम किया । कई बड़े बड़े डॉक्टरों की जानें गयीं । आज वक्त है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का और स्वास्थ्य बजट के दृष्टि से हम आये हैं तो जरूरत इस बात की है कि उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करें और हम मजबूती से सरकार के साथ खड़ें हों । भगवान न करे कि तीसरी लहर आये लेकिन यदि आये तो ये बताना चाहिए कि विपत्तियों में किस तरह लोगों ने कोशिश की है। विपत्तियों में किस तरह का ओपोजिशन का कर्त्तव्य बनता है और उसके अनेक इतिहास है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूॅ, आज उनको मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है लेकिन दूबे जी जो बात कर रहे थे और आप लोगों ने, ओपोजिशन पर मैं ऊंगली उठाना नहीं चाहता था लेकिन आप लोगों ने तो बाधा डालने का प्रयास किया और बाधा इस तरह डालने का प्रयास किया कि किसी तरह अराजकता पैदा हो जाय, किस तरह ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाये कि सरकार परेशान हो जाये और सरकार अक्षम हो जाये ।

( इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जब कोरोना महामारी आया और पहला लॉकडाउन लगाया गया तो उस समय हमारे यहां पी0पी0ई0किट भी नहीं बनता था, इस पर विस्तार से मंत्री जी बतायेंगे, मैं लंबी विस्तार में नहीं जाना चाहता हूॅ लेकिन ओपोजिशन ने क्या किया, आपकी संवेदनशीलता क्या थी, आपने ऐसा माहौल बनाया देश भर में कि गलत हो गया और लोग पैदल चल पड़े, किन कठिन परिस्थितियों में चल पड़े । यदि देश का राजनीतिक दल और मीडिया साथ होता और लोगों में यह माहौल बनाने की कोशिश होती कि महीने, दो महीने की बात है तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूॅ लेकिन आपकी असंवेदनशीलता के कारण परिस्थितियां बिगड़ी, आपकी असंवेदनशीलता के कारण माहौल खराब हुआ और लोग पैदल चल पड़े लेकिन मैं फिर धन्यवाद देता हूॅ बिहार की सरकार को कि बाहर से आने वाले किसी भी लोगों को, बिहार के हमारे प्रवासियों को, बिहार उनका घर है बिहार के वे वेटे है, उनको कहीं रोका नहीं, उनके खाने की, उनको रहने की इस सरकार ने सारी व्यवस्था की और आपलोग जो अराजकता पैदा करना चाहते थे, आपके मंसूबे धरे के धरे रह गये, बिहार की जनता आराम से काम करते रह गये। आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आप लोगों को भी मौका मिला है, दूबे जी से मैं पूछना चाहता हूॅ, आप वरीय सदस्य हैं, पहले बिहार में कितने

मेडिकल कॉलेज थे, आजादी के 40–50 साल के बाद भी, आप याद करिये, मुझे तो याद है कि पटना का प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज अंग्रजों ने बनाया था आजादी से पहले और दूसरा मेडिकल कॉलेज दरभंगा का जिसे दरभंगा महाराज ने 1945 ई0 1946 ई0 में 300 एकड़ जमीन देकर प्रारम्भ की और आप कितने बनाने में सफल हुए । आप जरा एक बार इसको देख लीजिये, ये बिहार है और आज 2011 की जनगणना में यह ज्यादा घनत्व वाले राज्य हैं प्रतिवर्ग कि0मी0 में, यहां इतनी बड़ी आबादी है, इतने कम जमीन में इतनी बड़ी आबादी..

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य,अब कंक्लूड किया जाय ।

श्री विनोद नारायण झाः अभी तो मेरा बहुत समय होगा, मैं तो आराम से बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2–3 दरभंगा, भागलपुर को छोड़ दीजिये, भागलपुर, वेतिया छोड़ दीजिये, वह सरकारी मेडिकल कॉलेज है जितने भी मेडिकल कॉलेज हों, मुजफ्फरपुर का हो, नालांदा का हो, बोध गया का हो ये प्राइवेट लोगों ने खोली थी, आप धन्यवाद दीजिये कि यहां डबल इंजन की सरकार हुई और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु जी के नेतृत्व में एक दर्जन मेडिकल कॉलेज में आज सरकार की ओर से काम हो रहा है । आपने क्या किया, तीन मेडिकल कॉलेज 70 सालों में और हमारा 15 सालों का रेकर्ड देखिये, इतना ही नहीं, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, पारा मेडिकल कॉलेज हो, हर जिला में नर्सिंग कॉलेज हो, मैं तो पूरी तैयारी में था, मुझे बताया गया था आपको लंबा बोलना है लेकिन कोई हर्ज नहीं है, इतना ही काफी है, बहन बोल रही थी मोहनियां की विधायिका, मैं आपको याद दिलाता हूँ आप यह भी पढ़ लीजिये कि 2005 से यहां पहले मृत्यु दर क्या थी, आप ही आंकड़े भी ले आईए कि शिशू मृत्यु दर क्या थी और आज क्या है, पूरे बिहार में टीकाकरण जो सिर्फ 11 प्रतिशत था , महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिए अस्पताल में नहीं आती थी और मौत के शिकार हो जाती थी...

उपाध्यक्षः आपका समय हो गया है माननीय सदस्य,बैठ जायें।

टर्न–18/मधुप/29.07.2021

उपाध्यक्ष : डॉ0 संजीव कुमार जी ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचेतक महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ । आज मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका मिला है ।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि बिहार में आज से 15 साल पहले प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलाकर मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे और आज माननीय मुख्यमंत्री की देन है, यह भाजपा-जदयू सरकार की देन है कि आज हमारे बिहार में 25 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं और 3 मेडिकल कॉलेज जमुई, बेगुसराय और बक्सर में भी जल्द बनकर तैयार हो जायेंगे । मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज से 15 साल पहले स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति थी ? पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं था और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, लगभग हरेक प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का बिल्डिंग बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो कि प्राइवेट हॉस्पीटल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ । आपलोग देख सकते हैं । उसके बाद महीने में जहाँ 30 मरीज नहीं आते थे और आज के दिन में ओ0पी0डी0 में 10 हजार मरीज हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आते हैं, यह देखा जा सकता है और सिर्फ आते ही नहीं हैं बल्कि मरीज का इलाज भी होता है और उनको प्रोपर दवाईयाँ भी दी जाती हैं, डिजिटल एक्स-रे की भी व्यवस्था है, पैथोलोजी की जाँच भी होती है । हर अस्पताल में डॉक्टर एवं नर्स भी हैं, भले कमी थोड़ी है लेकिन उसकी भी बहाली हो रही है, मैं यह भी बता रहा हूँ आप लोगों को । सबसे बड़ी बात कि बिहार में 18 सदर अस्पताल में सी0टी0 स्कैन की सुविधा शुरू हो चुकी है और बाकी में भी हरेक सदर जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन लग रही है । (व्यवधान) उसके बाद 35 अनुमंडल में ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 का प्रशिक्षण संस्थान बन चुका है और उसके बाद पैरामेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो रही है हरेक अनुमंडल में । अभी बहुत महत्वपूर्ण है जो माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी की देन है कि अभी से 15 महीने में हरेक विधान सभा क्षेत्र में आपको 5 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर बनने जा रहा है और एक एडीशनल पी0एच0सी0 का निर्माण आज से 15 महीने में शुरू हो जायेगा जिसके निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई है । मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी परबत्ता के पूर्व विधायक आर0एन0 सिंह जी के अनुरोध पर वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल गोगरी जमालपुर में बनाने का कार्य जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है और हमारे विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी उपलब्ध है, मैं आग्रह करता हूँ कि हर जिला में जब आप मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं तो खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज दिया जाय । मेरा यह आग्रह है ।

सबसे प्रोब्लेम यह है, मैं मानता हूँ कि कुछ विपक्ष के साथी ने बात सही कहा है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स हैं लेकिन टेक्निसियन्स नहीं हैं । खगड़िया

में भी यही हुआ  कोरोना में कि हमारे पास 8-8 वेंटिलेटर्स हैं लेकिन टेक्निसियन्स नहीं हैं । हमारे यहाँ एनेस्थेसिस्ट नहीं हैं तो मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था (व्यवधान) मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कोरोना का डेथ हुआ है, अगर हमारे पास एनेस्थेसिस्ट रहते, हमारे पास सदर अस्पताल में हमलोगों के यहाँ वेंटिलेटर्स अनयूज्ड रह गया, नहीं तो डेफनेटली कोरोना में जो मरीज मरे हैं, कम मरीज मरते और यह हमारे लिए अच्छा रहता, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा रहता ।

पिछली बार मुझे बजट सेशन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में बोलने का मौका मिला था तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि हमारा एन0एम0सी0एच0 है, बिहार में पटना आते हैं लोग इलाज के लिए और एन0एम0सी0एच0 का मेडिकल डिपार्टमेंट हर बार बारिश में डूब जाता है । कम से कम मेडिकल डिपार्टमेंट का आई0सी0यू0 बनना चाहिए । उस वक्त भी प्रधान सचिव जी से कहीं पर मेरी मुलाकाल हुई थी तो बोले थे कि हमने हर चीज पेन-डाउन किया है । प्रधान सचिव महोदय, आप जो पेन-डाउन करते हैं, अभी तक डाउन ही रह गया है, थोड़ा इसमें आगे बढ़ना भी चाहिए । मैंने उस वक्त भी कहा था कि एन0एम0सी0एच0 में कौपलियर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है, उसको शुरू करना चाहिए । 3-4 ऑडियोमेट्रिस्ट को वहाँ पर बहाली नहीं करने के कारण हियरिंग टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है । उस वक्त भी कहा गया था कि हाँ हो जायेगा लेकिन चार महीना हो गया है, अभी तक नहीं किया गया है । लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द शुरू हो जायेगा ।

महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार के सेशन में जो हुआ, मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार चिकित्सा क्षेत्र में अब आगे जायेगा क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना हो चुकी है । सारे मेडिकल कॉलेजेज अब इससे एफिलिएटेड होंगे और इसी तरह मैं महाराष्ट्र मुम्बई में पढ़ा हूँ, वहाँ पर भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक में है जो 20 साल पहले स्थापित हो चुका था । बिहार में भी अब हो गया है, इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहता हूँ ।

एक और महत्वपूर्ण बात, अब कोरोना की बात आ रही है । पिछली लहर में कोरोना उतना एग्रेसिव नहीं था लेकिन इस बार जो कोरोना हुआ, सभी लोगों ने अपनों को खोया है । नो डाउट, सब लोगों को दर्द है । बात भी सही है, कुछ खामियाँ हममें भी थी । मैं यह नहीं कहता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिसके कारण, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, नो डाउट । मैंने खुद अपने

रिलेटिव के लिए 25 हजार में एक सिलेंडर खरीदा था लेकिन कालाबाजारी पर तुरंत, एक दिन ऐसी घटना घटी और उसके बाद कालाबाजारी जो कर रहे थे, उसपर तुरंत कार्रवाई हुई । मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ । रेमडेसिविर की बात हुई, मैं इसपर आपलोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग सुनें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में रेमडेसिविर की किल्लत थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे एक-एक सदर हॉस्पीटल में सरप्लस रेमडेसिविर रहा, जो कि आज एक्सपायर भी कर रहा है । मैं कम से कम 100 मरीजों को सदर हॉस्पीटल में अलग-अलग जिलों में रेमडेसिविर दिलवाया जिस समय देश में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था । फ्री में लोगों को रेमडेसिविर मिला है, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए । अभी से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोरोना को हमलोग एवॉयड करेंगे, हमलोग कहते हैं कि प्रीवेंशन इज बेटर दैन क्योर लेकिन आपलोग कहते हैं कि यहाँ बिहार में मौतें हुईं, भारत में इतनी मौतें हुईं, हमलोगों से तो बहुत आगे था ब्राजिल, यू0एस0, इंगलैंड, वहाँ क्यों मौतें हुईं । यह बीमारी ही ऐसी थी कि इसका कोई इलाज अभी तक नहीं हो पाया है । बात को समझिए, खाली हाथ उठाने से नहीं होगा । समझने की बात है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है कि आये-दिन म्यूटेट करते जाता है, वैक्सीन भी हमलोग ले लिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमलोग सेफ हो गए, वैक्सीन वायरोलेंस को कम करेगा, हमलोगों को प्रीवेंशन इज बेटर दैन क्योर, इसी रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा । लेकिन अभी मैं देखकर आया हूँ, हरेक जिला में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है बिहार सरकार द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा । यह बहुत गर्व की बात है कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली है, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ अपनी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से । हरेक जिला में ऑक्सीजन प्लांट बन गया है और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी । बस मेरा आग्रह है कि हरेक जिला के आई0सी0यू0 को विधिवत चालू कर दिया जाय एक महीना के अन्दर नहीं तो तीसरी लहर आयेगी और फिर वही पुरानी कहानी होगी कि वेटिलेटर है लेकिन टेक्निसियन नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें कि वेंटिलेटर टेक्निसियन, एनेस्थेसिस्ट की हर जिला अस्पताल में बहाली हो जानी चाहिए । हमारा लक्ष्य है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का, जो कि बहुत तेजी से ड्राइव चल रहा है, इसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ । हर जगह डेडिकेटेड कोविड हॉस्पीटल भी बन गया है, वार्ड भी हर जिला में बन गया है कि अगर तीसरी लहर बहुत

आयी भी तो हमलोग उसका सामना डटकर करेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, अगर हुआ भी तो हमलोग इस लड़ाई को अच्छे से जीतेंगे । मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जितनी भी कोरोना से मृत्यु हुई थी, सभी के परिजन को 4-4 लाख रूपये की जो राशि दी जा रही है, बहुत राहत उनके परिजनों को हो रही है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । अंत में बस यही कहना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लुड किया जाय ।

डॉ0 संजीव कुमार : तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित,
चाहता हूं बिहार की धरती तुझे कुछ और भी दूँ ।
जय हिन्द ! धन्यवाद ।

टर्न-19/आजाद/29.07.2021

श्री भारत भूषण मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से जो पैसे की मांग की जा रही है, भाईयों जरा शांति बनाये रखेंगे तो मुझे बात रखने में सुविधा होगी, नहीं तो ध्यान बंट जाता है ।

मित्रों, मैं आपसे बता रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से पैसे मांगे जा रहे हैं, यह पूरी तरह से अनुचित है, इसमें कोई न्यायसंगत बात नहीं है । बिहार में दूसरे कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे बिहार में कहीं कोई हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा था । कहीं पर लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग स्वास्थ्य सुविधा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग डॉक्टर नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं, कहीं लोग वेन्टीलेटर नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं और कहीं लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं तो फिर किस बात के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है । कोई औचित्य तो दिखना चाहिए, कोई तर्कसंगत बात दिखनी चाहिए । हमको पूरी तरह याद है कि कोरोना काल में बिहार में जैसी स्वास्थ्य विभाग में कुव्यवस्था थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसकी मिसाल इस देश में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है । पूरा स्वास्थ्य विभाग लगता था कि दम तोड़ चुका है । कहीं लोग जा रहे थे, प्राइवेट होस्पीटल में चूँकि सरकारी होस्पीटलों में कोई व्यवस्था थी ही नहीं । सरकारी होस्पीटल में जाने पर वहां के डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि हमारे यहां ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहां वेन्टीलेटर नहीं है, अगर है तो उसको कोई चलाने वाला नहीं है । आप प्राइवेट होस्पीटल में चले जाइए और प्राइवेट होस्पीटल

ने जिस प्रकार से गरीब लोगों को उस कोरोना काल में लूटा, वह अद्‌भूत नजारा देखने को मिला । लोग धन सम्पत्ति, जमीन–जायदाद जो कुछ भी उसके पास पैसा बचा हुआ था, वह सारा लगा दिया लेकिन उसका परिजन नहीं बचा । यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल । इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ जैसे लगता है कि इस सुशासन बाबू के पास कोई सुव्यवस्थित प्लानिंग ही नहीं है । आखिर डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं की जाती है, नर्सों की बहाली क्यों नहीं की जाती है, पारा–मेडिकल स्टाफ की बहाली क्यों नहीं की जाती है, स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्तियां हैं और अनुकूल अनुपात में डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो इस तरह से मौतें हुई हैं, वह नहीं हुआ होता । इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी रिक्तियां हैं, उनको जल्दी भरा जाय ताकि असमय में किसी की जिन्दगी न जाय ।

महोदय, जहां तक स्वास्थ्य विभाग के दूसरे जो क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो पी0एच0सी0 है, जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, वहां क्या हो रहा है, आप जाकर देखिए । मैं मधुबनी जिला के लौकहा से आता हूँ और अखबारों में भी बात बहुत प्रमुखता से आयी है कि सदर होस्पीटल में बेड पर कुत्ता सो रहा है, सदर होस्पीटल में बैल और गाय बैठा हुआ है और स्वास्थ्य उप केन्द्रों में भूंसा भरा हुआ है, स्वास्थ्य उप केन्द्रों में बकरी बांधी हुई है । यह कौन सा विभाग है, मंत्री क्या कर रहे हैं, यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, जबकि रोज अखबारों में यह खबरें आ रही है, रोज प्रमुखता से यह खबर आ रही है लेकिन उसके बाद भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है । आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है ? इसीलिए मित्रों, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि आपको ठीक से स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा, ठीक से उसकी व्यवस्था करनी होगी तभी जाकर स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा । बिहार पहले से गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मर रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से यह मंत्रालय ही बीमार है । इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पैसे की मांग की जा रही है, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है । दूसरी बातें जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में आया । अभी हम मधुबनी सिविल सर्जन से पूछ रहे हैं, वे बता रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आखिर वैक्सीन नहीं मिलेगा तो हमलोग कोरोना के तीसरी लहर से बिहार के लोगों की कैसे जान बचायी जायेगी ? सिर्फ ढिढ़ोरा पीटा जा रहा है और वैक्सीन की उपलब्धता का हवाला दिया जाता है लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत है । अगर समय रहते वैक्सीन उपलब्ध कराकर के लोगों की जान नहीं बचायी गयी,

इसपर सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया गया तो फिर से तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई तैयारी इनकी नहीं है तीसरी लहर की । कहां गया ऑक्सीजन, क्या व्यवस्था है ऑक्सीजन का, टेकनिसियन कहां है । टेकनिसियन के अभाव में अधिकतर मौतें हुई हैं । इसीलिए मैं इस विभाग से प्रश्न कर रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप अधिक ध्यान केन्द्रीत करके जो स्वास्थ्य विभाग में कुव्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, उसको दुरूस्त करने के दिशा में जरूरी कदम, जरूरी तैयारी शुरू करें ।

दूसरा सवाल जो स्वास्थ्य विभाग से है, जो हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार का आलम कि स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार है । बिहार में तो भ्रष्टाचार है ही लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जैसा भ्रष्टाचार है, वैसा तो किसी विभाग में देखने को नहीं मिल रहा है । पैसा क्यों चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए, पैसा क्यों चाहिए, माल बनाने के लिए । इसीलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विभाग पैसों की मांग करता है तो ईमानदारी से उसको खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यह महकमा पूरी तरह से एकदम कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है । इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो मांग है, इसका कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, जब तक आप व्यवस्था को दुरूस्त नहीं करेंगे तब तक सरकार को पैसा मांगने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है । इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर जो अनुपूरक बजट लाया गया है, उसके पक्ष में और विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसपर मुझे बोलने के लिए जो समय दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

स्वास्थ्य जो अभी-अभी कोरोना महामारी आया था, यह कोई पहली बार नहीं है । इससे पहले भी देश में कई महामारी आयी और सफलतापूर्वक उसपर विजय प्राप्त किया गया था । कोरोना महामारी के समय जिस समय डॉक्टरों का पीक मौसम हुआ करता था, एक अभिशाप के कारण कई वरदान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया । उस समय ग्रामीण चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लोग काढ़ा पी-पी करके अपने स्वास्थ्य को बचाने का काम किया । विपक्ष जो कटौती प्रस्तावी लायी है, विपक्ष को लालच शब्द को थोड़ा छोटा करना चाहिए और सरकार जो स्वास्थ्य विभाग पर अनुपूरक बजट लायी है उसके पक्ष में अपनी बात को रखनी चाहिए । 1946 में जब दरभंगा महाराज के द्वारा मेडिकल चिकित्सा स्थापित किया

गया था, उसके बाद अभी तक बिहार में सरकारी क्षेत्र में कुछ इने-गिने चिकित्सा महाविद्यालय थे । आज सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कई विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं । एक से एक दरभंगा में विवेकानंद कैंसर होस्पीटल हो या एम्स का दूसरा संस्थान स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा जमीन आवंटित कर दिया गया है । स्वस्थ्य भारत की ओर जब स्वस्थ्य ही न हो, ज्ञान स्वयं प्रकट नहीं हो सकता, कला प्रदर्शित नहीं की जा सकती, शक्ति लड़ नहीं सकती, धन व्यर्थ हो जाता है और बुद्धि काम करना बन्द कर देता है, इसके लिए जीवन का अभिन्न अंग स्वास्थ्य जिसके लिए पूरक बजट सरकार के द्वारा लायी गयी है, उसके पक्ष में विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक दौर था जब 6 दिनों के अन्तराल में महामारी के कारण 41 शिशुओं का मौत हो गया था । उस समय मधुमेह के बारे में पहला रोगी को खोजा गया था । आज जीवन स्तर इस कद्र स्वास्थ्य महकमा के कारण बढ़ा है, जिसके कारण एक परिवार में 6-6 पीढ़ी के लोग रहते हैं । आज बिहार में इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकॉर्ड प्रणाली विकसित किया जा रहा है । जहां पर 40 प्रतिशत चिकित्साकर्मी अस्पताल से बाहर रहा करते थे, वही पर सरकार एक एक्ट लाकर के नीतीश सरकार की देन है कि जिसमें यह एक्ट लाया गया ..... क्रमशः .....

टर्न-20/ज्योति/29-07-2021

क्रमशः

श्री बीरेन्द्र कुमार : जिसके कारण शत प्रतिशत चिकित्साकर्मी अस्पताल में आने का काम किये । उस ऐक्ट की देन है । आजादी के बाद आजतक किसी सरकार ने उतनी हिम्मत नहीं की थी जो उस ऐक्ट को सदन में लाने का काम किया । वह काम माननीय नीतीश जी की सरकार की देन थी जो उस ऐक्ट को लाकर सरकारी चिकित्सालय में शत प्रतिशत डॉक्टरों की भागीदारी सुनिश्चित की । आज देन है, उनकी भागीदारी हो रही है जिसके कारण निजी क्षेत्र में लोग उपचार के लिए नहीं जाते हैं और प्रायः लोग सरकारी अस्पताल में अपना उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं जिसका परिणाम है महामारी के दौर में भी मृत्यु दर निकाल कर देखा जाय तो सरकारी चिकित्सालय और निजी चिकित्सालय में बहुत का अंतर है । एक से एक माननीय सदस्य सरकारी

चिकित्सालय में कोरोना के पीरियड में अपना उपचार कराने के लिए पहुंचे थे । ऐसा हमलोगों के सामने दृश्य दिखा करता था । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के साथ साथ मान्यता प्राप्त आशा बहु का योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है जिसके कारण नौनीहाल जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु दर बहुत घटी है उसमें स्वास्थ्य महकमा का बहुत बड़ा योगदान है । इन सब बातों को देखते हुए विपक्ष को चाहिए था कि पूरक बजट का समर्थन करना । रही थाली बजाने की बात या दीप जलाने की बात तो यह जन जागरण के लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ है । आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में जब माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महामारी के प्रति जो जागरुकता फैलायी गयी तीस सालों तक लोकतांत्रिक पद पर आसीन रहने के बाद भी, उनके दरवाजे तक सत्ता की आहट नहीं गयी जिसका परिणाम है उनकी आवाज 140 करोड़ लोग सुनने का काम किए और आसानी से कोरोना को दूर भगाने का काम किये । आज वह जागरुकता नहीं फैलायी जाती और यह जागरुकता नयी बात नहीं है जब आकाल पड़ा था देश के दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब बोले थे जो हम एक दिन भूखा रहेंगे तो विदेश का लाखों क्वींटल मीट्रिक टन गेहूँ सड़ जायेगा जिसके कारण हरित क्रांति स्थापित हुई और वह जागरुकता देश में कोई दूसरा व्यक्ति लाने का काम किया तो देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी लाये और उस जागरुकता का परिणाम था जो कोरोना का अभिशाप देखने को मिला था उसका शत प्रतिशत आंकड़ा अपने देश में बहुत कम रहा । चाहे वैक्सिनेशन की बात हो ।

(व्यवधान)

आप 15 साल तक विपक्ष के बंधुओं जिसके कारण सड़कों में गढ्ढा नहीं गढ्ढा में सड़क दिखा करती थी और आप लोग प्रायः चर्चा करते थे जो लाठी कटवाओ और तेल पिलाओ वह दिन समाप्त हो गया बंधुओं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की तरफ देखिये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज है । 5 निजी क्षेत्र में है । वेक्सिनेशन की जो बात है बिहार में 1 करोड़ 96 लाख 4 हजार 256 लोगों को प्रथम चरण का डोज दिया जा चुका है और कुल 36 लाख 65 हजार 854 वैक्सिन का दूसरा डोज लोगों को पड़ चुका है । इसके लिए सरकार के जो लोग हैं गांव गांव तक जागरुकता फैला रहे हैं और विपक्ष भ्रामक स्थिति पैदा किया ।

उपाध्यक्ष : अब कनक्लुड किया जाय माननीय सदस्य ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : भ्रम फैलाया जा रहा था कि वैक्सिन लेने से मर जाते हैं और चोरी छिपे वैक्सिन लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो या सदर अस्पताल हो वहाँ पहुंचने का काम करते हैं । कुल वैक्सिन 2 करोड़ 32 लाख 70 हजार 110 लोगों को वैक्सिन सरकार द्वारा लगायी जा चुकी है । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ।

श्री सुदामा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, कोरोना महामारी ने पूरे बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल करके रख दी । अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी, नर्सेज की कमी, बेड की कमी, वेंटीलेटर की कमी, दवा की कमी, ऑक्सिजन की कमी से असंख्य मरीजों की मौत हो गयी तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि पहले तो अपनी कमियों को शिनाख्त कीजिये इसके बाद और पैसा जितना हो ले लीजिये । कमी नहीं जानेंगे तो आप सही प्रबंध भी नहीं कर सकते हैं । महोदय, हॉस्पिटल में ऐसे हजारों मरीजों की मौत हुई जिनका कोविड का इलाज चला, ऑक्सिजन का सिलिंडर लगा लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने कोविड की जॉच नहीं करायी । एक छोटा उदाहरण जानने के लिए काफी है । 4 मई को आरा सदर अस्पताल में प्रतापपुर के परशुराम सिंह को ऐडमिड कराया गया और उनको कोविड था और कोविड का इलाज चला, सब है पुर्जा और ऑक्सिजन भी लगा और उनकी मृत्यु 11 मई को हो गयी लेकिन जेल प्रशाासन ने उनके कोविड की जॉच नहीं करायी थी । सर्टिफिकेट नहीं दिया कि कोविड से मृत्यु हुई है । हमलोगों ने यहाँ स्वास्थ्य विभाग में तारांकित प्रश्न डाला तब जा कर उनको सर्टिफिकेट मिला । यह एक उदाहरण है । ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने गंवई डॉक्टरों से इलाज कराया । असंख्य लोगो की मृत्यु हुई है कोविड से भी और ओ.पी.डी. बंद रहने के कारण दूसरी बीमारियों से भी और हमारी सरकार से मांग है कि आप जॉच टीम गठित कीजिये और ईमानदारीपूर्वक जॉच कराईये आपको दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जायेगा । हमलोगों ने एक महीने तक कठिन कठोर मेहनत करके 9 जिलों की एक रिपोर्ट तैयार की है । भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना ग्रामीण, सिवान, दरभंगा और पश्चिम चंपारण के 66 प्रखंडों की जॉच हुई । 515 पंचायतों में गांव हैं 1,693 । और 7,200 लोगों की मृत्यु हुई

जो हमलोगों को रिपोर्ट मिली जिसमें से 6,420 वह कोविड से मरे और 780 दूसरी बीमारियों से तो यह मात्र 1693 गांवों की रिपोर्ट है । 50 हजार के लगभग गांव हैं बिहार में तो औसत निकाला जाय तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है । पहले इस तथ्य को सरकार कबूल करे इसके बाद जो है अन्य चीजों पर चर्चा करे । हमने यह सुबह में रखा था यह मौत का बण्डल है । 7,200 लोगों की मौत हो गयी जिनकी सरकार की आपराधिक लापरवाही से जो इलाज में बरती गयी उन लोगों की यह रिपोर्ट है और आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करुंगा कि इसे आप ग्रहण कीजिये । आप इसे ग्रहण कीजिये और यह जो है रिपोर्ट है इसको प्रोसिडिंग्स में शामिल किया जाय और जॉच कराईये और अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो हमलोग उसको दुरुस्त करेंगे । अब आया जाय महोदय, सरकार का स्वास्थ्य बजट था वित्तीय वर्ष 2021-22 का 13,464 करोड़ का और इसके अतिरिक्त इनको मिला इस काल में 4100 करोड़ । सब मिला कर हो गया 17,564 करोड़ इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विधायकों से दो दो करोड़ लेंगे ।

क्रमशः

टर्न-21/पुलकित-अभिनीत/29.07.2021

क्रमशः

श्री सुदामा प्रसाद : तो यह पैसा कहां खर्च हो रहा है आकाश में खर्च हो रहा है कि पताल में खर्च हो रहा है । यह कहां खर्च हो रहा है ? यह हमलोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है । पिछले साल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि अपने इलाके में, अपने तरारी विधान सभा में हम सेनेटाइजर, मास्क, दवा और साबुन का वितरण करना चाहते हैं, हमको 50 लाख खर्च करने की इजाजत दीजिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी इजाजत नहीं दी और उल्टे हर विधायक से 50-50 लाख रुपया काट लिया गया । इस बार भी हमने 3 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है दिन में कि हमको एक करोड़ रुपया सहार, तरारी और पीरो के अस्पताल में बेड पर, ऑक्सीजन सिलेण्डर पर, एम्बुलेंस पर खर्च करने के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन नहीं शाम को तीन मई को ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गयी कि हर विधायक के कोटे से दो-दो करोड़ रुपया लिया जायेगा और ले लिया गया, लेकिन यह पैसा कहां खर्च होगा कम-से-कम हमलोगों को तो बताया जाय । हमलोगों को तो यह अधिकार दिया जाय कि हम कह सकें कि हमारे हॉस्पिटल में

इन चीजों की जरूरत है । मेरा यह सुझाव है कि अभी डी0डी0सी0 की अध्यक्षता में जो स्वास्थ्य सामाग्री क्रय समितियां बनायी जा रही हैं उसमें माननीय विधायकों को भी शामिल किया जाय ।

महोदय, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना से तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां के मुख्य सचिव की मृत्यु हुई, माननीय पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी जी की मृत्यु हुई, जब ऐसे हाई-प्रोफाइल लोगों को इलाज नहीं मिला तो आप आम लोगों को क्या इलाज दे रहे हैं ? इससे तो पता चल रहा है, यह तथ्य है महोदय, इसलिए सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि हां ऑसीजन के, सभी जितने माननीय विधायक बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के अप्रील के लास्ट वीक में और भर मई कोई सोया नहीं है रात में बढ़िया से । दिल पर हाथ रखकर कहिए, ठीक है आप सत्ता पक्ष के हैं, रिपोर्ट यह आता था कि नहीं कि सिलेण्डर का अभाव है, ऑक्सीजन नहीं है, सो नहीं पाते थे और खून के आंसू रोये हैं हमलोग । खून के आंसू रोये हैं और सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई । आप सबसे पहले अपनी कमी नहीं सुधारिएगा तो स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां हैं उनको दुरूस्त कैसे कीजिएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है तो इसको स्वीकार किया जाय पहली मांग ।

दूसरी बात, हमलोग शुरू से ही जोर दे रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकरण कीजिए । जो आपके स्वास्थ्य उप केंद्र हैं गांवों में वहां इलाज नहीं हो रहा है, साथी ने ठीक ही कहा कि वहां भूसा रखा जा रहा है, गोईठा पाथा हुआ है । 99 प्रतिशत स्वास्थ्य उप केंद्रों की यही स्थिति है, इनको आप चालू कीजिए और प्रखंडों में पी0एच0सी0 की जो सुविधाएं हैं उनको वहां बहाल कीजिए गांवों में जहां स्वास्थ्य उप केंद्र हैं और सदर अस्पताल की सुविधा आप पी0एच0सी0 ब्लॉक में दीजिए तथा पी0एम0सी0एच0 में जो सुविधाएं हैं उसको आप सदर अस्पताल में दीजिए । ऐसा करेंगे तभी पटना पर लोड घटेगा, पटना पी0एम0सी0एच0 पर लोड घटेगा । नहीं तो अफरा-तफरी, मरीज नीचे सोये हुए हैं, नीचे भी जगह नहीं मिल रही है, यह स्थिति थी और पूरा कहा जाय कि अराजकता का माहौल था । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि...

उपाध्यक्ष : अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : बस-बस कंक्लूड कर रहे हैं सर । महोदय, कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से पूरा कहा जाय कि आम आदमी की कमर टूट गयी है । चाहे किसान हों, मजदूर हों, दुकानदार हों सबकी हालत खराब हो गयी है, सबकी

कोरोना काल में जमा पूंजी टूट गयी, लेकिन इसी कोरोना काल में गौतम अदाणी की पूंजी एक साल में 2 लाख 40 हजार करोड़ बढ़ गयी । क्या जादू है भाई ? आम आदमी की पूंजी टूट गयी और उनकी पूंजी बढ़ गयी तो हमारी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि आप शहर, देहात में हर परिवार को 25 हजार रुपये का मुआवजा दीजिए, हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज दीजिए और मनरेगा सरीखी योजनाओं को शहर और गावों में आप पारदर्शी तरीके से युद्धस्तर पर चलाइये । हमारे जिले में 39 दिन में 39 करोड़ रुपया खर्च हो गया अप्रील और मई में । 39 करोड़ का लिस्ट मांग रहे हैं हम तीनों प्रखंडों में पी0ओ0 से कि भाई कहां योजना चली है हमको लिस्ट दीजिए, लेकिन कोई लिस्ट नहीं दे रहा है । क्या तमाशा है? यह कागज पर काम चल रहा है मनरेगा का भी तो यह मेरा सुझाव है और इसके बाद जो है..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : एक मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, अभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाप के जो सृजित पद हैं और खाली हैं उनको तत्काल आप एक महीना के अंदर भरिए और जो आशा कर्मी हैं, ममता हैं, सफाई कर्मी हैं, एम्बुलेंस ड्राईवर हैं उनको आप स्थायी कीजिए और कम-से-कम 18 हजार रुपया का उनको महीना दीजिए । इसके साथ आउटसोर्सिंग का धंधा बंद हो, आउटसोर्सिंग की आड़ में हजारों-करोड़ों रुपये की लूट हर महीने बिहार में हो रही है, आम जनता का पैसा, इसको बंद किया जाना चाहिये और दवाओं की कलाबाजारी पर जो है वह बहुत हुआ, जो मुआवजा की मांग हमने किया चाहे वे कोरोना से मरे हों या बिना करोना के दूसरी बीमारी से मरे हैं सबको बिना भेदभाव के चार लाख रुपया सरकार मुआवजा दे । एक मामला आया पारस हॉस्पिटल का...

उपाध्यक्ष: समाप्त किया जाय माननीय सदस्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : बस खत्म कर रहे हैं महोदय, एक मिनट । महोदय, पारस अस्पताल में एक महिला पीयूष विश्वकर्मा की मृत्यु 7 मई को हुई । पूरा पैसा लिया गया महोदय लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिली तो यह बात है अंत में कि सत्ता पक्ष के साथी...

उपाध्यक्ष : श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, एक मिनट ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्तावित प्रथम अनुपूरक व्यय के संबंध में चर्चा सदन के समक्ष रखना चाहती हूं । अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय के संबंध में बोलने से पहले मैं स्वास्थ्य विभाग के

मंत्री श्री मंगल पाण्डेय जी, एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इनके प्रयासों से पिछले एवं इस वर्ष विकट कोरोना रूपी स्वास्थ्य समस्यों को दृढ़ इच्छा शक्ति से एवं सुनियोजित कार्यक्रम के द्वारा लगभग 12 करोड़ जनता के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किये गयें । महोदय, राज्य की जनता की स्वास्थ्य समस्याओं के त्वरित निदान हेतु प्रथम अनुपूरक व्यय 3673 करोड़ 99 लाख 40 हजार रूपये किये हैं । इस राशि से स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी मदों में व्यय करने का प्रावधान किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष महीनों में स्वास्थ्य संबंधित विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री शमीम अहमद ।

श्री शमीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाये गये अनुपूरक बजट के विपक्ष में बोलने के लिए आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का । आज से मात्र चार दिन पहले इसी सदन में हमलोगों ने शोक सभा की और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे माननीय सदस्य खड़े हुए थे और इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए थी, सभी को यह जानकारी है कि इतनी लम्बी फेहरिस्त इस विधान सभा में पहले कभी नहीं हुई थी । इसका असल ये दर्शाता है कि ये सरकार स्वास्थ्य के मामले में फेलयर है । आज जिस तरह से महामारी में, बिहार सरकार में जितने भी हमारे विधायक जीतकर के आते हैं । कोई यहां प्लानिंग नहीं बन पाती । सारे विधायक जो इलेक्शन लड़कर आते हैं । साढ़े तीन-तीन लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके उनके बीच से चुने जाते हैं । इन सभी में कुछ न कुछ कैलिबर है, तभी तो लोगों ने विधान सभा में भेजा, लेकिन इनके बारे में इनसे कोई भी सलाह-मशविरा नहीं लिया जाता और बैठकर के योजना बना दी जाती है ।

(क्रमशः)

टर्न-22/हेमन्त-धिरेन्द्र/29.07.2021

क्रमशः...

श्री शमीम अहमद : ऐसी योजना से हम कैसे बिहार की तरक्की कर सकते हैं । सारे विधायक का, सारे क्षेत्र का मसला अलग-अलग है लेकिन किसी की जानकारी लिये बिना हम योजना बना देते हैं । आज हमारे पूर्वजों ने, ऋषि-मुनियों ने लिखा है कि

''समदोषः समाग्निश्च समधातुमल क्रियः
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ।''

मनुष्य के, इंसान के जिस्म में जब ये सारे गुण पाये जाते हैं वैसे आदमी को हम स्वस्थ कहते हैं । आज जिस तरह की महामारी हुई, मैं सदन के सामने, अपने स्वास्थ्य मंत्री के सामने, हमारे इंसान के पास शरीर पर कितने बाल होते हैं एक बाल मैं स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखता हूं और पूरा बजट देता हूं उनको कि आप किसी वैज्ञानिक को बुलाकर इसी विधान सभा में उसको आप जुड़वा दें । इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो आपको जिम्मेदार बनना चाहिए था । आपको पैसा किसलिए दिया जाय ? लोगों को ऑक्सीजन नहीं देने के लिए, बिहार को शर्मसार करने के लिए । एक महिला ने अपने पति को माऊथ टू माऊथ रेस्पिरेशन देने के लिए, एक मां ने अपने बेटे को माऊथ टू माऊथ रेस्पिरेशन देने के लिए, इसी के लिए आपको पैसा दिया जाय ? क्या इसी के लिए आपको पैसा दिया जाय कि एक मामूली ऑक्सीमटर जो मात्र दो से ढ़ाई हजार में मिलता है, इस बिहार में नहीं मिल पाता है । क्या इसी के लिए पैसा दिया जाय कि कहीं पर वेंटिलेटर है लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए आदमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है । मेरा मानना है कि यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चली गयी है और वेंटिलेटर चलाने वाले ही हमारे सुस्त पड़े हुए हैं । आज किसलिए आपको पैसा दिया जाय कि बिहार को केंद्रित कर रहे हैं सिर्फ पी.एम.सी. एच., आई.जी.आई.एम.एस. और एम्स । क्या और जगह जाकर डॉक्टर ईलाज नहीं कर सकते ? आप पूरे सदर हॉस्पिटल को सुदृढ़ नहीं बनाते । अगर सभी जगह सदर हॉस्पिटल सुचारू ढंग से हो जाते तो पूरे बिहार की लूट पटना में नहीं पड़ती । हर जगह बीमार लोग अगर 6-6 घंटे, 7-7 घंटे एम्बुलेंस से आना पड़ता है तो क्या उसकी लाइफ बच सकती थी । अगर सदर हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर दें, वहां डॉक्टर की व्यवस्था कर दें, वहां स्टाफ की व्यवस्था कर दें, वहां नर्स की व्यवस्था कर दें यह आप कर देते । आज पैसा किसलिए आपको दिया जाय ? जिस तरह का टेस्ट यहां मिला, आर.टी.पी.सी.आर. करना चाहिए था, आपने रेपिड टेस्ट करके कितनों की जिंदगियां ले गये । इस विधान सभा के कई माननीय सदस्य और विधान परिषद् के भी माननीय वर्तमान सदस्य चले गये, पूर्व में जो गये सो गये और तीसरी लहर आने वाली है । अगर इस तरह की लापरवाही रही तो अगले सत्र में हम लोगों में से कितने रहें या नहीं रहें लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर सतर्क हों । अगर विपक्ष की जहां भी भूमिका, आपको मदद की जरूरत है तो आप कहिये हम लोग तैयार हैं, पूरे विधायक एक तरफ से, पक्ष हो या विपक्ष हो जहां भी जरूरत है । आप चलिये पूरे बिहार में दौरा करिये पूरे ए. पी.एच.सी. को देखिये, पूरे पी.एच.सी. को देखिये, सारी जगह बेड दीजिये, भवन

नहीं हैं कितनी जगह ए.पी.एच.सी. को, अब सरकार किराये पर लेकर ए.पी.एच.सी. चलाये इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है । आपको पी.एच.सी. में ऐसी व्यवस्था नहीं है । अब लोगों का सरकारी अस्पताल से मुंह मुड़ गया है और अगर देखा जाय तो सिर्फ इंजरी बनवाने और पोस्टमार्टम करवाने के अलावा और कोई कार्य नहीं हो रहा है । आपको किसलिए पैसा दिया जाय कि एम्बुलेंस से कहीं पर गिट्टी-बालू ढोया जा रहा है, उसका सुचारू ढंग से मरीजों को फायदा नहीं हो पा रहा है, कितना घोटाला हो रहा है । किसलिए पैसा आपको दिया जाय आप दस हजार पर मात्र आठ डॉक्टर दिये हैं और दो नर्स हैं, जबकि 45 नर्स और 45 डॉक्टर 10 हजार मरीजों पर होने चाहिए थे । बिहार सरकार ने उदारता दिखायी और इन्होंने....

उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री शमीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और टाइम दे दिया जाय । बिहार में मृत्यु दर सिर्फ 5424 बतायी, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगायी तो 9375 हुआ । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, चाहे सारे विधायक से भी अलग-अलग सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप पूछ सकते हैं कि इनके क्षेत्र में कितनी मृत्यु हुई और आप देखते हैं कि आपने चार लाख रुपये की घोषणा की है, बिहार सरकार ने की है लेकिन उसमें एक परेशानी आ रही है कि रैपिड टेस्ट कर उसका इलाज हुआ लेकिन इलाज के दौरान जब मरीज सीरियस हुआ तो सदर हॉस्पिटल छोड़ कर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चले गये । आर0टी0पी0सी0आर0 की जाँच नहीं हो पायी । एच0आर0सी0टी0 करा कर उसका इलाज चला ....

उपाध्यक्ष : समय हो गया, माननीय सदस्य ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, टाईम है मेरा । एच0आर0सी0टी0 करा कर इलाज हुआ लेकिन अब जब आपदा द्वारा चार लाख रुपये की बात आ रही है तो इसमें आर0टी0पी0सी0आर0 का टेस्ट मांगा जा रहा है तो इस पर आप ध्यान दें और एच0आर0सी0टी0 जिसके पास है, रैपिड टेस्ट है तो उससे आप काम चलायें, उसको चार लाख रुपया दें । आज आपने.....

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, दो मिनट सुन लिया जाय ।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया ।

श्री शमीम अहमद : आज मेरे क्षेत्र में एम0एस0डी0पी0 योजना से महोदय, इस पर ध्यान दिया जाय। बंजरिया प्रखंड है जो सिकरहना नदी से दो पार्ट में बँट जाता है, वहां पर एक एम0एस0डी0पी0 योजना से सी0एस0सी0 का प्रावधान हुआ है और पहले से

जो पी0एच0सी0 है, वह मोतिहारी के सटा है तो वह प्रावधान जो आया है, मैं चाहूँगा कि इसको सिकरहना नदी के उस पार बनाया जाय ताकि लोगों को फायदा हो । चूंकि, बाढ़ आने की वजह से यह सारा लगाव टूट जाता है तो मैं इतनी ही बात कह कर, इस पर हमारे मंत्री जी सजग हों और जहां भी हमारे सारे माननीय विधायकों से मंतव्य लें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री जीतन राम मांझी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साथ ही आज मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो बजट की मांग की गई है, हम उसका समर्थन करते हैं साथ ही यह कहते हैं कि बिहार सरकार ने जो कोरोना महामारी में जो विश्व की यह महामारी थी, विश्व के सभी उन्नत देश इस महामारी से अक्रांत हुए और इस अक्रांता के कारण जितनी मौते हुईं, अगर हम बिहार की तुलना करेंगे तो हम पायेंगे कि अन्य देशों की अपेक्षा बिहार की सरकार ने जो इससे उबरने का कार्यक्रम किया और जो व्यवस्था की, उसके लिए पूरे विश्व की ओर से जो धन्यवाद मिला बिहार सरकार को, हम भी बिहार सरकार को अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं । कोरोना महामारी में भले कुछ कमियां हुई हैं, चूंकि यह महामारी का दौर था, सारे लोग अपनी-अपनी बीमारियों को निपटने में लगे हुए थे, दवा की कुछ कमियां हुई हैं, सरकार ने जो सुझाव दिये हैं, आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, काम किया ही जाना चाहिए और जो मेडिकल की सुविधा है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जानी है, सरकार ने जो व्यवस्था पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में ऑक्सीजन निर्माण की जो व्यवस्था करने का काम किया है, वह प्रारंभ किया गया है ।

क्रमशः

टर्न-23/संगीता-सुरज/29.07.2021

(क्रमशः)

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन से जो भी मृत्यु हुई है, जो अक्षुण्ण मृत्यु हुई है उस पर काबू पाए जाने की नितांत आवश्यकता है । साथ ही साथ जो कोविड की बातें हुई हैं या अन्य जो बातें हुई हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात आई है पी0एम0एी0एच0 में, सीट बढ़ाकर उसे एम0बी0बी0एस0 में, पी0जी में जो सीट की संख्या अभी है, जो 2 हजार 200 सीट की व्यवस्था

एम0बी0बी0एस0 में है पी0एम0सी0एच0 में उसे सरकार ने बढ़ाकर 250 किया है और पी0जी0 में जो 146 सीट अभी हैं उसे भी बढ़ाकर 200 करने का काम किया जा रहा है और सरकार द्वारा जो जगह-जगह ए0एन0एम0 के लिए ट्रेनिंग करने की व्यवस्था की गई है आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो उपकेन्द्र हैं, स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें ए0एन0एम0 की व्यवस्था की जाएगी, डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी । इसलिए बिहार सरकार ने जो बजट लाया है स्वास्थ्य विभाग ने बजट लाया है उसका तहे दिल से समर्थन करते हुए इन्हीं चन्द शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू जी ।

श्री रणविजय साहू : सबसे पहले हम माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रति आभार जताना चाहते हैं कि आपने बोलने का मौका दिया और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार जताते हैं कि आज कटौति प्रस्ताव पर बोलने का आप ने मौका दिया और मोरवा की महान जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार जताना चाहते हैं कि जिसने मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को आर्शीवाद देकर इस सदन में भेजने का काम किया और वही मोरवा जो कल का ताजपुर था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो भूमि था मैं वहीं से आज कटौति प्रस्ताव के पक्ष में हम आज आपके बीच खड़े हुए हैं । आप जानते हैं और सभी लोगों ने विस्तार से चर्चा किया । पिछले सवा साल में इस बिहार में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसकी पोल खोलकर रख दिया । सभी लोगों ने माना कि किस रूप में यहां स्वास्थ्य की बदहाली के कारण अस्पताल में बेड हो, दवा हो, ऑक्सीजन हो जिसकी कमी के कारण सरकारी आंकड़ा है कि 9500 हजार लोगों की मृत्यु हुई लेकिन हम सब का मानना है कि लाखों में लोग मरे हैं । आप सब लोग जानते हैं और जिस प्रकार से इस बिहार में लचर स्वास्थ्य की व्यवस्था है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जहां से आते हैं वहां इनके जिले के हबीबगंज में एक अस्पताल है वहां उस अस्पताल में पुआल भरा हुआ है और लकड़ी वहां जमा हुआ है, लकड़ी का जमावड़ा है और उस अस्पताल में हमेशा ताला लगा हुआ रहता है । इससे बड़ी और क्या बिडंबना हो सकती है कि जिस राज्य के उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी जो डेली आती-जाती हैं पटना, रूकनपुरा उनका आवास है और वहां के सरकारी अस्पताल की जो स्थिति है वहां ताला लगा हुआ है और तबेला में तब्दील है । हम आप सबको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है इस सरकार में स्वास्थ्य की उसको सब लोग जानते हैं नीति आयोग के द्वारा जो मापदंड या बिहार को सबसे निचले स्तर पर 19वें

स्थान पर हमारे बिहार राज्य का स्थान है । आप सब लोग यह जानकर काफी आश्चर्य करेंगे कि हमसे बेहतर व्यवस्था बगल के पड़ोसी राज्य बंगाल में है जो बेड की सिस्टम की व्यवस्था हो या अन्य जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनसे बेहतर है लेकिन इस राज्य में तब घोर आश्चर्य हुआ जब अप्रील और मई का समय था, कोरोना का दूसरा चरण एकदम चरम पर था तब मैं अपने कन्स्टूएंसी मोरवा के क्षेत्र के ताजपुर में जब मैं वहां पहुंचा जब वहां के जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा स्थापित रेफरल अस्पताल में जब मैं वहां गया तब वहां छत से सीमेंट झड़ रहा था और पानी टपक रहा था, यह हाल था जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि है जिसे उन्होंने स्थापित किया था उस अस्पताल की यह दुर्दशा है । उसके बाद बगल में कोठिया के पी0एच0सी0 में जहां हम जांच करने गए, निरीक्षण करने गए तो वहां काउंटर पर आपको आश्चर्य होगा कि एक्सपायरी दवाई मिली, मैंने तुरंत डी0एम0 और सिविल सर्जन को लिखित सूचना दिया और दो तीन घंटा बैठने के बाद भी जो उसका स्टॉक रूप था वह स्टॉक रूम नहीं खुला, और लोग भाग खड़े हुए यह हाल था अस्पताल का । आप सब लोग जानते हैं कि आज पूरे पटना से लेकर पूरे बिहार भर में जब फोन आते थे कि विधायक जी का कोटा होता है पी0एम0सी0एच0 में, हमको सीट दिला दीजिए । विधायक जी का कोटा होता है आप आइ0जी0एम0एस0 में सीट दिला दीजिए तो उस समय बड़ी विवशता होती थी, शर्मीन्दगी महसूस होती थी कोई सीट कोई जगह नहीं मिलता था उस कोरोना काल में । आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पटना के बड़े-बड़े अस्पताल में भी कहीं जगह नहीं मिल रहा था, एक भी सीट कहीं एवुलेवल नहीं था तब लोगों ने पूरे तौर पर लोगों ने गरीब हो या अमीर हो किसी तरह से व्यवस्था करके कहीं से सिलेंडर लाकर और अपने घर में होम क्वारंटीन रहना ही उचित समझा तब बहुत सारे लोगों को निश्चित तौर पर उससे लाभ मिलने का काम हुआ । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पटना में किस प्रकार से इस स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यावसायीकरण किया गया, पूरा व्यावसायीकरण हो गया है । आप जब पटना से निकलिए बाईपास इलाके में, सैकड़ों ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ गरीब को सिरिंज लगाकर खून चूसने के लिए बैठे होते हैं सरकार का इसपर कोई अंकुश नहीं है, सरकार का कोई उसपर आधिपत्य नहीं है, कोई उस पर दबाव नहीं है, कोई उसकी देखरेख नहीं है । मैं गवाह हूं दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनका मैं गवाह हूं और मैं उस अस्पताल तक गया हूं जो मरीज मर जाता है उसका भी वेंटीलेटर के नाम पर लाखों रूपया वसूलता है और यह खेला तब शुरू होता है जब मरीज गांव से पी0एम0सी0एच0 आते हैं और वहां दलाल के माध्यम से और वहां के एंबुलेंस के

माध्यम से जब वहां पहुंचते हैं तब वहां उसका मूल्यांकन किया जाता है उसके चप्पल से, उसके जूते से, उसके कपड़े से उसका मूल्यांकन होता है कि वह व्यक्ति कितना पैसा दे सकता है और अंतिम दम तक उस व्यक्ति से पैसा चूसा जाता है, पैसा लिया जाता है और पूरे तौर पर सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है । ऐसी घटनाएं भी हुई हैं दर्जनों बार जिनमें जो लोग थे मैं जाकर के आग्रह करके मैंने वैसे लोगों को उस अस्पताल से मुक्त कराने का काम किया हूं । यही स्वास्थ्य व्यवस्था है । आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बिहार में अगर सीवान में सिटी स्कैन के लिए अगर कोई 2 हजार लेता है तो वहीं पटना में 3 हजार रूपया वसूलता है 4 हजार रूपया वसूलता है । हम आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार एक पॉलिसी बनाये, पूरे बिहार में नियमावली बनावे कि किसी व्यक्ति का अगर पैथोलॉजी का जांच कराना है तो पूरे स्टेट में एक ही रेट हो उसका एक ही मापदंड हो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । एम0आर0आई0 हो या अन्य कोई जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो इस तरह से पूरे तौर पर इस स्टेट में लूट मची हुई है और सरकार का कहीं भी इस पर अंकुश नहीं है इसलिए आप तमाम लोगों से, तमाम सदस्यों से आग्रह करना चाहते हैं यह सिर्फ एक सदस्य का मामला नहीं है तमाम जो उपस्थित सदस्य हैं सब के साथ कहीं न कहीं यह बात होता होगा और निश्चित रूप से हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर सरकार संज्ञान लेकर पॉलिसी बनाने का काम करे और याद होगा सभी साथियों को हमलोग यही मानते थे कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है लेकिन आज क्या हो रहा है पूरे तौर पर सॉटकॉट के माध्यम से

(क्रमशः)

टर्न–24/मुकुल–राहुल/29.07.2021

क्रमशः

श्री रणविजय साहू : लोग तुरन्त चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जायं, तुरन्त अरबपति बन जायं तो इसके लिए भी निश्चित रूप से सरकार का एक मापदंड होना चाहिए कि किस प्रकार से प्राइवेट जो नर्सिंग होम हैं, जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर हैं इसको किस प्रकार से व्यवसायीकरण करना चाहते हैं उसको रोकने का काम करेंगे । इन्हीं चंद बातों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आभार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुर्यकान्त पासवान ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, चर्चाएं तो बहुत हो चुकी हैं, मैं

थोड़ा-बहुत चर्चा करना चाहता हूं, खासकर के मैं जो देशी चिकित्सक हैं जिनको झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने जो भूमिका अदा की है वह काबिलेतारीफ है । महोदय, उस आशाकर्मी और उस सफाईकर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके बदौलत कोरोना काल जिन लोगों की जान बची और जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हालचाल है, महोदय, मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि हमारे बेगूसराय जिला के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वे पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं होते थे, जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे उनके द्वारा उनको इंजेक्शन लगवाया जाता था, अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोग फर्श पर लेट करके वहां पानी चढ़वाने का काम किया करते थे, हमारे बेगूसराय जिला के जिला अधिकारी महोदय ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई और वहां पर हमारा उतना बड़ा जिला अस्पताल है वेंटिलेटर मात्र चार है और उसमें भी एक्सपर्ट नहीं हैं, वह कोरोना काल में बंद था और वेंटिलेटर के अभाव में हमारे वहां के बहुत सारे मरीज दम तोड़ दिये । हम सरकार से मांग करना चाहते कि तीसरी वेव की जो तैयारी होनी चाहिए वह निश्चित रूप से हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर अनुमंडल अस्पताल नहीं है । महोदय, बखरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर अनुमंडल अस्पताल नहीं है, वह सुदूर देहाती इलाका है उसमें अनुमंडल अस्पताल नहीं है वहां से इस कोरोना काल में पेशेंट को दूसरी जगह भेजा जाता था जाते-जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया करते थे । महोदय, मैं आपको कुछ ...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त किया जाय ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : कोरोना महामारी के दौरान राज्य के अस्पतालों, एक तरफ लोग बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर की कमी से दम तोड़ रहे थे तो महोदय, दूसरी तरफ राज्य और केन्द्र में सत्ताधारी नेताओं के घर एम्बुलेंस सड़ रही थी । महोदय, महामारी के दौरान जब पूरा देश शोकाकुल था उस समय हमने कारपोरेट अस्पतालों का राक्षसी रूप भी देखा है, एक-एक मरीज से एक से दो लाख, दो लाख-तीन लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी । महोदय, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए मैं राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के द्वारा नियंत्रण चाहता हूं, महोदय, राज्य के उप स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र में कोई भी व्यवस्था नहीं है ।

उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाय, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, एक मिनट । महोदय, मैं मांग करता हूं राज्य के द्वारा राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा निंदनीय है । महोदय, कोरोना से जितने भी लोग उस समय मरे हैं उन्हें सरकार के द्वारा वह राशि दी जाय ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं और मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल को कोविड-19 ने खोल करके रख दिया और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, इस सदन के एक सदस्य जो मंत्री भी रह चुके थे मेवा लाल चौधरी जी, उनका निधन कोरोना से हुआ और उनके निधन के बाद उनके पी0ए0 का बयान जो अखबार में छपा कि जब वह मुंगेर से चले और पटना आये, पटना में पूर्व मंत्री सिर्फ बेड के लिए दर-दर भटक रहे थे और उन्हें आखिरी तौर पर किसी पटना के कलेक्टर के प्रयास से पारस हॉस्पिटल में एक बेड किसी तरह से मिल पाया था । जब एक पूर्व मंत्री को आप बेड मुहैया नहीं करा सकते, जब सदन के एक पूर्व सदस्य को बेड मुहैया नहीं करा सकते, तो आप क्या स्वास्थ्य विभाग का लंबा-चौड़ा बयान कर रहे थे । डॉ संजीव जी चले गए, मैं समझता हूं कि पक्ष की ओर से उन्होंने कुछ बातें जो कहीं वे एक डॉक्टर का दर्द था, वे डॉक्टर थे इसीलिए उन्होंने ईमानदारी से कहा कि कोविड के काल में 25,000 रुपये में गैस सिलेंडर मुझे खरीदना पड़ा यह सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, विपक्ष ने भी कुछ बातों को कहा । आप क्या बयान कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं ? जितना अनुपूरक बजट बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप मुकर नहीं सकते । मैं समस्तीपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं, 42 लाख आबादी समस्तीपुर में है और सदर अस्पताल में सिर्फ पांच वेंटिलेटर और उसमें सिर्फ एक टैक्नीशियन है, शुरू के दौर में एक टैक्नीशियन को पटना बुला लिया गया । कैसे किसके भरोसे आप 42 लाख लोगों की आबादी के स्वास्थ्य को इस कोरोना काल में आपने छोड़ दिया था, बाद के दिनों में आपने 3 वेंटिलेटर दलसिंहसराय में, 3 रोसड़ा में और 3 पटौरी में दिया, लेकिन टैक्नीशियन कहीं नहीं दिया तो वेंटिलेटर देने का मतलब क्या हुआ । वेंटिलेटर सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ कहने के लिए आज जो स्थिति है वह हम आपको कहना चाहते हैं, कहते है कि ऑक्सीजन की कमी से किन्हीं की मौत नहीं हुई, मंत्री जी का भी बयान, खबर छपी थी मैं देख रहा था उनका बयान आया था क्या ये सच्चाई है कि बिहार के अंदर किसी एक व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखिए और टटोलिए कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई की नहीं, मौत हुई है आप इंकार कर सकते हैं, इंकार करते रहिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हम लोगों की नजर के सामने चूंकि हम लोग घूम रहे थे, हम लोगों की नजर के सामने हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे थे । हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मौत का आंकड़ा आपने जो लिया वह कहां से लिया और कैसे लिया, मौत

कोरोना में जिनकी मौत हुई है उसको सिर्फ आर0टी0पी0सी0आर0 रिपोर्ट जिनको मिली उसके आधार पर आपने आंकड़ा लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समस्तीपुर के 5 हॉस्पिटल में कोरोना के समय में मैं जा रहा था और जिनकी मौत कोरोना के वार्ड में हुई उनको भी आप कहते हैं आपकी मौत कोरोना से नहीं हुई यही है आपकी व्यवस्था, तो आप कोरोना वार्ड में उनको भर्ती क्यों किए थे, अगर ...

उपाध्यक्ष : कंक्लूड कीजिए अब ।

श्री अजय कुमार : अगर कोरोना वार्ड में भर्ती करके उनकी मौत हुई, उस तमाम कोरोना काल में जिनकी मौत हुई आप उनको उसमें शामिल कीजिए । मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं, वैक्सीन की उपलब्धता, आप कह रहे हैं कि बोलने दीजिए, उपाध्यक्ष जी हैं, महोदय हैं, वे बोलेंगे तब मैं बैठ जाऊंगा । मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बेवजह कुछ बोलता हूं । वैक्सीन की जो उपलब्धता हुई है उससे चार हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है तो आपको इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, यह तो पैसा आपके सरप्लस और सब एम0एल0ए0 का पैसा भी आपने ले लिया । अंत में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि विभूतीपुर, जो असेंबली का एकमात्र हॉस्पिटल है, चार लाख की आबादी उस पर निर्भर करती है, एक महिला डॉक्टर वहां थी उस महिला डॉक्टर को भी आपने वहां से हटा दिया, यह बात सही है कि 12 साल से उनको आप डिप्यूट करके रखे हुए थे, लेकिन आज वहां एक भी महिला डॉक्टर नहीं है । पिछले दिनों एक महिला वहां जनने के लिए गई थी और बच्चे का जन्म होते ही मौत हो गई, कौन इसका जवाबदेह है, जवाबदेही किस पर तय की जाएगी, क्या आप कार्रवाई करेंगे ? आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप अविलंब 4 लाख की आबादी पर उस हॉस्पिटल को एक महिला डॉक्टर जरूर दीजिए और भी जो है उसको भी देखिए...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, टाइम हो गया ।

श्री अजय कुमार : एक लाईन सिर्फ हम कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं कि बिहार का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज पटना में है उसमें स्वीकृत चिकित्सकों के पद 78 हैं और सिर्फ 26 चिकित्सक उसमें पदस्थापित हैं । (क्रमशः)

श्री अजय कुमार: प्राचार्य की पदस्थापना गलत तरीके से, गलत नियम से हुई है उसको आप कब तक करेंगे अगर सदन को जवाब देते समय बताते तो बहुत अच्छा होता । शुक्रिया ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए सदन में खड़ा हूं । महोदय, स्वास्थ्य विभाग का यह बहस आज कोरोना केंद्रित हो गया और पूरी बहस का केंद्र बिंदु कोरोना हो गया । महोदय, यह कोरोना किसी से पूछ कर नहीं आया था इस देश में । हमलोग धन्यवाद दें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को संभालने का काम किया, अमेरिका और यूरोप जैसे देश थर्रा उठे थे उस कोरोना से । महोदय, पहली बार जिस समय इस देश में पी0पी0ई0 किट नहीं बन रहा था, वहॉ आज वेंटिलेटर की बात हो रही है, मुझे खुशी हो रही थी कि आज माननीय विपक्ष के सदस्यगण वेंटिलेटर पर चर्चा कर रहे हैं, कल तो पी0पी0ई0 किट की चर्चा के लायक नहीं थे । यह तो धन्यवाद दीजिए भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और साथ-साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सहित बिहार सरकार को, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाकर न केवल भारत को बचाने का काम किया बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की उस जनता को बचाने का काम किया, न केवल बचाने का काम किया, एक दामाद को जो सुविधा मिलती है अपने घर में वह सुविधा क्वारंटाइन के समय मिल रहा था, कोई लूंगी मांग रहे थे, कोई धोती की लड़ाई लड़ रहे थे, कोई बाल्टी मांग रहा था, कोई साबुन मांग रहा था, हमारी बहन वैक्सीनेशन पर चर्चा कर रही थी, जिस वैक्सीन की चर्चा हो रही थी महोदय, पोलियो का वैक्सीन कितने दिनों में बना था इस देश के अंदर, कितने दिनों में बना था पोलियो का वैक्सीन और आज मैं मानता हूं कि मौतें हुई हैं लेकिन जितनी मौत दुनिया के देशों में हुआ है वह भारत और बिहार में नहीं हुआ है यही संभालने का काम है, यही सुशासन का काम है । मैं आपको बता रहा हूं महोदय, कि क्वारंटाइन में जिस तरह से सेवा किया, बसों पर लादकर जिस प्रकार से लाया गया लोगों को इस बिहार के अंदर, क्या वह काबिले तारीफ नहीं है ? आप चर्चा कर रही थीं गंगा में लाश बहाने का, यह भी एक सुनियोजित साजिश था कि हम उस परिवार का, अपने पिता के जमीन का वारिस हो सकते हैं लेकिन उसके लाश को ठीक प्रकार से हम दफना नहीं सकते और गंगा में जाकर बहा दिया कि बिहार आये और बिहार बदनाम हो, क्या इसके लिए वह भी सोची-समझी साजिश थी ? जब केवल कुछ ही देश दुनिया में वैक्सीन बना रहा

था, भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाकर आज आच्छादित करने का काम कर रहा है और 6 महीना के अंदर इस बिहार के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है, वैक्सीन के बारे में मैं बता रहा हूं माननीय अजीत बाबू कि किस प्रकार से आप लोगों ने वैक्सीन के नाम पर नाटक किया, किस प्रकार से लोगों का गुमराह किया, किस प्रकार से जनता के बीच गलत मैसेज देने का काम किया, गांव के गरीब लोगों को छला स्वयं तो वैक्सीन आकर ले लिए, स्वयं आप लोगों ने वैक्सीन आकर ले लिया...

उपाध्यक्षः शांति, शांति माननीय सदस्य । शांति ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः लेकिन आप गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको आपने छलने का काम किया, उसको गुमराह करने का काम किया कि वैक्सीन लीजिएगा तो आप मर जाइएगा, वैक्सीन लीजिएगा तो बीमार हो जाइएगा, ये कहिए एन0डी0ए0 की सरकार को कि इस प्रकार से विश्वास पैदा किया जनता के बीच, जो आज वैक्सीनेशन का काम इतनी तेजी से हुआ है और आप आंकड़े छुपा रहे थे, जब आप बोल रहे थे विपक्ष के लोग तो आंकड़े छुपा रहे थे, जरा याद करिए 2005 से पहले, याद करिए 39 मरीज एक पी0एच0सी0 पर आ रहा था प्रति माह और आज हजारों मरीज आ रहे हैं प्रति महीना कहां जा रहे हैं आप ? मैं मानता हूं चिकित्सकों की आज भी कमी है, आज तेजी से बहाली हो भी रही है जितनी आबादी है जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उस तरह से डॉक्टर नहीं हैं लेकिन जो स्थिति 2005 में थी, वह स्थिति आज नहीं है, आज बेहतर स्थिति में हम बात करने के लिए तैयार हैं और स्वास्थ्य के लिए अब पी0एच0सी0 संपन्न हो चुका है, पी0एच0सी0 संपन्न हो चुका है, हम एडिशनल पी0एच0सी0 और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं । बिहार सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया है आपके विधान सभा में 5-5 स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा हुई है और आपके विधान सभा के अंदर 5 स्वास्थ्य केंद्र और एक पी0एच0सी0 दिये जाएंगे, यह भी निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है । बंधुओं जरा आप हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि अगर नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री आपको नहीं मिला होता, संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं मिला होता, संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिला होता, तो शायद हम में से भी कितने लोग और चले गए होते । अभी तो हमारे 2 ही साथी की चर्चा हो रही थी लेकिन यह कम से कम आप आभार प्रकट करिए बिहार की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को संभालने का काम किया है । आप जोड़ लीजिए दुनिया के 150 देशों के बराबर अकेले भारत की आबादी है, दुनिया में 150 देशों के बराबर अकेले भारत की

आबादी है और उस आबादी को संभालना किसी के बूते की बात थी तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री के बूते की बात थी । ये विपक्ष जिस प्रकार से काम किए हुए हैं वह भी दिन याद है हमलोगों को कि किस प्रकार से हमारे भारत भूषण भाई कह रहे थे कि सूअर और कुत्ता अस्पताल में, इनको पुरानी बात याद आ गई, 2005 से पहले की बात याद आ गई क्योंकि 2005 से पहले हमेशा घूमते रहते थे, आज कल ये घूमते कम हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, मधुबनी जिला में एम0एल0ए0, एम0पी0 का व्हाटसएप्प ग्रुप बना हुआ है, प्रतिदिन कितना वैक्सीनेशन होता था, कितना सीट खाली थी, कितने मरीज भर्ती हुए, कितने ठीक हुए सब का आंकड़ा आपको व्हाट्सएप्प पर मिलता था एम0एल0ए0, एम0पी0 के ग्रुप में..

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, आप सब उसके गवाह हैं लेकिन आप व्हाट्सएप्प नहीं खोलिएगा, आप देखना ही नहीं चाहिएगा, आप तेजस्वी जी के नजर से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, अगर आप इधर की नजर से देखिएगा तो आपको जरूर दिख जाएगा, आपको डर होता होगा, आपको डर होता होगा की कहीं हमारे नेता हमको निकाल न दें पार्टी से, इसलिए सच बोलिए, सच बोलने की ताकत रखिए यह सत्य का मंदिर है, यह लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें सच बोलने वाला ही टिका रहेगा ।

उपाध्यक्षः अब आप समाप्त कीजिए, मा0 सदस्य ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः इसलिए सच-सच बोलिए और बताइए, अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा किः ''वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ।''

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, मुख्य सचेतक बड़े भाई ललित यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया । महोदय, कहा गया है कि- ''जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'' जिसके परिजन, जिसके संबंधी, जिसके परिवार में लोग कोरोना से मरे हैं, वह जानते हैं कि कोरोना महामारी में क्या सुविधा और क्या असुविधा रही है । मैंने झेला है, महोदय, मैंने अपने दर्जनों संबंधी को इस कंधे पर उठाया है कोरोना पीड़ित से मरने वालों को, जिसमें हमारे चाचा

भी थे और मैं जब मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में उनको लेकर के गया, जिलाधिकारी से मैंने बात किया...

...क्रमशः...

टर्न-26/सत्येन्द्र/29-7-21

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव(क्रमशः) जब कहीं जगह नहीं मिली तो मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां स्वयं ट्रौली पर मरीज को रखना पड़ा और ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने से करना पड़ा । जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि 15 से 20 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर के हमलोग 10-10 सिलेंडर रखे हुए थे, मजबूरी थी हमलोगों के साथ और महोदय जब मैंने बेड मांगा तो मुझे कहा गया कि किसी मरीज को मरने दीजिये तो आपको जगह देंगे, ये है स्वास्थ्य विभाग, यह मुझे कहा गया, उसी जगह पर एक सीनियर डॉक्टर जो कोरोना पीड़ित था, वह हमें कहता है कि जब मैं डॉक्टर हूँ तो भी हमें कोई देखने नहीं जा रहा था तो आपको कौन देखेगा । मेरे पेसेंट को उपाध्यक्ष महोदय, ऑक्सीजन लगा हुआ था और एंटीजन जांच वाला आकर कहता है कि सर आपके पेसेंट का निगेटिव रिपोर्ट है, आप जल्दी लेकर भाग जाईए, ये दूदर्शा है स्वास्थ्य विभाग का । मैं भोगा हूँ वहां और मैं जानता हूँ कि इस सदन में बैठा हुआ आदमी, एक दो आदमी को छोड़कर के, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सगा संबंधियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई होगी लेकिन कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके सगा संबंधियों को यह मुश्किल झेलना नहीं पड़ा होगा। अरे, इस सरकार की बात करते हैं, इस सरकार ने तो वैक्सिन को सही ढंग से हिफाजद नहीं कर पाया और भारी मात्र में वैक्सीन खराब हो गया। हमलोग तो डबल डोज लिये हुए हैं । मांझी जी जो हमारे गार्जियन हैं, वे वोले थे कि वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट में मोदी जी का नाम है तो ठीक कहा था उन्होंने कि मरने वाले सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी का नाम होना चाहिए, यह क्यों नहीं किया गया । जांच की व्यवस्था जो थी, एच0आर0सी0टी0 जांच को लोग मान नहीं रहा था और आर0टी0पी0सी0आर0 जांच रिपोर्ट उस समय 10-10 दिन पीछे मिल रहा था और जब मरीज मर जाता था तब उसका निगेटिव रिपोर्ट आता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुजफ्फपुर मेडिकल कॉलेज में पांच सौ से अधिक लोगों का जांच के लिए गया और उसमें मात्र 62 आदमी का रिपोर्ट मिला, एंटीजन जांच को उस समय कोई महत्व नहीं देता था, मैं आपको बता देना चाहता कि जब डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब आप अनुदान देते हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट पर जब लिखता है कि कोबिड से मरीज

मरा तो उसको क्यों नहीं अनुदान दिया जाता है । महोदय, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में एक साथ दो मरीज एडमिट हुआ, एक सम्पन्न व्यक्ति था और दूसरा एक गरीब व्यक्ति था, 24 अप्रैल को दोनों की मौत हो जाती है । महोदय, 15 दिनों तक दोनों आदमी एक साथ इलाज करवाया, जो सम्पन्न लोग था उसका अनुदान का चला आया पैसा और जो गरीब आदमी है वह आज भी भटक रहा है । मैं खुद जब जाकर सुपरिटेंडेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि जांच का रिपोर्ट नहीं आया है । इलाज किये कोबिड का, रखे कोबिड बार्ड में और मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हो कोबिड का तो उस गरीब आदमी के साथ अन्याय क्यों ? ऐसी ऐसी विवशता झेलनी पड़ी है, ठीक कहा है हमारे साथियों ने कि जब प्राइवेट अस्पताल में अपने संबंधियों को लेकर गया लेकिन लास्ट में जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो नर्सिंग होम में वेंटिलेटर नहीं था और जब मेडिकल कॉलेज में लेकर आया तो उसका वहां एक भी टेक्नीशियन नहीं मिला जो उसको चला सके। महोदय, मेडिकल कॉलेज में न तो वेंटिलेटर चलाने वाला है, आप डायलेसिस मशीन तो लगा दिये लेकिन उसका भी कहीं टेक्नीशियन नहीं है, ऐसी दशा है सरकारी होस्पीटल का और आप कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को पैसा चाहिए। कोरोना काल में आप विधायकों से 2 करोड़ रू0 ले लेते हैं, अभी यहां डी0एम0 पूर्ववर्त्ती जो मुजफ्फरपुर के थे बैठे हुए हैं, तीन करोड़ नबासी लाख रू0 ब्लौक में गया, टीम गठित कर के मीनापुर के सी0ओ0 और बी0डी0ओ0 पर चार्ज किया गया कि पैसे का गबन हुआ है जिसकी जानकारी मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी दिया था और भूमि सुधार मंत्री को दिया था । क्या हुआ उसमें, एफ0आई0आर0 हुआ, 6 महीना से कोई कार्रवाई नहीं हुई, टीम गठित हुआ और तीन सदस्यीय टीम वहां गया, वरीय उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर, लेखापाल और डी0आर0डी0ए0 का चेयरमैन, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कौन चीज का पैसा आपको चाहिए, कौन चीज का पैसा, लूटने का पैसा, –हमहुं लुटव तूहूं लूट लूटे के आजादी वा । लूटने के लिए पैसा चाहिए और वैसे बी0डी0ओ0 को श्रवण बाबू डुमरा का बी0डी0ओ0 बना दिये, डुमरा शहर एरिया का बी0डी0ओ0 बना दिया गया जो लूटेरा है, जहां लाखों आदमी मर रहा है उसका पैसा खाने वाला, हमारे साथी कहते हैं कि सेंटर पर दामाद के जैसा व्यवस्था था। अरे, वह लूटने का व्यवस्था था महोदय, हमलोगों ने भी देखा है कोई ऐसा कोरेंटाईन सेंटर नहीं था, एक जोन हो, दो जोन हो या तीन जोन हो, कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहां मैं नहीं गया । सभी जगह केवल लूटने का काम हुआ, 45 लाख रू0 का भाउचर जमा होता है और 55 लाख रू0 का अग्रिम भुगतान होता है। मैंने श्रवण बाबू को लिस्ट बनाकर दिया था जबकि 30 प्रतिशत

अग्रिम भुगतान का नियम सरकार तय किये हुए है यहां तो 100 प्रतिशत से ज्यादा दिया जा रहा है, पैसा आपको किस चीज का चाहिए लूटने के लिए चाहिए, कहां व्यवस्था है आपका, कोरोनाकाल में वार्ड व्याय एक मिनट..

(व्यवधान)

आप बैठिये। उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जब मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी अच्छी रहती तो उस काल में वार्ड व्याय की नियुक्ति क्यों की गयी ? मात्र तीन महीना के लिए कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए वार्ड व्याय की व्यवस्था की गयी, नर्सिग स्टाफ की व्यवस्था की गयी। मैं समझता हूँ कि यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि तीन महीना के लिए किसी नौजवान को नौकरी पर रखकर के उसको लात मारकर हटा दिया गया, तीन महीना के लिए वह बेरोजगार आदमी इस उम्मीद पर काम में लगता है कि हमारा तीन महीना के बाद एक्सटेंशन हो जायेगा, तीसरा लहर का बेड तैयार हो रहा है लोगों में भय है कि पता नहीं वह किसके लिए बेड रखा हुआ है, उस बेड पर इलाज नहीं हो सकता, उस बेड पर किसी न किसी के नाम लिखा हुआ होगा और वह कोई मेरा बिहार का भाई ही होगा, गरीब आदमी होगा । हमको तो भरोसा है उस बेड को देखकर, लोगों में दहशत है कि 700 बेड बनवा दिये आप फोटो खींचवा लिये,हमें तो लगता है कि 700 लोगों के लिए कफन रखा हुआ है इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप कोरोना काल की तीसरी लहर से पहले चाहे मेडिकल कॉलेज हो या चाहे कोई भी अस्पताल हो, अपने टीम को वहां भेजिये, चाहे अपने जाकर देखिये कि आपकी क्या व्यवस्था है वहां कोई किसी को पूछने वाला नहीं है ।

उपाध्यक्षः अब कंक्लूड कीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः कोरोना वॉरियरर्स के नाम पर जो भी डॉक्टर हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख होता है कि हमारे इसी सदन के सदस्य ने भी दम तोड़ा है और आप जान सकते हैं कि उस सदस्य पर क्या बीता होगा, चाहे वे हजारी जी हों या मेवालाल चौधरी जी हों, हमको लगता है कि बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर जो हार्ट के डॉक्टर थे डॉ0 प्रभात कुमार, वे भी गुजर गये । जब ऐसे ऐसे लोगों का इलाज यहां नहीं हो पा रहा है तो हम क्या उम्मीद करें। हमारे मुख्यमंत्री जी मोतियाबिंद का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, क्या है यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर पी0एम0सी0एच0 में इलाज कराते, एन0एम0सी0एच0 में इलाज कराते, एस0के0एम0सी0एच0 में इलाज करवाते तो मैं समझता कि यहां बिहार की

स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। वे खुद अपना इलाज करवाने बाहर जाते हैं इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोला हूँ । जय हिंद ।

टर्न-27/मधुप/29.07.2021

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूँ । मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं बेनीपुर की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी कृपा से यहाँ पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

आज विपक्ष के हमारे कई मित्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर तरह-तरह की बातों की चर्चा की है जिसमें हमारे पुराने सहयोगी रहे आदरणीय बड़े भाई भारत भूषण मंडल जी की भी बात सुनने का मौका मिला । असल में भारत भूषण मंडल जी मूल रूप से हमलोगों के साथ में काम किये हुये हैं तो जो उस समय में वे भाषण देते थे वही भाषण का टेप आज चल गया । दुर्भाग्य से वह अभी के समय में बात किये, आपने सही कहा लेकिन वह समय था, वह कालखंड था 2005 के पूर्व की बात, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सिर्फ समय की अवधि आपने गलत बता दी, यह आपने गलत बताया । 2005 से पूर्व में, आप सही कहे कि उस समय में किसी भी हॉस्पीटल के बेड पर आदमी नहीं मिलते थे, किसी भी वार्ड में आदमी नहीं मिलते थे, उस समय में उसमें गाय, भैंस, बकरी, उनका आश्रय रहता था । वह याद दिलाने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

अभी सुदामा भाई ने भी कहा है कि आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है, सही भी उन्होंने कहा । साथ-ही उन्होंने कहा कि कमी खोजने की जरूरत है । कहाँ कमी ? स्वास्थ्य सेवा में सुधार कोई एक दिन का काम नहीं है जो स्वीच दबाइये और आपको वहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ मिल जायेगा । सुदामा भाई, आप आज जिस तरफ हैं, उस समय भी आपके राज्य में एक भी नर्सिंग कॉलेज व स्कूल नहीं था तो जब नर्सिंग स्कूल और कॉलेज नहीं था तो फिर नर्सिंग स्टाफ कहाँ से आयेगा ? यह भी तो आप बता देते । आपने सही कहा कि आत्म विश्लेषण की जरूरत है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं, यह कहने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है, हमारे सारे विद्वान से विद्वान यहाँ पर विधायक बैठे हैं, अपोजीशन में

एक पर एक विद्वान बैठे हुये हैं । सबों को मालूम है कि आज बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं । कितने नर्सिंग कॉलेजेज हैं । प्रत्येक जिला में कम से कम एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की, ए0एन0एम0 कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है । यह है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य करने की शैली । आपलोग उल्टी बात कह रहे हैं । यह बात अपने कालखंड की बात हमलोगों को कह दिये । सही में आप विश्लेषण कीजिए, आप खोजिए कि कहॉ गड़बड़ी है, वह बात आप कीजिए । एन0एस0एच0ओ0 के अनुसार आज भी कुल स्वास्थ्य कर्मियों की जनसंख्या अनुपात के मामले में बिहार सर्वाधिक पीछे है । क्यों है ? सही में आपने कहा कि विश्लेषण करने की जरूरत है । यह हमारे विपक्ष के मित्रों के लिए है कि वे विश्लेषण करें कि क्यों है ? कुल डॉक्टरों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बिहार झारखंड, राजस्थान, छतीसगढ़, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों से आगे है । बिहार का स्वास्थ्य सेवाओं में पीछे होने का मुख्य कारण एक समय में नर्सिंग कॉलेजों की नगण्यता रही है । जबकि अब जिस तरह से संस्थाएँ खोली जा रही हैं, आने वाले दिनों में वह नहीं मिलेगा । इसलिए आप चिन्तित न हों, आज नीतीश बाबू के कार्यकाल में जिस तरह से नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी अच्छी होंगी, यह हमें पूर्ण भरोसा है । आपके समय में क्या होता था, यह बोलने की जरूरत नहीं है । चरवाहा विद्यालय आप खोलते थे ।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : पूर्ववर्त्ती सरकार की वजह से आज भी बिहार हॉस्पीटल या बेड के मामले में कई राज्यों से पीछे है । क्यों है, यह आपको विश्लेषण करने की जरूरत है । उस विपरीत परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य कुशलता की वजह से और दक्षता की वजह से हर विपरीत परिस्थिति में विकास की पटकथा लिखने की क्षमता के अलावा श्रेय किसे दिया जा सकता है । जिस तरह से हमलोगों ने....

अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : एक मिनट, हुजूर । (व्यवधान) सत्यदेव बाबू, एक मिनट शांत हो जाइये । दूसरे के समय में डिस्टर्ब करने की बड़ी खराब आपकी आदत है । इसको सुधार लीजिए।

एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल जहॉ से मैं आता था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये लोग बतलाते हैं कि सरकारी अस्पताल में नहीं रहना चाहते हैं, वह एक अस्पताल था जहॉ पर

सीरियस होने पर अगर रेफर किया जाता था तो मरीज वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते थे । यह सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर लोगों का भरोसा है । यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ । अंत में मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने दरभंगा में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ करवा दिया है, उसी तरह से बेनीपुर अनुमंडल में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसको शीघ्र चालू किया जाय । यह मैं आग्रह करता हूँ । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री ललित नारायण मंडल । दो मिनट में ।

श्री ललित नारायण मंडल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमको दो ही मिनट दिया, हमारे लिए बहुत है । हम नीतीश कुमार जी का, अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर का और श्रवण बाबू का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमको दो मिनट बोलने का विधान सभा में मौका मिला है ।

मित्रों, मैं सरकार के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हम विपक्ष के अपने साथियों का भाषण बहुत देर से सुन रहे हैं बड़े ध्यान से । हम कोशिश करेंगे, आपलोगों से निवेदन करते हैं कि मेरी भी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा । बीच में टोका-टोकी नहीं कीजिएगा । यह एक हमारी गुजारिश है।

मुझे याद है मित्रों, एक जमाना था जब कहा जाता था कि नो रोड, सड़क नहीं है । हॉस्पीटल - नहीं है । हॉस्पीटल में डॉक्टर नहीं है और अगर संयोग से कहीं डॉक्टर है तो चिट्ठा काटने के लिए कागज तक नहीं होता था । जहाँ तक एम्बुलेंस की बात और सुरक्षा की बात है, वह सब तो सपनों की बात हुआ करता था । वहाँ से चलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से एन0डी0ए0 की सरकार बनी है, बिहार कहाँ से कहाँ तक चला गया है । इसपर सोचने की बात है, मित्रों । आज कितने हॉस्पीटल हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेज हैं, कितने नर्सिंग कॉलेजेज खुल रहे हैं । इसपर थोड़ा सोचने की जरूरत है । आप कहते हैं कि कोरोना के सेकंड वेव में यह हुआ, वह हुआ, यह सब कमियाँ पाई गई थीं । हम कहते हैं कि उसी कमी को देखकर हमारे विद्वान स्वास्थ्य मंत्री ने इस बजट को बनाया है ताकि जो थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव में वैसी कमी हम आपके सामने नहीं देंगे, तो कैसे ? सपना से हो जायेगा कि हम सोच लेंगे कि थर्ड वेव में कोई कमी न हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो ? ऐसा संभव नहीं है । उसके लिए अर्थ की जरूरत होती है और अर्थ हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहते हैं, हमको देना पड़ेगा अगर बिहार की जनता की आप भलाई चाहते हैं तब । केवल

यहॉ पर बैठकर तकरीर करने से, भाषण देने से नहीं होगा । जबतक डॉक्टर्स नहीं होंगे, जबतक एम्बुलेंस नहीं होंगे, जबतक दवाईयॉ नहीं होंगे, जबतक वैक्सीन्स नहीं होंगे, जबतक और सामान हॉस्पीटल्स में नहीं होंगे तो कहॉ से इलाज होगा । इसीलिए तहेदिल से हम अपने स्वास्थ्य मंत्री का इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा बजट लाया ।

अध्यक्ष : आपने गागर में सागर भर दिया ।

श्री ललित नारायण मंडल : अंत में हम स्वास्थ्य मंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ कि सुलतानगंज में एक महिला हॉस्पीटल है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, थोड़ा-सा मेरी बात पर गौर करेंगे, महिला हॉस्पीटल को पूर्ण-रूपेण कार्य करने दिया जाय और उसे पूर्ण हॉस्पीटल का दर्जा दिया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहॉ स्वास्थ्य विभाग हेतु प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 सदन के समक्ष उपस्थापित करने का प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति के लिए आया हूँ । इस प्रस्ताव में कुल 3673,99,40,000 रूपये के अनुदान मॉग की स्वीकृति का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत गैर योजना मद में कुल 1442.31 करोड़ रूपये की राशि निहित है । योजना मद में कुल 2231.68 लाख करोड़ रूपये की अनुदान मॉग स्वीकृत करने का प्रस्ताव है जो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश हेतु है। इसमें से 1080.73 करोड़ रूपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्यांश, 4 करोड़ रूपये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य के लिए राज्यांश, 63.06 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पंचम चरण में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यांश के लिए प्रस्तावित है । 62 करोड़ रूपये राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 59.68 करोड़ रूपये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के राज्यांश के लिए 73.29 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चतुर्थ चरण के राज्यांश हेतु 647.72 करोड़ रूपये चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 241.2 करोड़ रूपये ए0एन0एम0 के वेतन एवं अन्य मदों हेतु प्रस्तावित है ।

....क्रमशः...

टर्न-28/आजाद/29.07.2021

..... क्रमशः .....

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके सामने कि -

जब आँखों में अरमान लिया,
मंजिल को अपना मान लिया,
है मुश्किल क्या आसानी क्या,
जन ठान लिया तो ठान लिया ।

महोदय, हमने ठान लिया कि जो व्यवस्था इन्होंने 50 वर्षों में बनायी थी, उस व्यवस्था से बिहार को हम बाहर निकालेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिए । बैठिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : और हम बिहार को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, यह हमने ठान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को हमने 15 वर्षों में अपने डगर को बढ़ा चुके हैं और जो हमने अपनी मंजिल तय की है, उस मंजिल की ओर हम बढ़ते चल रहे हैं ।

महोदय, विगत कुछ वर्षों से उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयासरत है । पिछले लगभग सवा साल से कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से सामना करते हुए बिहार राज्य ने जहां एक ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल एवं ईलाज पेशेवर ढंग से किया वहीं इसी क्रम में दृष्टिगत हुई कुछ कमियों को दूर किया गया है, जिसका परिणाम रहा कि विधान सभा निर्वाचन-2020, ईद, दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व एवं होली त्योहार को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया है । कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अनवरत कार्य करते हुए राज्य के चिकित्सकों एवं प्रशासकों ने कोरोना से मृत्यु दर को न्यूनतम रखने में सफलता पायी है । इस दौर में भी समय-समय पर उत्पन्न हुई नई चुनौतियों जैसे आवश्यक दवाओं एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता सभी स्तरों से निरन्तर प्रयास कर सुनिश्चित कराया गया महोदय ।

सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अन्तर्गत आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत गांवों-गांवों तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए हम संकल्पित हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाओं अन्तर्गत उपलब्ध विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाओं को राज्यवासियों को ससमय सुगमतापूर्वक एवं गुणवत्तायुक्त तरीके से समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेणु

देवी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है । इसी क्रम में राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है ।

महोदय, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के पहल किये गये हैं । चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मैं सदन को सम्मान के साथ बताना चाहूँगा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक विधान मंडल द्वारा पारित हो चुका है और शीघ्र ही इसके सम्पूर्ण क्रियान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी ।

बिहार राज्य में उन्नत चिकित्सा संस्थान विकसित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देश का पहला तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पुनर्विकास योजना के रूप में कराया जा रहा है । महोदय, 5540.07 करोड़ की योजना की लागत से कुल 5462 बेड की अस्पताल का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है और प्रयास है कि इसे 5 वर्षों में पूर्ण कर दिया जायेगा । महोदय, निर्माण होने के बाद संस्थान में एम0बी0बी0एस0 सीट भी 200 से 250 एवं पी0जी0 सीटों की संख्या 146 से बढ़कर 200 हो जायेगी ।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 11 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस 211 बेड का नये भवन का निर्माण भी इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा ।

महोदय, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं एवं मरीजों की संख्या में वृद्धि एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिपथ रखते हुए संस्थान को 2500 बेड में परिवर्तित करने की योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित है । एन0एम0सी0एच0 परिसर में उत्कृष्ट डायग्नोस्टिक सुविधाओं की उपलब्धता सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में किये जाने का प्रस्ताव है । 100 बेड का नया मातृ शिशु अस्पताल डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में कोरोना के द्वितीय लहर में मरीजों के इलाज एवं प्रबंधन हेतु अत्यंत कारगर रहा है।

महोदय, अभी मुजफ्फरपुर के एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल के बारे में माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की जा रही है । मैं पूरे सदन के सदस्यों के सामने बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर की तस्वीर 2005 के पहले की थी, उस समय के भवनों के तस्वीर

को देख लें और आज जो 2020 में एस0के0एम0सी0एच0 का जो कैम्पस दिखाई पड़ रहा है, उसको जाकर देख लें, अन्तर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा महोदय । आज उस अस्पताल के अन्दर 100 बेड का पीकू अस्पताल जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वह 8 महीना के रेकॉर्ड टाईम में बनकर तैयार हुआ है । महोदय, उस अस्पताल के अन्दर 200 करोड़ रू0 की लागत से कैंसर इन्स्टीच्यूट बनने जा रहा है और उसकी चहारदिवारी घेरने के बाद उसकी निविदा की प्रक्रिया होगी । महोदय, वह क्या नहीं दिखता है, वहां कैंसर का इलाज होगा, क्या वह नहीं दिखता है ? वहां का जो मूल भवन था, उस मूल भवन के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है, क्या वह नहीं दिखता है ? उन अस्पतालों के अन्दर दवाईयां नहीं होती थी, आज दवाईयां हैं, क्या वह नहीं दिखता है ? महोदय, एस0के0एम0सी0एच0 के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है, मुजफ्फरपुर के बच्चे-बच्चे से पूछियेगा तो बच्चा-बच्चा आज बोलेगा कि क्या परिवर्तन हुआ है और वहां जो घटना हुई थी दो साल पहले, आज क्या परिस्थिति है, आज बच्चा-बच्चा जान रहा है । महोदय, इस सदन में हम बोले, पक्ष बोले, विपक्ष बोले, जनता जो बोलती है, वही सच होता है और जनता आज मुजफ्फरपुर की बोल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एस0के0एम0सी0एच0 के चेहरे को हमने बदलने का काम किया है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अन्दर उस परिसर में 132.51 करोड़ की लागत से 397 बेड का सर्जिकल वार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है । महोदय, एक मिनट में मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूँगा । यह सर्जिकल वार्ड उस वार्ड का जो ब्लिडिंग है, आज उस ब्लिडिंग को खाली कराना पड़ा है । 1983 में उस अस्पताल का ब्लिडिंग बना था जो दरभंगा के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको मालूम होगा कि 1983 में किसकी सरकार थी, किन लोगों ने उस भवन को बनवाया था और आज वह भवन इन 38 वर्षों में जर्जर स्थिति में आ गया कि आज हमको खाली करवाना पड़ा, नहीं तो किसी दिन दुर्घटना हो जाती, कौन है इसका जिम्मेवार और आज वैसे भवन बनाने के कारण सरकार को वहां 132.51 करोड़ रू0 खर्च करके नया सर्जिकल वार्ड बनवाना पड़ रहा है । महोदय, यह परिवर्तन करना पड़ रहा है । ऐसा हमको मिला था और आज चेहरा बदलना है, तस्वीर बदलनी है, व्यवस्था बदलनी है तो ऐसा काम करना पड़ रहा है, यह मैं बताना चाहता हूँ । महोदय, उसको जून, 2022 तक पूर्ण कर लेंगे । वही पर दूसरा एम्स बनाने की स्वीकृति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दिया है और मैं आदरणीय

प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके दरभंगा में दूसरा एम्स बनाने की स्वीकृति मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर बिहार के उस प्रमुख स्थान को जो राज्य के अन्दर चिकित्सा सेवा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान में एम्स को बनाने की स्वीकृति दी और वहां पर 200.12 एकड़ के भूमि केन्द्र सरकार को हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और प्रस्तावित भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा 13.3 करोड़ की लागत से मिट्टी भराई योजना की स्वीकृति भी दे दी गई है । शेष बचे 27 एकड़ पर बचे डी0एम0सी0एच0 के पुनर्विकास की भी योजना प्रस्तावित है । महोदय, उसी अस्पताल में 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल भी निर्माणाधीन है, वह भी बन रहा है । उसके अतिरिक्त उसी डी0एम0सी0एच0 के अन्दर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 8 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस 210 बेड के नये भवनों का निर्माण भी अंतिम चरण में है ।

भागलपुर एवं अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया ये सारे जो अस्पताल हैं, इन सारे अस्पतालों के अन्दर आज सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक बन रहे हैं और वहां नये विकास के कार्य किये जा रहे हैं । उसी प्रकार से पावापूरी के परिसर में नवनिर्मित फार्मेसी संस्थान में इस वर्ष से महोदय मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उस समय तो पारामेडिकल इन्स्टीच्यूट, नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, फार्मेसी इन्स्टीच्यूट की कमी थी और महोदय पूरे 50 साल जिन लोगों ने राज किया उनके शासन काल में केवल एक फार्मेसी इन्स्टीच्यूट इस राज्य में रहा और आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 6 फार्मेसी इन्स्टीच्यूटों की स्वीकृति मिली है । यह परिवर्तन है तब न बच्चा पढ़कर आयेगा, तब न फर्मासिस्ट मिलेगा, कॉलेज ही नहीं था तो फर्मासिस्ट खोजियेगा तो कहां से मिलेगा ? नर्सिंग स्टाफ खोजियेगा, जब नर्सिंग इन्स्टीच्यूट ही नहीं था तो स्टाफ कहां से मिलेगा ? महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि पावापूरी में इसी साल से फार्मेसी संस्थान में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुरूआत करने का प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए महबूब जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इस परिसर में टी0बी0 कल्चर लैब का प्रस्ताव है, जिससे क्षय रोग की जॉच एवं शोध में सहायता मिलेगी ।

महोदय, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहा है बिहार में, पूर्णिया से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं । पूर्णिया में 346.28 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 500 बेडयुक्त

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अगले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 100 नामांकन क्षमता के साथ एम0बी0बी0एस0 का पाठ्यक्रम शुरू हो जायेगा । महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि 3 साल पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास हुआ था और हमलोगों ने उस समय कहा था कि चौथे साल यहां मेडिकल कॉलेज खोल देंगे और चौथे साल, अगले साल हमलोग पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं ।

टर्न-29/ज्योति/29-07-2021 (क्रमशः)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, इसी प्रकार से सारन जिला में 376.27 करोड़ की लागत से 500 बेड का राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और समस्तीपुर के सरायरंजन में 591.77 करोड़ की लागत से श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय 500 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य जारी है उसे भी 2022 तक पूरा किया जायेगा। मधुबनी के झंझारपुर में 500 करोड़ की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 500 बेड युक्त अस्पताल और सीतामढ़ी जिला में 541 करोड़ 4 लाख की लागत से अस्पताल और महुआ में 526 करोड़ की लागत से 500 बेड का अस्पताल बन रहा है । उसी प्रकार से सिवान जिला में भी आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी आपको खुशी होगी सिवान जिला के मैरवा में 568 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड युक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का कार्य शुरु हो गया है । आज तक हम सिवान के लोग हैं, आज सिवान की जनता के बीच क्या खुशी है, यह अवध बिहारी चौधरी जी जानते होंगे या हम जानते होंगे, जब वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य के तीन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बेगुसराय, जमुई एवं बक्सर के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निस्तार की कार्रवाई अंतिम चरण में है ।

अध्यक्ष : सिवान की बात हो रही है सुनिये । बैठिये सत्यदेव बाबू ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : सत्यदेव जी आपके ब्लौक में बनवा रहे हैं सी.एच.सी. कितना बढ़िया बन रहा है । आज तक बना था सी.एच.सी. जो बनवा रहे हैं ।

महोदय, कैन्सर मरीज की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आई. जी.आई.एम.एस. है वहाँ पर 138 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का स्टेट कैन्सर संस्थान का निर्माण किया गया है और 15

अगस्त, 2021 के पूर्व आई.जी.आई.एम.एस. के उस नये परिसर में कैन्सर मरीजों के इलाज का काम शुरु हो जायेगा । उसी प्रकार से महोदय, आई.जी.आई.एम. एस. के अंदर 500 बेड के अस्पताल का कार्य चल रहा है और 500 बेड का अस्पताल नया आई.जी.आई.एम.एस. के अंदर बन रहा है । 1200 बेड के नये अस्पताल 513 करोड़ की लागत से भी बनने का निविदा का कार्य निष्पादित हो गया है और 15 अगस्त के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी से तिथि लेकर हमलोग उस 1200 बेड के अस्पताल का भी आई.जी.आई.एम.एस. के अंदर उसका शिलान्यास करेंगे और आई.जी.आई.एम.एस. में आने वाले समय में लगभग 2750 बेड का अस्पताल होगा । अजीत बाबू, अभी भी जाकर देखते होंगे। महोदय, उसी परिसर में 191.67 करोड़ की लागत से नेत्र अस्पताल के भवन के निर्माण का काम भी चल रहा है । यह तो सब लोग जा कर देख सकते हैं । हो रही है, प्रगति दिखायी पड़ेगी । आपको भी दिखायी पउ़ेगी, जाकर देखिये । राज्य में सभी विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम में 564 सीटें, यू.जी. पाठ्यक्रम के 950 सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । इसी प्रकार से जो हमारे सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल हैं उन सभी अस्पतालों में भी बेहतर काम किए जा रहे हैं और उसका उन्नयन किया जा रहा है । चाहे वह इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान हो या लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल हो वहॉ भी ट्रौमा सेंटर 15 अगस्त के पहले शुरु करने जा रहे हैं जो बिहार का पहला ट्रौमा सेंटर होगा । राजेन्द्र नगर नेत्र सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल वहॉ भी 15 अगस्त के पहले हमलोग उस नये भवन में शुरु करने जा रहे हैं । (व्यवधान ) जरुरत पड़ेगी तो ले लेंगे । उसी प्रकार से महोदय, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल उस अस्पताल में भी 15 अगस्त के पहले, (व्यवधान) जब जरुरत होगी तो ले लेंगे । ललित बाबू हमारा बहुत ध्यान रखते हें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोगों की बात अब कहने जा रहे हैं तो धैर्य से सुनियेगा तब न ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल और उसी प्रकार से महोदय, भोजपुर में मानसिक आरोग्यशाला 128.96 करोड़ की लागत से महोदय, नालंदा के रहुई में अभी डेंटल कॉलेज की बात हो रही थी । दूसरा डेंटल कॉलेज भी फरवरी, 2022 तक नालंदा के रहुई में बनकर तैयार हो जायेगा और 404 करोड़ की लागत से 100 बेड का डेंटल कॉलेज बन कर तैयार है । महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति राज्य में लगातार बेहतर हो रही है और राजकीय

आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, बेगुसराय में नये तरीके से पढ़ाई शुरु की गयी है। महोदय, सुशासन के कार्यक्रम 2020 –25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। टेली मेडिसिन सुविधाओं का शुभारम्भ हमलोगों ने किया और 21 फरवरी 2021 को इस संजीवनी के माध्यम से हब एवं स्पोक के माध्यम से किया गया है और महोदय, इसमें 2263 स्वास्थ्य उपकेन्द्र को स्पोक के रुप में एवं 245 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल को हब से जोड़ा गया है । महोदय, आज तक लगभग 2 लाख 43 हजार 829 मरीजों ने इसका लाभ लिया है । महोदय, बच्चों के हृद्य में छेद से बच्चों की दुखद मौत हो जाती थी और जब यह सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदशील हैं और हमारी सरकार संवेदनशील है और सरकार ने निर्णय किया था कि जिन बच्चों के हृद्य में छेद होते हैं उनका मुफ्त में ऑपरेशन करेंगें और उन बच्चों का इलाज हम मुफ्त में करायेंगे और महोदय, हम संवेदनशील लोग हैं । हम एक बात कहना चाहते हैं कि '' पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को –ललित बाबू सुन लीजिये । मेरा सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : यह सेंटेंस सुन लीजिये । बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : एक मिनट सुन लीजिये ।

'' पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को,
उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते ।''

हमलोगों ने लिखा है वह पसीने की स्याही है । पसीना बहाते हैं। मेहनत करते हैं और मेहनत करके महोदय, हम इस काम को करते हैं । महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों के हृद्य में छेद है उन बच्चों के उपचार हेतु नि:शुल्क हृद्य योजना की सुविधा दी गयी है और महोदय, 46 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है । महोदय, सदर अस्पताल ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आप इसको रखिये वहीं । देख लिए हैं ।

( इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया )

श्री मंगल पाण्डेय , मंत्री : 12 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रुप में उन्नयन किया जा रहा है । 36 सदर अस्पतालों में सी.टी. स्कैन लगा रहे हैं । 16 जगहों पर इसकी स्थापना हो चुकी है । अनुमंडलीय अस्पतालों में भी 50 से 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पतालों के निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है । दो अनुमंडलीय

अस्पताल बेलसंड एवं तेरला का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । महोदय, दीदी की रसोई के माध्यम से भी आई.पी.डी. में रहने वाले लोगों को बेहतर भोजन सुविधा अगले पॉच वर्षों तक दी जायेगी उसका अनुबंध हुआ है । महोदय, ये लोग नहीं सुनेंगे विकास की बात जो इन लोगों ने देखा है वही देखते रहना चाहते हैं । हम लोग बिहार की तस्वीर बदलने वाले लोग हैं और तकदीर बदलने वाले लोग हैं इनको अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। विकास की बात तो सुन ही नहीं सकते विकास से तो बैर है इसीलिए जनता को आपलोगों से बैर है । आपलोगों को विकास से बैर है और जनता को आपसे बैर है । महोदय, कोविड की चर्चा हो रही थी और जो मैं कोविड की चर्चा करता आप सब रहते तो अच्छा होता । मैं एम.आई.एम. के सदस्यों को धन्यवाद दूँगा कि आप कम से कम हमारे साथ विकास की बातों को सुन रहे हैं । आप इसके सहभागी बन रहे हैं । महोदय, कोविड की चर्चा मैं करता । ये लोग गए नहीं होंगे अभी सामने जाकर टी.वी. पर मेरा भाषण सुन रहे होंगे तो वहॉ बढ़िया से सुनेंगे अच्छा है महोदय, मैं कहना चाहता हूँ

''हर दर्द की पहचान होती है,
खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है,
वही बदलते हैं रुख हवाओं का
जिनके इरादों में जान होती है ।''

हमारे इरादों में जान है महोदय, इसलिए उसको बदलने निकले हैं महोदय, और कोविड-19 की चुनौतियों का भी सामना हम सब लोगों ने अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक किया है और इस राज्य के अंदर कोविड के संक्रमण को पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हम सब लोगों ने रोकने का काम किया है। महोदय, कोविड के लिए जो व्यवस्थाएं हमलोगों ने पहले चरण में और दूसरे चरण में बनायी थी मैं सदन के पटल पर अपने भाषण को रखूंगा उसको अंश बनाया जायेगा चूँकि कई विषय उसके अंदर हैं लेकिन सी.सी.सी. हो, डी.सी.एस. सी. हो या डेडीकेटेड डी.सी.एच. हो ।

(क्रमशः)

टर्न-30/पुलकित-अभिनीत/29.07.2021

क्रमशः

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इन सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में बेडों की व्यवस्था की गयीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गयी, हमारे माननीय सदस्य विरोधी दल के रहते मैं उनको एक-एक आंकड़ा पढ़कर सुनाता, लेकिन ये सारे आंकड़े मैं सदन पटल पर रखूंगा । महोदय, जो होम आइसोलेटेड लोग थे उनके लिए भी हमलोगों ने काम किया और हिट एप हमलोगों ने बनाया । होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन हमलोगों ने बनायी जिसकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया महोदय और फिर इस एप के जैसा एप देश के कई राज्यों ने बनाया । बिहार ने जिस एप को बनाया उसको देखकर फिर देश के अन्य राज्यों ने फिर इस तरीके से काम किया । महोदय, आई0टी0 विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूं, निश्चित रूप से आई0टी0 विभाग के सहयोग से यह काम हुआ है । महोदय, राज्य में जो दूसरी कोरोना की लहर आयी उसमें हम सब लोगों ने सतत प्रयास किया और दवाइयां उपलब्ध करायी तथा ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करायी । महोदय, 16 मीट्रिक टन यहां पर मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग होता था जब दूसरे दौर की शुरूआत हुई और एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी कि हमलोगों ने 232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भी उठाव किया । महोदय, 14 गुणा अधिक ऑक्सीजन का उठाव और किसी भी चीज का डिमांड यदि 20 दिन में 14 गुणा बढ़ेगा तो उस व्यवस्था पर कितना दबाव आयेगा इसका अंदाज लगाया जा सकता है । महोदय, फिर भी हमलोगों ने कमी नहीं होने दी और आज भी मैं सदन के अंदर खड़े होकर बहुत ही जिम्मेवारी से साथ कह रहा हूं कि किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में हमलोगों ने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी ।

महोदय, RT-PCR जांच True Nat, Rapid Antigen Kit की व्यवस्था हर कार्य को हमलोगोंने किया और पर्याप्त संख्या में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जांच बढ़ती रहे, जांच पर्याप्त हो इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं और उसका लाभ यह होता है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से काम करता है और परिणाम देता । महोदय, उस परिणाम का ही प्रतिफल है महोदय, विपक्ष के लोग, वैसे नेता प्रतिपक्ष तो बहुत टेक्नोमेटिक हैं, टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं और कोविड पोर्टल जरूर देखते होंगे तो मेरे माननीय सदस्य जो टी0वी0 देख रहे होंगे वे मेरी बात को जरूर नेता प्रतिपक्ष को जाकर कहेंगे कि Cowin पोर्टल पर डेली देश के सभी राज्यों का रिपोर्ट होता है । उसमें टोटल टेस्ट कितना हुआ, कंफर्म कितना है, एक्टिव कितना है, रिकवर कितना हुआ, मृत्यु कितना है यह रोज दर्शाया जाता है । महोदय, पेपर मैं लाया हूं इसे कोई भी पढ़ सकता है और आज जो बिहार की स्थिति है, आज बिहार में कुल एक्टिव केस 479 है जो देश के 26

राज्यों से कम है, बिहार 27वें नंबर पर है । महोदय आबादी हमारी तीसरे नंबर पर और 26 राज्यों में हमसे अधिक मरीज, हमारी व्यवस्था यदि अच्छी नहीं है, हमने मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो यह एक्टिव केस इतना कम क्यों है इसका जवाब दे सकते हैं ? महोदय, इस राज्य के अंदर कह रहे हैं कि बचाया नहीं गया तो यह आंकड़ा गवाह है, एक-एक दिन का आंकड़ा है, 7 लाख 14 हजार 554 लोगों की जान बिहार की इसी स्वास्थ्य व्यवस्था ने, इसी स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करके लोगों की जान बचायी है । महोदय, समय की कमी है मैं समझ सकता हूं इसलिए आर0टी0पी0सी0आर0 जांच सहित सभी चीजों को हमने आगे बढ़ाया, आर0टी0पी0सी0आर0 वैन हमलोगों ने चलाया, 10 वैन चलाया हमलोगों ने, 21 जिलों में आर0टी0पी0सी0आर0 लैब हमलोग बनवा रहे हैं और 17 जिलों में लैब बनकर तैयार भी हो चुका है । लगातार हम जो जांच कर रहे हैं, अभी तक 3 करोड़ 68 लाख 94 हजार जांच हो चुकी है महोदय और हमारी जो रिकवरी रेट है वह देश के औसत से बेहतर है । हम काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं तो रिकवरी रेट कैसे बेहतर है और यह हम नहीं कह रहे हैं इस देश के अंदर जो Cowin पोर्टल है उसकी रिपोर्ट है । 98.6 परसेंट हमारी रिकवरी रेट है और आज जो हमारी पॉजिटिविटी रिपोर्ट है वह .05 परसेंट है जो देश के किसी भी राज्य से सर्वाधिक है ।

महोदय, वर्ष 2020 में जो वैश्विक महामारी आई उसमें इस टीका को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, टीकाकरण करने के लिए सतत अनुश्रवण मैं कहूंगा यदि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जैसा अनुश्रवण करने वाला व्यक्ति न हो, व्यक्तित्व करने वाला व्यक्ति न हो, जितने अच्छे तरीके से हमलोगों ने टीकाकरण का काम किया है, वो शायद हम नहीं कर पाते और आज इसीलिए आप समय-समय पर अखबारों में पढ़ते होंगे कि बिहार के कई दिन ऐसे होते हैं कि टीकाकरण देश में पहले नंबर पर आता है और वह अखबार की सुर्खियां बनता है । वह इसलिए बनता है कि प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग होती है, एक दिन भी थोड़ी कमी होती है तो मुख्यमंत्री जी का फोन आयेगा । मुख्यमंत्री जी तुरंत हमसे, अधिकारियों से पूछना शुरू कर देते हैं, कम क्यों हुआ ? आज इस राज्य में 839 एक्सप्रेस टीका गाड़ियां घूम रही हैं । गांव, देहात के अंदर, टोलो, मोहल्लों में जा रही हैं । हम दिव्यांगों को टीका दे रहे हैं, वृद्धजनों को टीका दे रहे हैं, हम फोन करते हैं उनके घर पर टीका पहुंचाया जाता है । यह काम हम सब लोग करने में सफल हुए हैं, इसलिए कि आज नेतृत्व संवेदनशील है और नेतृत्व की बहुत स्पष्ट सोच है कि हमें करना क्या है ? इसीलिए आज जो यह सारा प्रस्ताव आया है

इसमें राशि की उपलब्धता, इन सारी बातों में की गयी है । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनका स्पष्ट मत है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो भी आवश्यकता पड़ेगी राज्य की सरकार हर संसाधन देने के लिए तैयार है और दे रही है, इसलिए परिस्थिति बनी है । महोदय, कोरोना के संभावित तीसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का जो कार्य है महोदय दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा । सुदृढ़ीकरण के कार्य के संबंध में अंत में मैं आपको कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले कहूंगा महोदय ।

''यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा,
जमीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा ।
ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा ।।''

अध्यक्ष : चलिये, बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, हम इससे आगे निकलेंगे, हम कोरोना को मात देंगे और कोरोना को मात देकर हम आगे बढ़ेंगे । महोदय ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए जो काम किये गये हैं, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से काम बताये गये हैं उसमें मैं बहुत समय नहीं लगाउंगा केवल इतना कहूंगा 122 स्थानों पर पी0एस0ए0 प्लांट लगाया जा रहा है, मेडिकल टैंक लगाये जा रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेजों में और ये सारे कार्य हमारे सदस्य पूछ रहे थे कब तक होगा ? 31 अगस्त के पूर्व ये सारे कार्य सम्पन्न कर लिये जायेंगे और इसमें से अधिकतर ऑक्सीजन पी0एस0ए0 प्लांट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग उनका समय लेकर 15 अगस्त से पहले करवायेंगे । महोदय, उसी प्रकार राज्य के अंदर एम्बुलेंस की सेवाओं को बेहतर करेंगे और इस साल हमने बजट भाषण में ही कहा था कि एक हजार एम्बुलेंस की नई बेड़ी इस साल हमलोग शामिल करेंगे और हमने तय किया है कि इस कोरोना के कारण 534 नये एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम हमलोग खरीदने जा रहे हैं और इन सारे एम्बुलेंस के क्रय पर लगभग 416 करोड़ रूपये का खर्च आना है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सदन पटल पर रख दें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं रख रहा हूं । मानव संसाधन के लिए भी लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं चाहे वह चिकित्सक हों, जी0एन0एम हों, ए0एन0एम0 हों, पैरा मैडिकल स्टाफ हों सभी कि नियुक्तियां की जा रही हैं । महोदय,

''मंजिलें क्या है रास्ता क्या है,
हौसला है तो फिर फासला क्या है ।''

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इसलिए महोदय, हम उस फासले को पाटने में लगे हुए हैं और अंत में मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा । हम सब लोग अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के विकास, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की योजनाओं की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की अहम भूमिका निभाने में लगे हुए हैं । इस कड़ी को और सुदृढ़ करने के लिए पांच-छः प्वाइंट हैं ।

राज्य के पटना में बच्चों के सभी बीमारियों के इलाज हेतु सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जायेगी । राज्य के सभी ए0एन0एम0 एवं आशा कर्मियों को विभिन्न प्रकार के उपकरण युक्त किट प्रदान किये जायेंगे और यह हम 15 अगस्त के पहले करेंगे । राज्य की सभी आशा कर्मियों को स्मार्ट फोन उपलब्धता की योजना शुरूआत की जायेगी, यह योजना भी 15 अगस्त से पहले होगी । राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जगह-जगह पर फैले वर्षों से अनुपयुक्त पुराने धातु के कचरे के सुव्यवस्थित निस्तारण हेतु मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम0एस0टी0सी0) के साथ एम0ओ0यू0 हुआ है । जिसकी शुरूआत पी0एम0सी0एच0 (पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल) एवं डी0एम0सी0एच0 (दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थानों से की जा रही है । राज्य में नयी, पहले के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में यह सबसे बड़ी बात थी, हमारे माननीय सदस्यों को सुननी चाहिए थी, सभी विधान सभा क्षेत्र में पांच हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर तथा एक ए0पी0एस0 (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य) केन्द्र की स्थापना के साथ 122 से अधिक स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी निर्माण किये जायेंगे, जिस पर 2060.76 करोड़ रूपये की लागत पर निविदा आमंत्रित कर ली गई है और शीघ्र ही निविदा का निस्तारण होगा । ईमरजेन्सी कोविड रिस्पोन्स पैकेज के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 1482.34 करोड़ रूपये की योजना है । राज्य में रेफरल वाहन की व्यवस्था में बढ़ोतरी हेतु 1000 नये एम्बुलेंस के क्रय पर 416 करोड़ रूपये की योजना है ।

(क्रमशः)

क्रमशः..

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इस प्रकार से महोदय कुल 3959.10 करोड़ रुपये जो अगले दो वर्ष के अंदर खर्च होने का प्रस्ताव है, वह खर्च किया जायेगा । महोदय, हमारे बहुत से विपक्ष के साथी कह रहे थे कि दो करोड़-दो करोड़, वह दो करोड़ उनका नहीं है, वह दो करोड़ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा है और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खर्च करने का निर्णय किया है । भारत की सरकार ने भी सांसदों के पैसे को उस हित में खर्च करने का निर्णय किया है और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दो करोड़ की चिंता छोड़िये, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यह 3959.10 करोड़ रुपया अगले दो साल में खर्च होगा, उसे यदि हम 243 विधान सभा से औसत निकालेंगे, तो 2 करोड़ के बदले 16.29 रुपया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर विधान सभा की जमीन पर काम खड़ा करके और काम करने के लिए पैसा खर्च किया जायेगा । यह काम हम लोग करने जा रहे हैं, आप दो करोड़ की चिंता में लगे हैं । महोदय, मैं अब समाप्त कर रहा हूं यह कहते हुए कि-

''मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए,
होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए,
बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से,
हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उसकी स्वीकृति दी जाय ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ''स्वास्थ्य विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 के

उपबन्ध के अतिरिक्त 3673,99,40,000/- (तीन हजार छः सौ तिहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से लिए जायेंगे ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक के व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01, कृषि विभाग के संबंध में 348,32,12,000/- (तीन सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बारह हजार) रुपये,

मांग संख्या-02, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 27,86,000/- (सताईस लाख छियासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-03, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 464,32,75,000/- (चार सौ चौंसठ करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-04, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 6,27,00,000/- (छः करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये,

मांग संख्या-06, निर्वाचन विभाग के संबंध में 84,03,00,000/- (चौरासी करोड़ तीन लाख) रुपये,

मांग संख्या-07, निगरानी विभाग के संबंध में 1,70,01,000/- (एक करोड़ सत्तर लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-08, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,000/- (एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-09, सहकारिता विभाग के संबंध में 41,85,000/- (एकतालीस लाख पचासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-10, ऊर्जा विभाग के संबंध में 1465,00,95,000/- (एक हजार चार सौ पैंसठ करोड़ पंचानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या–11, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 1215,78,77,000/– (एक हजार दो सौ पंद्रह करोड़ अठहत्तर लाख सतहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या–12, वित्त विभाग के संबंध में 8382,10,00,000/– (आठ हजार तीन सौ बयासी करोड़ दस लाख) रुपये,

मांग संख्या–16, पंचायती राज विभाग के संबंध में 182,00,00,000/– (एक सौ बयासी करोड़) रुपये,

मांग संख्या–18, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 462,35,87,000/– (चार सौ बासठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तासी हजार) रुपये,

मांग संख्या–19, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 108,74,51,000/– (एक सौ आठ करोड़ चौहत्तर लाख इक्यावन हजार) रुपये,

मांग संख्या–21, शिक्षा विभाग के संबंध में 1144,89,01,000/– (एक हजार एक सौ चौवालीस करोड़ नवासी लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–22, गृह विभाग के संबंध में 554,00,94,000/– (पांच सौ चौवन करोड़ चौरानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या–23, उद्योग विभाग के संबंध में 46,62,01,000/– (छियालीस करोड़ बासठ लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–25, सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 1,02,50,000/– (एक करोड़ दो लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या–26, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 1,81,26,000/– (एक करोड़ इक्यासी लाख छब्बीस हजार) रुपये,

मांग संख्या–27, विधि विभाग के संबंध में 1,26,00,000/– (एक करोड़ छब्बीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–30, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 1,000/– (एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–32, विधान मंडल के संबंध में 1,30,00,000/– (एक करोड़ तीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–33, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 27,00,000/– (सत्ताईस लाख) रुपये,

मांग संख्या–35, योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 331,81,94,000/– (तीन सौ इकत्तीस करोड़ इक्यासी लाख चौरानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या–36, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 380,00,02,000/– (तीन सौ अस्सी करोड़ दो हजार) रुपये,

मांग संख्या–37, ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 120,00,00,000/– (एक सौ बीस करोड़) रुपये,

मांग संख्या–38, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 5,00,000/– (पांच लाख) रुपये,

मांग संख्या–39, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 900,33,01,000/– (नौ सौ करोड़ तैंतीस लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–40, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 47,58,000/– (सैंतालीस लाख अट्ठावन हजार) रुपये,

मांग संख्या–41, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 920,48,00,000/– (नौ सौ बीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–42, ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 2780,58,50,000/– (दो हजार सात सौ अस्सी करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या–43, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 33,44,38,000/– (तैंतीस करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार) रुपये,

मांग संख्या–44, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 20,00,00,000/– (बीस करोड़) रुपये,

मांग संख्या–46, पर्यटन विभाग के संबंध में 25,02,000/– (पच्चीस लाख दो हजार) रुपये,

मांग संख्या–47, परिवहन विभाग के संबंध में 11,27,60,000/– (ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख साठ हजार) रुपये,

मांग संख्या–48, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 641,28,02,000/– (छः सौ इकतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख दो हजार) रुपये,

मांग संख्या–50, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 22,02,000/– (बाईस लाख दो हजार) रुपये,

मांग संख्या–51, समाज कल्याण विभाग के संबंध में 2763,43,91,000/– (दो हजार सात सौ तिरसठ करोड़ तैंतालीस लाख इक्यानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

## विधायी कार्य

## बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

## विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-32/संगीता-सुरज/29.07.2021

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तिय वर्ष 2021-22 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक-26.07.2021 को उक्त स्थापित किया गया है । महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2020 से ही कोरोना महामारी से पूरे विश्व के साथ हमारा देश भी प्रभावित रहा है । बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के लिए इस संक्रमण की रोकथाम के संदर्भ में चुनौतियां भी अधिक हैं । अभी पिछले वर्ष के महामारी के प्रभाव के पश्चात सामान्य जीवन बहाल होने की प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को पुनः प्रभावित किया । इससे एक ओर अर्थव्यवस्था पर जहां चुनौतिपूर्ण प्रभाव पड़ा वहीं दूसरी ओर इसने मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर हालात पैदा किए । इस कोविड महामारी का सामना करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी सक्रियता से कार्य किया और कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए व्यापक पैमाने पर त्वरित कार्रवाई की गई तथा संक्रमण की

रोकथाम एवं प्रभावित व्यक्तियों के इलाज हेतु सभी पहलुओं तथा टेस्टिंग, ट्रैकिंग एवं ट्रीटमेंट पर भी सफलता पूर्वक काम किया गया ।

महोदय, कोविड महामारी की राज्य में रोकथाम तथा इससे संक्रमित व्यक्तियों के जांच एवं उपचार हेतु आवश्यक सामग्री सेवा एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से 2 करोड़ रुपये प्रत्येक माननीय सदस्य बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् की अनुमान्यता राशि से स्वास्थ्य विभाग को कुल 626 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं । महोदय, कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए एक माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई । इस पर अनुमानत: 316 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा । राज्य के सभी जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के अंत:वासी रोगियों को उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन यथा- "दीदी की रसोई" की शुरूआत की गई । कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत 3 हजार 737 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि दी गई है । अब राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को प्रति आश्रित 4 लाख रुपये का भुगतान राज्य संसाधन से करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक में उपबंध भी किया गया है । राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु "बाल सहायता योजना" नाम से नई योजना की स्वीकृति दी गई है । इसके अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा शून्य से 18 वर्ष आयु समूह बच्चों के पालन-पोषण हेतु 1500 रुपये की अनुदान राशि प्रतिमाह दी जाएगी । उक्त वर्णित स्थिति में बिहार आकस्मिकता निधि से किए गए कुल प्रावधान 2 हजार 475 करोड़ 88 लाख 56 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण 2021-22 सदन में प्रस्तुत किया गया ।

महोदय, वार्षिक स्कीम के अंतर्गत 14 हजार 161 करोड़ 90 लाख 82 हजार रुपये की राशि का प्रावधान प्रथम अनुपूरक आग्नण में प्रस्तावित किया गया है । इसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश मद में कुल प्रावधानित

राशि 7 हजार 716 करोड़ रुपये में केंद्रांश मद में 336 करोड़ रुपये एवं राज्यांश मद में 7 हजार 380 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । वार्षिक स्कीम के अंतर्गत राज्य की अपनी स्कीम के लिए कुल प्रावधानित राशि 5 हजार 311 करोड़ 17 लाख 53 हजार रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 12 हजार 885 करोड़ 5 लाख 86 हजार रुपये की राशि का प्रावधान प्रथम अनुपूरक आग्नण में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 8 हजार 382 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि आकस्मिकता निधि में स्थायी कार्य में राशि अंतरण हेतु, 1 हजार 465 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को उपभोक्ता सब्सिडी अंतर्गत रिसोर्स गैप मद हेतु, 1 हजार करोड़ रुपये कोविड-19 उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकरण हेतु, दवा भंडार मद में 754 करोड़ 3 लाख रुपये विभिन्न विभागों के अंतर्गत वेतनादि मद हेतु, 600 करोड़ रुपये प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु, 300 करोड़ रुपये कोविड-19 से मृत्यु होने पर निकटतम आश्रित को अनुदान हेतु मुख्य है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में वार्षिक ऋण अधिसीमा अतिरिक्त 2 प्रतिशत की वृद्धि कर 5 प्रतिशत किया गया था । पुनः भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी । शेष 0.5 प्रतिशत की उधार सीमा राज्य के लिए निर्धारित शर्तों पर आधारित होगी ।

महोदय, 2021-22 में निर्धारित 4 प्रतिशत की अधिसीमा के अलावा 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार सीमा भी दिए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है जो ऊर्जा प्रक्षेत्र में किए जाने वाले सुधार से संबद्ध होगा । राज्य के लिए निर्धारित ऋण अधिसीमा में भारत सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2021 इसी सत्र में सदन में उपस्थापित किया गया है ।

महोदय, बिहार विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2021 द्वारा कुल 27 हजार 50 करोड़ 17 लाख 83 हजार रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । विनियोजन राशि 27 हजार 50 करोड़ 17 लाख 83 हजार रुपये मतदेय है । कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व मद में 15 हजार 186 करोड़ 51 लाख रुपये एवं पूंजीगत मद में 11 हजार 863 करोड़ 66 लाख 83 हजार रुपये है।

अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सदन से अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनि मत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-29 जुलाई, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-45 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई )

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक-30 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

## प्रथम अनुपूरक बजट अभिभाषण

## (वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु)

जुलाई, 2021

**माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का प्रथम अनुपूरक बजट अभिभाषण सामग्री**
**(वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु)**

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

**मैं यहॉ स्वास्थ्य विभाग हेतु प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021–22 सदन के समक्ष उपस्थापित करने हेतु आया हुआ हूँ। इस प्रस्ताव मैं कुल 3673 करोड़ 99 लाख 40 हजार रूपये की अनुदान मॉग स्वीकृति का प्रस्ताव है।**

**इस प्रस्ताव के अंतर्गत गैर योजना मद में कुल 1442.31 करोड़ रूपये की राशि निहित है। योजना मद में कुल 2231.68 (बाइस सौ एकत्तीस करोड़ 68 लाख) करोड़ रूपये की अनुदान मांग स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश हेतु है। इसमें से 1080.73 करोड़ रूपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राजयांश, 4 करोड़ रूपये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य के लिए राज्यांश 63.06 करोड़ रूपये की राशि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पंचम चरण में इंदीरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यांश के लिए प्रस्तावित है।**

**62 करोड़ रूपये राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 59.68 करोड़ रूपये आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के राज्यांश के लिए 73.29 करोड़ रूपये प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चतुर्थ चरण के राज्यांश हेतु 647.72 करोड़ रूपये चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 241.2 करोड़ रूपये ए0एन0एम0 के वेतन एवं अन्य मदों हेतु प्रस्तावित है।**

**महोदय,**

**जब ऑखों में अरमान लिया**
**मंजिल को अपना मान लिया**
**है मुश्किल क्या आसानी क्या**
**जब ठान लिया तो ठान लिया।**

विगत कुछ वर्षों से उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयासरत है। पिछले लगभग सवा साल से कोविड–19 महामारी की चुनौतियों से सामना करते हुए बिहार राज्य ने जहॉ एक ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल एवं ईलाज पेशेवर ढंग से किया वहीं इसी क्रम में दृष्टिगत हुई कुछ कमियों को दूर किया गया है, जिसका परिणाम रहा कि विधान सभा निर्वाचन–2020, ईद, दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व एवं होली त्योहार को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अनवरत कार्य करते हुए राज्य के चिकित्सकों एवं प्रशासकों ने कोरोना से मृत्यु दर को न्यूनतम रखने में सफलता पाई है। इस दौर में भी समय–समय पर उत्पन्न नई चुनौतियों जैसे

आवश्यक दवाओं एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता सभी स्तरों से निरन्तर प्रयास कर सुनिश्चित कराया गया।

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अन्तर्गत गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए हम संकल्पित हैं।

**महोदय,** सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाओं अंतर्गत उपलब्ध विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाओं को राज्यवासियों को ससमय सुगमतापूर्वक एवं गुणवत्तायुक्त तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री तथा श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी, माननीय उप–मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को Digital Technology की मदद से विकसित करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु विभिन्न प्रकार के पहल किये गये हैं :–

**(क) <u>चिकित्सा शिक्षा</u>**

मैं सदन को बताना चाहूँगा कि **राज्य में चिकित्सा शिक्षा हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक विधान मंडल द्वारा पारित हो चुका है और शीघ्र ही इसके संपूर्ण क्रियान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई संपन्न की जायेगी।**

बिहार राज्य में उन्नत चिकित्सा संस्थान विकसित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देश का पहला तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण **पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना** के पुनर्विकास योजना के रूप में कराया जा रहा है। रु० 5540.07 करोड़ की योजना की लागत से कुल 5462 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है और प्रयास है कि इसे पाँच वर्षों में पूर्ण करा दिया जाय। निर्माण होने के बाद संस्थान में MBBS सीट भी 200 से 250 एवं PG सीटों की संख्या 146 से बढ़कर 200 हो जाएगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत 11 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस 211 बेड के नए भवन का निर्माण भी इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

**महोदय, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना** में उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं, मरीजों की संख्या में वृद्धि एवं भविष्य की आवश्यकता को दृष्टपथ रखते हुए संस्थान को 2500 बेड में परिवर्तित करने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। एन0एम0सी0एच0 परिसर में उत्कृष्ट डायग्नॉस्टिक सुविधाओं की उपलब्धता सेंटर ऑफ

एक्सेलेंस में किए जाने का प्रस्ताव है। 100 बेड का नया मातृ शिशु अस्पताल डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में कोरोना के द्वितीय लहर में मरीजों के ईलाज एवं प्रबंधन हेतु अत्यन्त कारगर रहा है।

**श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर** में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से मोबाईल होम बेस्ड पेलियेटिव केयर की शुरूआत की गयी जिससे कैंसर के अंतिम चरण के मरीजों की पीड़ा में राहत हुई है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु लगभग रूपये 200 करोड़ की लागत के आधार पर निविदा शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है।

राज्य के 14 जिलों यथा–नालंदा, सीवान, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, सुपौल, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना एवं औरंगाबाद में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुचारू रूप से संचालित है।

मुजफ्फरपुर एवं आस–पास के जिलों में फैलने वाले A.E.S. (Acute Encephalitis Syndrome) समूह की बीमारी की चिकित्सा हेतु 100 बेड के बाल गहन चिकित्सा यूनिट (PICU) का भवन निर्माण एवं मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशाला का निर्माण रिकॉर्ड आठ महीने में किया गया है। A.E.S. (Acute Encephalitis Syndrome) रोग के संबंध में जागरूकता, प्रारंभिक लक्षणों की पहचान, ससमय उचित उपचार के माध्यम से इस वर्ष इस रोग के बहुत कम कुल 92 मामले प्रतिवेदित हुए हैं एवं इस रोग से होने वाली मृत्यु की संख्या भी काफी कम रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत 08 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस 210 बेड के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है।

**दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा** के परिसर में 132.51 करोड़ रूपये की लागत से 397 बेड का सर्जिकल वार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में दूसरे एम्स (AIIMS) के निर्माण हेतु 200.12 एकड़ भूमि केन्द्र सरकार को हस्तांतरण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और प्रस्तावित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा 13.3 करोड़ रूपये की लागत पर मिट्टी भराई की योजना स्वीकृत की गयी है। शेष बचे 27 एकड़ भूमि पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के पुनर्विकास की योजना प्रस्तावित है। 100 बेड युक्त मातृ शिशु अस्पताल निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत 08 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस 210 बेड के नए भवन का निर्माण अंतिम चरण में है।

**जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर** एवं **अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया** में भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत 07 सुपरस्पेशलिटी विभागों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों से लैस क्रमशः 202 एवं 176 बेड के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। 100 बेड का नया मातृ शिशु अस्पताल बनकर तैयार है।

बिहार राज्य के अत्यन्त पिछड़े एवं बाढ़ ग्रस्त कोसी क्षेत्र के निवासियों को उन्नत एवं अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएँ **जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा** के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है और इस क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजो का ईलाज भी यहाँ किया गया।

**वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी** के परिसर में नवनिर्मित फार्मेसी संस्थान में इस वर्ष से डिपलोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की शुरूआत करने का प्रस्ताव है। इसी परिसर में TB Liquid culture lab की स्थापना का भी प्रस्ताव है जिससे क्षय रोग की जाँच एवं शोध में सहायता मिलेगी।

**पूर्णियाँ में** 346.28 करोड़ रू0 की लागत से निर्माणाधीन 500 बेडयुक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और शैक्षणिक सत्र 2021–22 से इसमें 100 नामांकण क्षमता के साथ एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

**सारण जिला** के छपरा में 376.27 करोड़ रू0 की लागत से 500 बेडयुक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा **समस्तीपुर** के सरायरंजन प्रखड में 591.77 करोड़ रू0 की लागत से **श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय** में 500 बेडयुक्त अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है, जिसे वर्ष 2022 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

**मधुबनी जिला** के झंझारपुर में 515.00 करोड़ रू0 की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 500 बेडयुक्त अस्पताल तथा **सीतामढ़ी जिला** में 541.40 करोड़ रू0 की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं 500 बेड के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है, जिसे वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है।

**वैशाली जिला** के महुआ में 526.40 करोड़ रू0 की लागत से 500 बेडयुक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है, जिसे फरवरी, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

**सीवान जिला** के मैरवा में 568 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेडयुक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शिलान्यास किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य के तीन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यथा **बेगुसराय, जमुई एवं बक्सर** के निर्माण कार्य से सम्बन्धित निविदा निस्तार की कार्रवाई अंतिम चरण पर है। **भोजपुर जिले के आरा शहर** में 500 बेडयुक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की निविदा प्रक्रियाधीन है।

महोदय, बिहार की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना** में Kidney एवं Cornea Transplant, Bypass Surgery एवं लीवर ट्रान्सप्लान्ट कार्य आरंभ हो चुका है और निकट भविष्य में Heart Transplant का कार्य भी प्रारंभ किये जाने की योजना है।

कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस संस्थान में 138.00 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 100 बेड के **स्टेट कैंसर संस्थान** का निर्माण किया

गया है और 15 अगस्त, 2021 के पूर्व ही इसमें उपचार की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी जायेगी। साथ ही इस संस्थान को सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध बेड 1032 को बढ़ाकर 2732 किये जाने का कार्य जारी है। इसके लिए 500 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है एवं अतिरिक्त 1200 बेड के नये अस्पताल भवन के निर्माण की योजना भी 513.21 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण हेतु निविदा निष्पादित की जा चुकी है एवं 15 अगस्त, 2021 के पूर्व ही इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

साथ ही, 151.67 करोड़ रुपये की लागत से 200 बेड के **नये नेत्र अस्पताल** के भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में Comprehensive Day Care Centre for Blood Disorder (Thalassemia Haemophillia etc.) स्थापित किया जा चुका है तथा SKMCH, Muzaffarpur, ANMCH, Gaya एवं JLNMCH भागलपुर और पूर्णिया के सदर अस्पताल में यह प्रक्रियाधीन है।

राज्य के सभी विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में 564 सीटों एवं यू०जी० पाठ्यक्रमों में 950 सीटों की वृद्धि हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य में इस सत्र से चार फार्मेसी संस्थान यथा नालन्दा, सिवान, रोहतास एवं बांका में डिप्लोमा फार्मेसी की पढ़ाई हेतु फार्मेसी काउँसिल ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त हो गयी है और आगामी सत्र से इन चारों संस्थानों में नामांकन लिया जायेगा। इसी प्रकार राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने हेतु भी फार्मेसी काउँसिल ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त है तथा आगामी सत्र से इस पाठयक्रम में भी नामांकन लिया जायेगा।

**(ख) <u>अतिविशिष्ट अस्पताल (Superspeciality Hospital)</u>**

**इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना** में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड की संख्या 145 से बढ़ाकर 250 करने एवं तद्नुकूल विभिन्न स्तर पर कुल 383 पद सृजित किए गए हैं। इसके नवनिर्मित भवन को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं सहित शीघ्र ही क्रियाशील किया जायेगा।

**महोदय,** सदन को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में **लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना** को विस्तारित करते हुए इस अस्पताल को 400 बेड क्षमता वाले अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में 215.00 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। इस अस्पताल में लगभग 12 करोड़ रू० की लागत से तीस बेड के ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण कार्य लगभग संपन्न हो गया है, जिसे 15 अगस्त, 2021 के पूर्व ही क्रियाशील कर दिया जायेगा।

पटना जिला में **राजेन्द्र नगर स्थित सुपरस्पेशलिटी नेत्र अस्पताल** में 76.04 करोड़ रू0 की लागत से 106 बेड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। इसे भी 15 अगस्त 2021 के पूर्व क्रियाशील कर दिया जायेगा।

पटना में अवस्थित जय प्रभा अस्पताल में **जय प्रभा मेदान्ता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना** का निर्माण जन निजी भागीदारी (PPP) में कराकर दिनांक–18.09.2020 से इस अस्पताल में ओ0पी0डी0 सेवाओं का शुभारंभ हो चुका है। अगस्त माह में सुपर स्पेशियलिटी, इन्डोर और आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होने जा रही है। इस अस्पताल में BPL कार्ड धारकों की सुविधा के लिए 25 प्रतिशत बेड को सी0जी0एच0एस0 दर पर संचालित करने की बाध्यता होगी। इस अस्पताल में चिकित्सा कराने पर सरकारी कर्मचारियों को अन्य सरकारी अस्पताल की भांति करायी गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

**भोजपुर जिला** में 128.96 करोड़ रू0 की लागत से **मानसिक आरोग्यशाला** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

**नालन्दा जिला के रहुई प्रखंड, ग्राम पैठना** में लगभग रु० 404.00 करोड़ की लागत से 100 नामांकन का राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे फरवरी, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 322 नये पदों का सृजन किया गया है।

**(ग) <u>आयुष चिकित्सा पद्धति</u>**

**राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना** में 100 यू०जी० सीट को बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। इस संस्थान में पी०जी० कोर्स में छः विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसे बढ़ाकर आठ विषयों की अनुमति प्राप्त है। राज्य सरकार के अथक प्रयास से **राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय** में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में 30 सीटों पर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020–21 में 38 सीटों पर नामांकन किया जा रहा है।

पटना सिटी स्थित नवाब मंजिल के परिसर में 50 बेड के **एकीकृत आयुष अस्पताल** के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था के संपूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

**(घ) सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2** के तहत् स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में अमूलचूल परिवर्तन के तहत् स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जा रहा है। इस क्रम में **टेली मेडिसीन** सुविधाओं का शुभारम्भ दिनांक–21 फरवरी, 2021 को ई–संजीवनी के माध्यम से हब एवं स्पोक के माध्यम से किया गया। जिसमें 2263 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (स्पोक) को 245 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल (हब) से जोड़ा गया है। अद्यतन इस सुविधा का लाभ 2,43,829 मरीज 2,65,214 कनसलटेशन के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के बाधित रहने की स्थिति में भी मरीजों को सामान्य बिमारियों के उपचार का लाभ प्राप्त हुआ है। इसे और विस्तारित करते हुए राज्य के सभी हिस्सों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इसे आमजन के फोन पर ई–संजीवनी ओ0पी0डी0 के माध्यम से घर बैठे डाक्टर द्वारा टेली कन्सलटेशन की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। उन्हें डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर शुरू की जा रही है।

**(ड.) <u>बाल हृदय योजना</u>**

**पसीने की सियाही से जो लिखते हैं इरादे को**
**उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते।**

**महोदय,**

सदन की अनुमति से मैं बताना चाहुँगा कि हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों की निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना क्रियाशील कर दी गयी है तथा प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन, राजकोट में अबतक कुल 46 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है तथा अगले 10 दिनों में 21 और बच्चों का भी ऑपरेशन हो जाने की संभावना है।

**(च) सदर अस्पताल**

प्रथम चरण में 10 तथा द्वितीय चरण में 12 सदर अस्पतालों को मोडल अस्पतालों के रूप में उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। सभी 36 सदर अस्पतालों में सी0टी0 स्केन मशीनों का अधिष्ठापन कराया जा रहा है, जिसमें 16 जगह इनकी स्थापना की जा चुकी है।

**(छ) अनुमंडलीय अस्पताल**

50–100 बेड के 10 अनुमंडलीय अस्पतालों (यथा–मढौरा, बेनीपट्टी, हवेली खड़गपुर, रक्सौल, सिकरहना, पालीगंज, वीरपुर, बिरौल, त्रिवेणीगंज एवं दानापुर) का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही 2 अनुमंडलीय अस्पतालों यथा– बेलसंड एवं तेघड़ा का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दीदी की रसोई के माध्यम से अंतः वासी रोगियों को सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों में भोजन देने हेतु अगले 5 वर्षो के लिये अनुबंधित किया गया है।

**(ज)** मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष एवंआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को ईलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

**(2) कोविड–19**

**हर दर्द की पहचान होती है**
**खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है**
**वही बदलते हैं रूख हवाओं का**
**जिनके इरादों में जान होती है।**

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी से भारत समेत पूरा विश्व विगत सवा साल से प्रभावित है। भारत में सबसे पहले केरल में दिनांक 30.01.2020 को पहला मामला प्रकाश में आने के बाद से ही बिहार सरकार समय–समय पर इस वैश्विक महामारी के प्रकोप को भांपते हुये प्रयत्नशील रही एवं तदनुसार उपाय भी किये गये।

2. भारत सरकार के निदेश के आलोक में COVID-19 के सम्पुष्ट मरीजों के ईलाज हेतु राज्य में त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधा केन्द्र स्थापित की गयी। हल्के लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु कुल **334** कोविड केयर सेंटर (CCC) की स्थापना की गयी, जिनमें Beds की क्षमता **37792** थी तथा **23556** बेड सभी सुविधाओं सहित उपलब्ध थे। इन केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्स एवं पारा मेडिकल कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी। इस केन्द्र में भर्ती मरीजों हेतु भोजन, पानी, दवाईयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की गयी थी।

3. Moderate लक्षण वाले मरीजों हेतु **200** Dedicated Covid Health Centre (DCHC) की स्थापना की गयी थी, जिनमें कुल **13674** Beds की क्षमता थी तथा सभी सुविधाओं के साथ **11162** Beds कोरोना मरीजों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध थे। इन केन्द्रों पर सभी Beds के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अथवा गैस पाईप के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गयी थी।

4. गंभीर रूप से बीमार मरीजों हेतु **12** चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में Dedicated Covid Hospital (DCH) की व्यवस्था की गयी थी, जिनमें **5024** Beds की क्षमता थी तथा **3992 Beds** सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ उपलब्ध थे। इन Dedicated Covid Hospitals में मरीजों के ईलाज हेतु पर्याप्त संख्या में **ICU Bed** तथा **Ventilators** उपलब्ध कराये गये।

5. राज्य सरकार द्वारा कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज की अनुमति दी गयी, जिनमें कुल **3237** बेडों की व्यवस्था थी। राज्य में स्थापित **6** निजी चिकित्सा महाविद्यालय को Isolation Centre के रूप में चिन्हित कर कुल **720** Beds को कोरोना के मरीजों के ईलाज हेतु आरक्षित किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से डी0आर0डी0ओ0 के द्वारा बिहटा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में तथा मुजफ्फरपुर स्थित पताही हवाई अड्डे परिसर में 500–500 बेड के आई0सी0यू0 एवं वेंटीलेटरयुक्त अस्पतालों का निर्माण किया गया था।

6. COVID Positive पाये गये ऐसे मरीज जो Home Isolation में थे, के स्वास्थ्य के अनुश्रवण आशा, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, टेलीमेडिसीन तथा 104 टॉल फ्री नंम्बर तथा जिलों में स्थापित चिकित्सकीय नियंत्रण कक्ष एवं **हिट ऐप** के माध्यम से कराया गया। Home Isolation के दौरान उन्हें आवश्यक दवाओं, दो मास्क, चिकित्सकीय सलाह पर्ची आदि का एक किट दिया गया।

7. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु राज्य के सभी जिलों में मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु PPEKit, 3 Ply Mask, N95 mask, Sanitizer आदि प्रतिरक्षक समाग्रियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। स्वास्थ्य कर्मियों के

मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा एक महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया।

8. राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी सतत् प्रयास करते हुए कोरोना मरीजों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी गयी तथा जीवन रक्षक दवाईयों तथा ऑक्सीजन की निर्वाध उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।

9. कोविड–19 के रोकथाम के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोविड–19 की जॉच है, क्योंकि जाँच के द्वारा ही कोविड–19 Positive व्यक्ति की पहचान की जा सकती है एवं उन्हं आईसोलेट किया जा सकता है ताकि संक्रमण न फैले। राज्य में वर्तमान में कोविड–19 की जाँच हेतु उपलब्ध सभी माध्यमों यथा–RT-PCR, True Nat, Rapid Antigen Kit आदि के माध्यम से जाँच कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के स्वास्थ्य संस्थानों पर मांग के आधार पर Rapid Antigen Kit के माध्यम से जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य में कोविड–19 की जाँच हेतु निजी क्षेत्रों में भी जाँच करने की अनुमति दी गई है। राज्य में स्थापित 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भी सरकारी खर्च पर निःशुल्क RT-PCR जाँच की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ICMR के मानक के अनुरूप–11 अन्य निजी संस्थानों में भी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर RT-PCR/TrueNat जाँच हेतु अनुमति दी गई है। इसके माध्यम से वर्तमान में राज्य के 17 जिलों में आर0टी0पी0सी0आर0 लैब संचालित हैं।

10. राज्य के शेष 21 जिला अस्पतालों में भी जॉच हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा अगस्त माह तक यह सुविधा सभी जिलों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. बिहार राज्य अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक की आबादी एवं देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह आवश्यक था कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की जाँच की जाए, उन्हें अन्य व्यक्तियों से आईसोलेट किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य का अनुश्रवण किया जाए ताकि संक्रमण के चेन को रोका जा सके। इतनी बड़ी आबादी में संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु आवश्यक संख्या में जाँच का कार्य सिर्फ RT-PCR एंव True-Nat के माध्यम से किया जाना संभव नहीं था। इसलिये रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से भी कोरोना की जॉच की गयी। इसके अतिरिक्त 10 चलन्त आर0टी0पी0सी0आर0 वैन के माध्यम से भी कोरोना की जाँच करायी जा रही है। इन गतिविधयों से बिहार राज्य में COVID-19 संक्रमण को रोकने में काफी सहायता मिली है।

12. कोविड–19 के संबंध में विभिन्न सामग्रियों एवं उपकरण की अधिप्राप्ति बिहार स्वास्थ्य सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में किया गया है। विभिन्न सामग्रियों की अधिप्राप्ति एकबार न करके स्थिति की निरंतर समीक्षा कर, विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं

एवं ICMR तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों के आलोक में चरणवार तरीके से किया गया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कोविड–19 अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को अपने वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है जो सबके लिए सुलभ है।

13. सरकार के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि कोविड संक्रमण के रोकथाम एवं प्रबंधन में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। **दिनांक 28.07.2021 तक** बिहार में कुल **3,68,94,903** सैम्पल की जांच की गई है। **कुल 7,24,673** संक्रमित व्यक्तियों में से **7,14,554** व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार बिहार राज्य का रिकवरी प्रतिशत **98.6** प्रतशित है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी प्रतिशत **97.39** है। बिहार राज्य में अब तक कुल **9,639** व्यक्तियों की कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु हुई है। इस प्रकार बिहार में कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों में मृत्यु का **दर 1.33** प्रतिशत है, जबकि उक्त का राष्ट्रीय प्रतिशत **1.34** है।

**(3) <u>कोविड–19 टीकाकरण</u>** → अन्य वैक्सीन – 10-20 वर्षों में। कोरोना टीका । वर्ष में।

- हम प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का आभार व्यक्त करते हैं कि वर्तमान में 18 वर्ष से उपर के आयु वर्ग को दिया जाने वाला टीका भारत सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है।
- वर्ष 2020 में कोविड 19 वैश्विक महामारी से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देष्य से कोविड 19 का टीकाकरण कराये जाने का निर्णय लेते हुये इसे प्रारम्भ किया गया है। इस टीकाकरण के तहत लाभार्थियों को टीकों की दो खुराक निश्चित अंतराल पर दी जानी है।
- कोविड 19 का टीकाकरण प्रारम्भ किये जाने के पूर्व राज्य में सभी स्तर पर आवश्यक तैयारियाँ की गई। राज्य में NMCH, पटना स्थित राज्य वैक्सिन स्टोर के अतिरिक्त 10 क्षेत्रीय वैक्सिन स्टोर एवं सभी 38 जिलों में जिला वैक्सिन स्टोर स्थापित है। कोविड–19 टीकाकरण हेतु वैक्सिन के समुचित प्रबंधन तथा संग्रहण के लिए राज्य के सभी कार्यरत **679 शीत्–श्रृंखला इकाईयों** का सुदृढ़ीकरण किया गया है।
- कोविड 19 टीकाकरण का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस पूरे कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु भारत सरकार द्वारा CoWIN Portal विकसित किया गया है। लाभान्वितों के पंजीकरण का कार्य इस पोर्टल पर किया जाता है। जिसके आलोक में निर्धारित टीकाकरण की स्थल/तिथि की जानकारी लाभान्वित के मोबाईल फोन पर SMS के माध्यम से प्राप्त होती है। टीकाकरण के पश्चात् डिजिटल रिकार्ड के रूप में प्रथम टीके के बाद औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं दूसरे टीके के बाद अंतिम टीकाकरण प्रमाण–पत्र हेतु CoWIN Portal के माध्यम से लिंक प्राप्त होता है।

- **प्रथम चरण में बिहार के सभी** Health Care Workers (सरकारी एवं निजी सहित) के टीकाकरण का अभियान दिनांक **16 जनवरी 2021 को पटना स्थित इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना** से प्रारम्भ किया गया है। दूसरे खुराक प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 15.02. 2021 से प्रारंभ की गयी थी।

- **द्वितीय चरण में** Front Line Workers (यथाः रक्षा मंत्रालय, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के राजस्व कार्य से संबद्ध पदाधिकारी/कर्मचारी) के पदाधिकारियों एवं कर्मियों काटीकाकरण दिनांक **06 फरवरी 2021 से** प्रारम्भ किया गया है।

- **तृतीय चरण** में 45 वर्ष से उपर के व्यक्तियों तथा चतुर्थ चरण में 18 वर्ष से उपर के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण प्रारम्भ किया गया।

- बिहार की बड़ी आबादी के परिपेक्ष्य में राज्य में त्वरित गति से टीकाकरण का कार्य संपन्न कराने हेतु छः माह छः करोड़ डोज का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु सभी प्रखंडों में टीकाकरण केन्द्र बनाये गये हैं एवं सभी जिलों में सुबह 09:00 बजे से शाम 09:00 बजे तक संचालित केन्द्रों की भी स्थापना की गयी है। पटना जिले में 24x7 अनवरत क्रियाशील तीन टीकाकरण केन्द्र की भी स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त विशेष कर वृद्ध तथा निशक्त व्यक्तियों के लिये ग्रामीन क्षेत्रों में 718 तथा शहरी क्षेत्रों में 121 टीका एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से दूरस्थ एवं दुर्गम ईलाकों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। वर्त्तमान में दिनांक 27.07.2021 तक राज्य में 1 करोड़ 94 लाख 92 हजार 49 व्यक्तियों को प्रथम डोज एवं 36 लाख 24 हजार नौ सौ सत्तर व्यक्तियों को द्वितीय डोज उपलब्ध कराया गया है। अर्थात कुल 2 करोड़ 31 लाख 17 हजार 19 यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 71 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तियों को टीका दिया जा चुका है।

- राज्य के कई शहरों एवं प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है।

**(4) <u>कोरोना के संभावित तीसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढीकरण</u>**

**यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा**
**जमीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा**
**ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी**
**इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत गॉव–गॉव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पॉच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) तथा एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके क्रियान्वयन हेतु 1215 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र), 243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 2060.76 करोड़ रूपये की लागत के आधार पर निविदा प्रक्रियाधीन है।

- **<u>ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था</u>**

ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में बिहार राज्य ऑक्सीजन प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। इसके अंतर्गत दस चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना की जा रही है जो अगस्त 2021 तक स्थापित हो जायेगे। साथ ही राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में तीन सौ लीटर प्रति मिनट की क्षमता का पी0एस0ए0 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लान्ट अधिष्ठापित एवं कार्यरत है। नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी सदर अस्पतालों, सभी अनुमंडलीय अस्पतालों एवं कुछ अन्य अस्पतालों में भी कुल 122 स्थानों पर विभिन्न क्षमता का पी0एस0ए0 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लान्ट का अधिष्ठापन अंतिम चरण में है। इन सभी संस्थानों में सभी बेड पर मेडिकल गैस पाईप लाईन के अधिष्ठापन का कार्य भी द्रुतगति से संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें से वर्तमान में सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है। इन 122 पी0एस0ए0 प्लान्ट में से 62 पी0एम0 केयर्स फंड के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिसमें से 19 प्लान्ट क्रियाशील हो गये हैं और शेष सभी प्लान्ट 15 अगस्त 2021 तक क्रियाशील करने की योजना है।

राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता की अनवरत अनुश्रवण हेतु स्टेट ऑक्सीजन वार रूम की स्थापना पटेल भवन में की गयी है।

महोदय, ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु स्वास्थ्य संस्थानों के लेवल के अनुरूप मानक तय करते हुए प्रत्येक जिला अस्पताल में **60** एवं प्रति अनुमंडलीय अस्पताल में **35** की दर से **डी0 टाईप** ऑक्सीजन सिलेन्डर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र **20** और प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में **10** की दर से तथा प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एल 1) में **02** की दर से **बी0 टाईप** ऑक्सीजन सिलेन्डर तथा ऑक्सीजन फ्लो मीटर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रति जिला अस्पताल **40**, प्रति अनुमंडलीय अस्पताल **25**, प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र **10** और प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में **05** की दर से तथा प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एल 1) में **02** की दर से **ऑक्सीजन कनसनट्रेटर** उपलब्ध कराये गये है।

राज्य के विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 6 हजार 183 ऑक्सीजन कनसनट्रेटर, 10 हजार 924 बी0 टाईप ऑक्सीजन सिलेन्डर, 3 हजार 696 डी0 टाईप ऑक्सीजन सिलेन्डर, 765 बाई पैप मशीन एवं 169 पोरटेबल एक्स–रे मशीन उपलब्ध कराये गये हैं। इन उपकरणों का संधारण एवं प्रबंधन ईक्वीपमेन्ट मेनटेनेंस एवं मैनेजमेन्ट सिस्टम द्वारा किया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार इन उपकरणों का पुनर्आवंटन किया जा सकेगा। राज्य के 36 सदर अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन का अधिष्ठापन किया जा रहा है, जिसमें से 16 स्थलों पर इसका अधिष्ठापन हो चुका है।

- **एम्बुलेंस**

राज्य में सरकार द्वारा पूर्व से संचालित 1137 एम्बुलेंस तथा 59 मोरचुअरी वैन के अतिरिक्त 132 एम्बुलेंस तथा 10 मोरचुअरी वैन उपलब्ध कराया गया है। आमजन की आवश्यकता को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में इलाज हेतु वर्तमान में सभी बिहारवासियों के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क कर दिया गया है, ताकि जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसकी बुकिंग की प्रक्रिया में सुधार लाया गया है, जिसके तहत् टॉल फ्री नं० 102 पर कॉल कर बुकिंग करने के साथ–साथ '102 इमरजेंसी बिहार 'मोबाईल ऐप' के माध्यम से बुकिंग करने की सुविधा भी आरंभ की गई है। मरीजों एवं उनके परिजनों हेतु यह सुविधा भी ऑनलाईन प्रदान की गयी है जिसके माध्यम से वे अपने एम्बुलेंस के लोकेशन के बारे में रियल टाईम जानकारी ले सकें।

इसके उपरान्त एम्बुलेन्स की सुविधा को व्यापक स्तर पर विस्तारित करने हेतु लगभग 1000 एम्बुलेंस के क्रय की योजना है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड हेतु एक अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एडवान्सड लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस का क्रय सम्मिलित है। इसपर लगभग 416 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।

**(5) ईमरजेन्सी कोविड–19 रिस्पोन्स पैकेज द्वितीय चरण** के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से 60:40 राशि के प्रावधान अंतर्गत 8 जिला अस्पतालों में 32 बेड का शिशु चिकित्सा ईकाई तथा 28 जिला अस्पतालों में 42 बेड का शिशु चिकित्सा ईकाई के निर्माण का प्रस्ताव कुल 136.4 करोड़ रूपये की लागत पर प्रस्तावित है, जिसमें 8 एच0डी0यू0 बेड तथा 4 आई0सी0यू0 रहेंगे। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रूपये की लागत से राज्य स्तर पर एक शिशु चिकित्सा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 496 संस्थानों पर 20 बेड का विशेष यूनिट बनाये जाने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य संस्थानों में गहन चिकित्सा ईकाई की स्थापना/विस्तारीकरण के प्रस्ताव में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में कुल 270 अतिरिक्त आई0सी0यू0 बेड एवं जिला अस्पतालों में कुल 300 अतिरिक्त आई0सी0यू0 बेड का प्रावधान किया गया है। साथ ही 100 बेड के 12 एवं 50 बेड के 15 फील्ड अस्पताल के निर्माण तथा इनके संचालन हेतु ऑपरेशनल राशि प्रावधान है। रेफरल परिवहन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त 534 ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स की व्यवस्था का प्रवधान है। स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल ऑक्सीजन

गैस की समुचित व्यवस्था हेतु 30 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट, 23 जिला अस्पतालों एवं 256 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल गैस पाईप लाईन सिस्टम का प्रावधान हैं। डिजीटल हेल्थ रिकार्ड के संधारण हेतु 36 स्वास्थ्य संस्थानों में होस्पीटल मेनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में टेली मेडिसीन हब के निर्माण तथा 380 स्वास्थ्य संस्थानों को स्पोक के रूप में जोड़े जाने का प्रावधान है। कोविड–19 की जॉच को और भी सुलभ बनाने हेतु 2,73,75,000 आर0टी0पी0सी0आर0 किट तथा 5,11,00,000 रैपिड एन्टीजन टेस्ट किट की उपलब्धता का प्रावधान है। इसी क्रम में 27 नये आर0टी0पी0सी0आर0 लैब की स्थापना, 746 लैब टेकनीशियन तथा 38 माईक्रो–बॉयोलॉजिस्ट की व्यवस्था का प्रावधान है। कोविड–19 संक्रमण के उपचार एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रति जिला 1 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। राज्य में कोविड प्रबंधन हेतु अतिरिक्त मानव बल की सेवायें प्राप्त करने हेतु लगभग 56 करोड़ रूपये की योजना बनाई गयी है।

इसी प्रकार आई0टी0 व्यवस्था के सुदृढीकरण जिसमें एच0एम0आई0एस0 (हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम) की स्थापना भी सम्मिलित है, के लिये 5 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों में कोविड–19 के प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण हेतु भी 5 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन सभी प्रस्तावों पर रूपये 1482.34 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें से 889.4 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार एवं 592.94 करोड़ रूपये राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

**(6) जन–जागरूकता** के सभी माध्यमों यथा ईलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया के अतिरिक्त पोस्टर, बैनर, माईकिंग, होडिंग इत्यादि के माध्यम से आम नागरिक को कोरोना से बचाव हेतु नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क के प्रयोग तथा सामाजिक दूरी का संवाद पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।

**(7) <u>मानव संसाधन</u>**

**मंजिलें क्या है रास्ता क्या है**

**हौसला है तो फिर फासला क्या है।**

नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कुल 171 चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है तथा 163 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति अंतिम चरण में है। वर्तमान में जी0एन0एम0 के 4,102 पदों पर नियुक्ति हेतु कॉउन्सिंग की जा रही है, जो 15 अगस्त 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। सभी जिलों में आई0सी0यू0 एवं वेन्टीलेटर के सुचारू संचालन हेतु सभी जिलों से कुल 78 चिकित्सकों तथा 152 नर्सो को सात दिवसीय हैन्डस्ऑन प्रशिक्षण एम्स पटना के माध्यम से दिया गया है।

राज्य के शेष सभी जिला अस्पतालों में आर0टी0पी0सी0आर0 मशीनों के संचालन हेतु 17 माईक्रोबॉयोलॉजिस्ट की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है जो 10 अगस्त 2021 के पूर्व संपन्न हो जायेगा।

**किसी भी राज्य के विकास में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की भूमिका अहम होती है। इस कड़ी को और सुदृढ. करने हेतु :–**

- **राज्य के पटना में बच्चों के सभी बीमारियों के ईलाज हेतु सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जायेगी।**
- **राज्य में सभी ए0एन0एम0 एवं आशा कर्मियों को विभिन्न प्रकार के उपकरण युक्त किट प्रदान किया जायेगा।**
- **राज्य की सभी आशा कर्मियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना है।**
- **राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जगह–जगह फैले वर्षो अनुपयुक्त पुराने धातु के कचरे के सुव्यवस्थित निस्तारन हेतु मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम0एस0टी0सी0) के साथ एम0ओ0यु0 किया गया है, जिसकी शुरूआत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थानों से की जा रही है।**

- **राज्य में नयी पहल के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के साथ 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी निर्माण किये जाने हेतु कुल 2060.76 करोड़ रूपये के लागत के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी है।**
- **ईमरजेन्सी कोविड रिस्पोन्स पैकेज के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 1482.34 करोड़ रूपये की योजना है।**
- **राज्य में रेफरल परिवहन की व्यवस्था में बेहतरी हेतु 1000 नये एम्बुलेंस के क्रय पर लगभग 416 करोड़ रूपये की योजना है।**
- **इस प्रकार कुल राशि 3959.10 करोड़ रूपये जो अगले दो वर्ष के अंतर्गत व्यय होने का प्रस्ताव है। इसे यदि प्रति विधान सभा औसत निकाला जाये तो यह राशि लगभग 16.29 करोड़ रूपये आती है।**

**महोदय,**

मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए
होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए
बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से
हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए।

**महोदय, आपकी अनुमति से** अब मैं, वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या–20 के अनुसार योजना मद में 2231.68 करोड़ रूपये तथा गैर योजना मद में 1442.31 करोड़ रूपये अर्थात कुल 3673 करोड़ 99 लाखा 40 हजार की मांग स्वास्थ्य विभाग का रुपये 36,73,99,40,000 **(छत्तीस सौ तिहत्तर करोड़ निनानवें लाख चालीस हजार रूपये)** की अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**********